# चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 26 जून– 02 जुलाई 2017 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

# जो नगाओं को दिया वही कश्मीरियों को दीजिए

**नगा समझौते का बहु-प्रचार कर केंद्र की भाजपा सरकार खुद ही कई सवालों में घिर गई है. आम नागरिकों को भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि नगा समझौते के लिए अति-उत्साहित पहल करने वाली केंद्र सरकार कश्मीरियों की वाजिब मांगें भी सुनने को तैयार क्यों नहीं होती? अब तो 'चौथी दुनिया' ने 05 जून से 11 जून के अंक में यह उजागर कर दिया है कि नगा समझौते में केंद्र सरकार ने कहां-कहां और किन-किन शर्तों पर एनएससीएन प्रमुख थुइंगलेंग मुइवा के आगे घुटने टेके. केंद्र सरकार नगालैंड के एक आतंकी संगठन से समझौता कर लेती है, लेकिन कश्मीर में अलगाववादी संगठन से बात भी नहीं करना चाहती. यह दोतरफा व्यवहार क्यों? कश्मीर के अलगाववादी राष्ट्रवादी नहीं, तो क्या नगालैंड के उग्रवादी राष्ट्रवादी हैं? इन सवालों का जवाब केंद्र को देना ही होगा, आज नहीं तो कल...**

हारून रेशी

अगर नगा विवाद खत्म करने के लिए एक संगठन की शर्तों पर समझौता हो सकता है, तो कश्मीर के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अगस्त 2015 को केंद्र सरकार ने मुख्य वार्ताकार आरएन रवि की मध्यस्थता में आतंकी संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड के प्रमुख थुइंगलेंग मुइवा के साथ एकतरफा समझौता कर लिया. जबकि जुलाई 2016 में जब कश्मीर घाटी में हिंसा भड़की थी तभी वार्ताकार दिलीप पडगांवकर ने कहा था कि यदि सरकार ने वार्ताकारों की सिफारिशों पर अमल किया होता, तो कश्मीर को ये दिन नहीं देखने पड़ते. साल 2010 में ही जब घाटी की स्थिति तनावपूर्ण हुई और सेना के हाथों कई बच्चों समेत 120 लोग मारे गए थे, तब केंद्र सरकार ने स्थिति की समीक्षा के लिए और कश्मीर का हल तलाशने के लिए एक टीम गठित की थी. इस टीम में वरिष्ठ पत्रकार (अब मरहूम) दिलीप पडगांवकर, शिक्षाविद् प्रोफेसर राधा कुमारी और पूर्व सूचना आयुक्त एमएम अंसारी आदि शामिल थे. इस टीम ने दो वर्षों में कई बार जम्मू-कश्मीर का दौरा किया और अलग-अलग विचारधारा से सम्बन्धित छोटे-बड़े पांच हजार लोगों से मुलाकात की थी. इसके बाद टीम ने अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी. इस रिपोर्ट में कश्मीर मसले को हल करने और यहां के हालात को ठीक करने की सिफारिशें थीं. ये रिपोर्ट इस समय गृह मंत्रालय में किसी ताक पर धूल चाट रही है. विश्लेषक हैरान हैं कि कश्मीर में हालात इस कदर खराब होने के बावजूद, मोदी सरकार पूर्व सरकारी व गैर सरकारी वार्ताकारों की रिपोर्ट्स के अनुसार कोई कदम क्यों नहीं उठाती. या फिर यहां वार्ता का सिलसिला क्यों नहीं शुरू करती. कुछ विश्लेषकों का कहना है कि अगर मोदी सरकार नगा विवाद खत्म करने के लिए एक गैर मामूली समझौता कर सकती है, जिसमें बृहत्तर नगालैंड के लिए अलग संविधान, अलग न्यायपालिका, अलग झंडा, अलग मुद्रा, अलग पासपोर्ट यहां तक कि अलग सेना जैसी अभूतपूर्व मांगों को स्वीकार किया गया है, तो फिर कश्मीर के बारे में दोहरा मापदंड क्यों?

**कश्मीर में सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए या गैर सरकारी वार्ताकारों की सूची लम्बी है. इन्होंने 1990 से अब तक समय-समय पर यहां के हालात की समीक्षा करने के बाद किसी सकारात्मक पहल के लिए केंद्र सरकार से विभिन्न सिफारिशें पेश कीं. इन वार्ताकारों में केसी पंत से लेकर एन एन वोहरा (जम्मू-कश्मीर के मौजूदा गवर्नर) और राम जेठमलानी तक कई प्रसिद्ध नाम शामिल हैं. इसके अतिरिक्त कई अलग-अलग विचारधारा के लोगों ने अपने स्तर से भी कश्मीर की स्थिति को समझकर, इसके समाधान के लिए सरकार से सिफारिश की.**

कश्मीर देश का एकमात्र प्रदेश है, जहां देश की आजादी के 17 साल बाद यानि 1964 तक अपना प्रधानमंत्री था. यहां गवर्नर नहीं बल्कि सदर-ए-रियासत हुआ करता था. जम्मू-कश्मीर के पास आज भी अपना संविधान है. जम्मू-कश्मीर एकमात्र प्रदेश है, जिसका आज भी अपना झंडा है. कुछ दशक पहले तक जम्मू-कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का कोई हस्तक्षेप नहीं था. यहां भाजपा और कांग्रेस जैसी

राष्ट्रीय पार्टियां अपनी यूनीट तक नहीं खोल सकती थीं. ये एकमात्र ऐसा प्रदेश है, जहां आज भी कोई भारतीय नागरिक जमीन या कोई संपत्ति नहीं खरीद सकता है. ये एकमात्र ऐसा प्रदेश है, जहां के लोगों को आज भी दोहरी नागरिकता, यानि जम्मू-कश्मीर की नागरिकता और भारतीय नागरिकता हासिल है. ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं, जिनसे पता चलता है कि जम्मू कश्मीर भारत के अन्य राज्यों से अलग है. हकीकत ये है कि इस प्रदेश ने भारत के साथ विलय किया है. ये महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश की तरह आम प्रदेश नहीं है. फिर क्या कारण है कि केंद्र सरकार इस रियासत के हालात को ठीक करने के लिए गैर मामूली कदम नहीं उठाती. जब से ये खुलासा हुआ है कि मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट का विवाद खत्म करने के लिए परंपरा से हट कर एक गैर मामूली समझौता किया है, देश भर में कुछ गंभीर सोच रखने वाले राजनीतिक विश्लेषकों ने ये सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि कश्मीर में इस तरह का समझौता करने में क्या परेशानी है?

कश्मीर में सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए या गैर सरकारी वार्ताकारों की सूची लम्बी है. इन्होंने 1990 से अब तक समय-समय पर यहां के हालात की समीक्षा करने के बाद किसी सकारात्मक पहल के लिए केंद्र सरकार से विभिन्न सिफारिशें पेश कीं. इन वार्ताकारों में केसी पंत से लेकर एन एन वोहरा (जम्मू-कश्मीर के मौजूदा गवर्नर) और राम जेठमलानी तक कई प्रसिद्ध नाम शामिल हैं. इसके अतिरिक्त कई अलग-अलग विचारधारा के लोगों ने अपने स्तर से भी कश्मीर की स्थिति को समझकर, इसके समाधान के लिए सरकार से सिफारिश की. ऐसे लोगों में वजाहत हबीबुल्ला, कुलदीप नैयर, वलराज पुरी, एमजे अकबर, शांति भूषण और वीके ग्रोवर जैसे लोग शामिल हैं. इतना ही नहीं, 2007 में यूपीए सरकार ने कश्मीर में पांच वर्किंग ग्रुप बनाए थे, जिनमें एक ग्रुप जस्टिस सगीर की अध्यक्षता में बनाया गया था. इस ग्रुप को अपने रिपोर्ट्स और सिफारिशों के जरिए प्रदेश और केंद्र के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. जस्टिस सगीर ने अपनी सिफारिशें पेश कीं, लेकिन उन्हें भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया. पिछले एक साल के दौरान यशवंत सिन्हा, मणिशंकर अय्यर और कमल मोरारका जैसी शख्सियतों के नेतृत्व में यहां कई गैर सरकारी प्रतिनिधिमंडल आए. इन्होंने यहां के हालात की समीक्षा करने और लोगों से बातचीत करने के बाद केंद्र को कश्मीरियों से वार्तालाप स्थापित करने की सलाह दी. विनोद शर्मा, संतोष भारतीय और सीमा मुस्तफा जैसे पत्रकारों ने भी पिछले एक साल के दौरान कई बार कश्मीर के दौरे किए. यहां के हालात को इन्होंने अपने लेखों में ईमानदारी के साथ बयां किया और भारत सरकार को कश्मीर में ताकत का इस्तेमाल बंद करने की सलाह दी. लेकिन सरकार ने इनमें से किसी भी सलाह को गौर करने लायक नहीं समझा. नतीजतन हर गुजरने वाले दिन के साथ कश्मीर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं.

(शेष पृष्ठ 2 पर)


3 बेजान क़ानूनों के सहारे बेज़ुबान

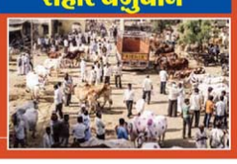

4 ग़लतियों से सीख रही है भाजपा

5 दफ़न हो रहे इंसान पल्ला झाड़त साहेबान

6 देश के किसान क्यों निराश हैं

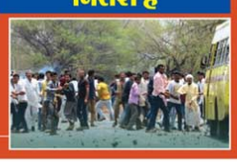

# जो निगाहों को दिया वही कश्मीरियों को दीजिए

पृष्ठ 1 का शेष

## कश्मीर के हालात मे तब्दीली कैसे आएगी

गत एक वर्ष से हिंसक हालात के शिकार कश्मीर घाटी में इन दिनों हर शख्स की जुबान पर यही सवाल है कि यहां अब क्या होने वाला है? दरअसल, लोग अभी तक गृहमंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान का अर्थ तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्होंने कश्मीर के हालात के बारे में इस साल 11 अप्रैल को दिया था. गृहमंत्री ने आश्वासन दिया था कि कश्मीर एक वर्ष के अंदर बदल जाएगा. उन्होंने अपने बयान को इन शब्दों में स्पष्ट किया, 'इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे, लेकिन तब्दीली (कश्मीर के हालात में) जरूर आएगी. इस बात में कोई शक नहीं कि एक साल के अंदर-अंदर कश्मीर में तब्दीली देखने को मिलेगी.' अगर यह बयान भाजपा के किसी आम नेता ने दिया होता, तो शायद इसे अंधेरे में फेंका हुआ तीर समझकर नजरअंदाज किया जा सकता था. लेकिन यह बयान देश के गृहमंत्री का है. गृहमंत्री ने यह बयान वास्तव में किसी सोची समझी रणनीति के तहत ही दिया होगा. कश्मीर के हालात पर गहरी नजर रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक यह समझ नहीं पा रहे कि केवल एक वर्ष के अंदर (दो महीने निकल गए) हालात कैसे ठीक किए जा सकते हैं. केंद्र सरकार हुर्रियत के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है. आतंकी संगठनों के साथ बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता. प्रदर्शनों पर काबू पाने और युवाओं का आक्रोश कम करने के लिए जमीनी स्तर पर कोई कदम नहीं उठाया गया है. फिर हालात एक वर्ष के अंदर कैसे ठीक हो सकते हैं. यह बड़ा अहम सवाल है.

कश्मीर घाटी के राजनीतिक विश्लेषक मोदी सरकार की मौजूदा कश्मीर नीति और सेना प्रमुख से लेकर अमित शाह तक के बयानों की रौशनी में एक अलग तरह की स्थिति बनती देख रहे हैं. उनके अनुसार, नई दिल्ली कश्मीर में सभी मिलिटेंट्स को खत्म करने, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बेतहाशा ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें खामोश करने और हुर्रियत नेताओं की जनता में साख खराब करने की कोशिश कर सकती है. उनकी कोशिश रहेगी कि यहां कब्रिस्तान जैसी खामोशी कायम करके इसे शांति का नाम दिया जा सके. प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने एक बयान के जरिए सेना को निर्देश दिया कि कश्मीर में मौजूद मिलिटेंट्स को दो महीने के अंदर-अंदर खत्म किया जाए. हालांकि नई दिल्ली की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रधानमंत्री के बयान से पूर्व श्रीनगर में सेना की उच्चस्तरीय बैठक में दक्षिणी कश्मीर के बारह मिलिटेंट कमांडरों की लिस्ट को मंजूरी दे दी गई है. इन बारह मिलिटेंट कमांडरों में से लश्कर के 6, हिज्ब के 5 और जैश मोहम्मद का 1 कमांडर शामिल है. स्थानीय मीडिया ने इन मिलिटेंट कमांडरों की सूची भी प्रकाशित की है. दूसरी तरफ, सेना प्रमुख पहले ही वार्निंग दे चुके हैं कि फौज और

मिलिटेंट्स के बीच झड़पों के दौरान मिलिटेंट्स को भागने का अवसर देने के लिए पथराव करने वाले युवाओं से सख्ती से निपटा जाएगा. इस समय हुर्रियत नेताओं पर आरोप लगाया जा रहा है कि वे पाकिस्तान से सैकड़ों करोड़ रुपए हासिल करके घाटी में हालात खराब करवा रहे हैं. लेकिन अभी तक सरकार इस सिलसिले में कोई ठोस सबूत या दलील पेश करने में असफल साबित हुई है. सोलह मई को इंडिया टुडे ने एक सनसनीखेज वीडियो जारी करते हुए कश्मीर में हवाला स्कैंडल का पर्दाफाश करने का दावा किया. वीडियो में तीन हुर्रियत नेताओं नईम अहमद खान, फारूख अहमद डार और गाजी बाबा को ये स्वीकार करते हुए दिखाया गया कि कश्मीर में हालात खराब करने के लिए पाकिस्तान से सैकड़ों करोड़ रुपए की राशि हुर्रियत नेताओं को मिलती है.

## मीडिया ताकतवर या सुरक्षा एजेंसियां

एक आम राय थी कि इस खुलासे के बाद सुरक्षा और जांच एजेंसियां हरकत में आ जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. दो सप्ताह बाद यानि एक जून को नेशनल इनवेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) की 50 सदस्यीय कमिटी कश्मीर आई. टीम का नेतृत्व एक एडिशनल डायरेक्टर रैंक के ऑफिसर कर रहे थे. टीम में एक डिप्टी इंस्पेक्टर, दो एसपी और दस डीएसपी शामिल थे. यहां पहुंचने के दो दिन बाद यानी 3 जून को एनआईए की टीम ने विभिन्न व्यापारियों, हुर्रियत नेताओं और पूंजीपतियों के घरों पर छापे मारने का सिलसिला प्रारंभ किया. तीन जून को एनआईए की 10 टीमों ने कुल 18 स्थानों पर छापे मारे. दूसरे दिन, यानि चार जून को अन्य सात स्थानों पर छापे मारे गए. इसके अलावा एनआईए ने दिल्ली और हरियाणा के नौ स्थानों पर भी छापे मारे. दिल्ली में वे छापे ग्रेटर कैलाश, पीतमपुरा और बल्लीमरान में कथित तौर पर हवाला डीलरों के घरों या दफ्तरों पर मारे गए. जम्मू शहर के गैर मुस्लिम व्यापारी के घर पर भी छापा मारा गया. कुल 34 जगहों पर छापे मारे गए.

हैरानी की बात ये है कि इतने बड़े पैमाने पर की गई कार्रवाई के बाद खुद एनआईए की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि इन छापों के दौरान केवल एक करोड़ 15 लाख रुपए नकद, सोने के 85 सिक्के और 40 लाख रुपए के जेवर जब्त किए गए. उल्लेखनीय है कि इन सभी चीजों को केवल एक जगह से नहीं, बल्कि विभिन्न घरों से बरामद किया गया था. विश्लेषकों का कहना है कि एनआईए ने 33 विभिन्न जगहों पर की गई छापेमारी में इतनी मामूली राशि और कुछ लाख रुपए के जेवर बरामद होने की बात कहकर, खुद ही इन आरोपों को संदेहास्पद बना दिया है कि हवाला के द्वारा कश्मीर में हजारों या सैकड़ों करोड़ रुपए लाए जा रहे हैं. विभिन्न जगहों पर जब्त की गई इस मामूली राशि के बल पर कोर्ट में कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता है. अगर किसी पूंजीपति या व्यापारी के घर से चंद लाख रुपए जब्त किए भी जाते हैं, तो उस पर अधिक से अधिक चंद लाख रुपए ब्लैकमनी रखने का आरोप लगाया जा सकता है. एनआईए ने छापों के दौरान कई लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं. उल्लेखनीय है कि जिन पूंजीपतियों या व्यापारियों के यहां छापे मारे गए हैं, उनके पास बाहर के व्यापार का सालाना हजारों करोड़ रुपए का व्हाईट ट्रांजेक्शन है. ये भी गौर करने वाली बात है कि एनआईए ने इस जांच के लिए एक ओपन एफआईआर दर्ज कर लिया है. यानि किसी भी व्यक्ति को आरोपी नहीं बनाया गया है. इन तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली के जिन न्यूज चैनलों पर कश्मीर में हवाला स्कैंडल बेनकाब हो जाने के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, उनका कोई ठोस सबूत अभी तक सामने नहीं आया है. एनआईए ने विभिन्न घरों से जो कुछ भी जब्त किया है, संभव है कि वो सब अदालत में, जिनका है उनको वापस करना पड़े. यहां ये उल्लेखनीय है कि 2002 में इनकम टैक्स विभाग ने घाटी में बड़े पैमाने पर छापे मारे थे. तब भी कई हुर्रियत नेताओं के घरों से 'अहम दस्तावेज' बरामद करने के दावे किए गए थे. दिल्ली के मीडिया वालों ने बवाल मचाते हुए ये दिखाने की कोशिश की थी कि बहुत बड़ा स्कैंडल बेनकाब हुआ है. लेकिन कुछ दिनों बाद ही खुद इनकम टैक्स विभाग ने वो केस बंद कर दिया. संभव है कि आने वाले चंद सप्ताहों में एनआईए खुद ही उस एफआईआर को खत्म करेगी, जिसके आधार पर इतने बड़े पैमाने पर छापे मारे गए हैं और मीडिया ने इतना बवाल मचा रखा है. देश के गंभीर विश्लेषक इस बात पर हैरान हैं कि अगर सरकार का ये दावा सही है कि कश्मीर में हालात खराब करने के लिए पाकिस्तान से सैकड़ों करोड़ रुपए यहां भेजे जा रहे हैं, तो क्या कारण है कि प्रदेश और केंद्र की सरकार इतने वर्षों में एक ठोस सबूत भी नहीं पेश कर सकी. क्या कारण है कि सरकार की जांच और सुरक्षा एजेंसियां आज तक ये पता लगाने में असफल रही हैं कि इतनी बड़ी राशि कहां से और किन लोगों के द्वारा यहां पहुंचाई जा रही है. इंडिया टुडे की तरफ से स्टींग ऑपरेशन के बाद ही एनआईए हरकत में क्यों आई? क्या सरकार ऐसे मामले में मीडिया पर निर्भर है? गत एक वर्ष से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पथराव करने वालों को पैसा मिलता है. अगर ये सही है, तो जाहिर है इसके पीछे बाकायदा एक नेटवर्क होगा, जो घाटी के कोने-कोने तक पैसा पहुंचाने का काम करता होगा. उस नेटवर्क के साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़े होंगे. तो फिर सरकार की एजेंसियां यहां क्या कर रही हैं. दो ही बातें हो सकती हैं कि या तो सरकार और उसकी एजेंसियां नकारा हैं, जो अब तक कुछ पता नहीं लगा सकीं और न कुछ साबित कर सकीं या ये हो सकता है कि इस तरह के सारे आरोप निराधार और झूठ पर आधारित हैं. जहां तक आम कश्मीरियों का ताल्लुक है, वे यही समझते हैं कि सरकार इस

> हैरानी की बात ये है कि इतने बड़े पैमाने पर की गई कार्रवाई के बाद खुद एनआईए की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि इन छापों के दौरान केवल एक करोड़ 15 लाख रुपए नकद, सोने के 85 सिक्के और 40 लाख रुपए के जेवर जब्त किए गए. उल्लेखनीय है कि इन सभी चीजों को केवल एक जगह से नहीं, बल्कि विभिन्न घरों से बरामद किया गया था. विश्लेषकों का कहना है कि एनआईए ने 33 विभिन्न जगहों पर की गई छापेमारी में इतनी मामूली राशि और कुछ लाख रुपए के जेवर बरामद होने की बात कहकर, खुद ही इन आरोपों को संदेहास्पद बना दिया है कि हवाला के द्वारा कश्मीर में हजारों या सैकड़ों करोड़ रुपए लाए जा रहे हैं.

तरह के झूठे आरोप लगाकर कश्मीरियों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है. पिछले 9 जून को घाटी में हुर्रियत के आह्वान पर व्यापक हड़ताल हुई. हुर्रियत के कुछ नेताओं ने श्रीनगर में प्रदर्शन का आह्वान किया था और उसे असफल बनाने के लिए सरकार को शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा. साफ जाहिर है कि एनआईए के छापों और दिल्ली के न्यूज चैनलों की तरफ से चरित्र हनन के अभियान के बावजूद हुर्रियत का आम लोगों में मान सम्मान है. वे वो सारे तथ्य हैं, जिन्हें दिल्ली का मीडिया छुपा रहा है. 'चौथी दुनिया' ने पिछले एक वर्ष से कश्मीर के वास्तविक हालात को ईमानदारी के साथ अपने पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश की है.

## मिलिटेंट्स के साथ जनता की हमदर्दी क्यों?

जहां तक कश्मीर में मिलिटेंसी का सवाल है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर घाटी, खासतौर से दक्षिणी कश्मीर में मिलिटेंसी का घेराव बढ़ रहा है. हर गुजरने वाले दिन के साथ इसका दायरा बढ़ता जा रहा है. सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि दक्षिणी कश्मीर में इस वक्त 300 मिलिटेंट्स सक्रिय हैं, लेकिन हमारे सूत्र के अनुसार ये संख्या इससे कहीं ज्यादा है. पुलिस खुद इस बात को स्वीकार कर रही है कि गत तीन वर्ष के विरोध-प्रदर्शन के बाद दर्जनों युवा मिलिटेंट्स के साथ जुड़ गए हैं. स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दक्षिणी कश्मीर में गत एक वर्ष के दौरान युवाओं ने सुरक्षा बलों और पुलिस से 60 से ज्यादा राइफलें छीन लीं. सुरक्षा बलों से बंदूकें छीनने की घटनाएं इतने बड़े पैमाने पर पहले कभी देखने को नहीं मिली हैं. इतना ही नहीं, विश्वसनीय सूत्रों ने 'चौथी दुनिया' को बताया कि कश्मीर में मिलिटेंट्स के खिलाफ सेना और पुलिस की असफलता का एक बुनियादी कारण आमलोगों का मिलिटेंट्स से हमदर्दी रखना है. मिलिटेंट्स की बस्तियों में तलाश करना फौज के लिए कोई आसान काम नहीं है. उल्लेखनीय है कि 1990 में घाटी में सशस्त्र आंदोलन के बाद यहां जनता ने बड़े पैमाने पर मिलिटेंट्स का साथ दिया था. हालांकि कुछ सालों बाद मिलिटेंट्स से लोगों की ये हमदर्दी कम होनी शुरू हो गई थी. लेकिन गत एक वर्ष के हालात और घटनाओं को देखें, तो पता चलता है कि मिलिटेंट्स को फिर से जनता का समर्थन मिल रहा है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब अगर कोई मिलिटेंट मारा जाता है, तो उसके नमाज-ए-जनाजा में लोगों की शिरकत को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है. गत एक-डेढ़ साल से यहां मारे जाने वाले मिलिटेंट्स के जनाजे में हजारों लोगों की शिरकत देखने को मिल रही है. ऐसे मौके पर युवाओं में काफी जोश-ओ-खरोश देखने को मिलता है.

गत एक वर्ष से दिल्ली के कुछ टीवी चैनल लगातार ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि कश्मीर में पत्थर फेंकने वालों को पैसे दिए जाते हैं. लेकिन अब घाटी में जगह-जगह स्कूली छात्र-छात्राओं को पथराव करते हुए देखा जा सकता है. इसकी शुरुआत लगभग दो महीने पहले हुई. 15 अप्रैल को सेना ने दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा डिग्री कॉलेज में प्रवेश किया था और कथित तौर पर यहां छात्रों के साथ मारपीट की थी. कॉलेज के प्रिंसिपल ने स्थानीय मीडिया को बताया था कि उन्होंने फौज को कॉलेज परिसर में दाखिल होने से मना किया था, लेकिन उनकी एक न सुनी गई. सरकार ने इस घटना की जांच का आदेश दिया था. लेकिन दूसरी सैकड़ों घटनाओं की जांच की तरह इस घटना की जांच का आदेश भी एक धोखा ही साबित हुआ. आज तक किसी को ये पता नहीं चला कि सेना, प्रिंसिपल और प्रशासन की अनुमति के बगैर कॉलेज परिसर में दाखिल क्यों हुई थी और उसे वहां क्या मिला. लेकिन इस एक घटना के कारण वादी में छात्र-छात्राओं के प्रदर्शन और पथराव का सिलसिला शुरू हो गया. पिछले 25 वर्ष में ऐसा पहली बार हो रहा है कि स्कूल ड्रेस पहने लड़के-लड़कियां सड़कों पर उतरकर सेना पर पथराव कर रहे हैं. छात्र-छात्राओं के हिंसात्मक प्रदर्शन को विदेशी मीडिया भी खुब दिखा रहा है.

कश्मीर में हालात खराब होने का ताल्लुक केवल मिलिटेंसी और पथराव की घटनाओं से ही नहीं जुड़ा है. लाईन ऑफ कंट्रोल पर आए दिन भारत-पाक फौज के बीच गोलीबारी के कारण सीमा पर रहने वाले लोगों की जिंदगी दुश्वार हो गई है. राजौरी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में पिछले कुछ सप्ताह के दौरान पाकिस्तानी गोलाबारी से एक लड़की समेत तीन लोग मारे जा चुके हैं. यहां गोलाबारी से बचने के लिए लगभग 550 परिवारों को प्रवास करने के लिए मजबूर होना पड़ा है. ऐसे परिवारों के 2000 से ज्यादा लोगों को प्रशासन ने पांच विभिन्न कैंपों में पनाह दे रखी है. लाइन ऑफ कंट्रोल पर केवल गोलाबारी ही एक मसला नहीं है, बल्कि यहां हर दूसरे दिन मिलिटेंट्स और फौज के बीच की झड़पें आम बात बन चुकी हैं. इन खबरों को मीडिया द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है. लेकिन कश्मीर के वास्तविक हालात का इस तरह की झड़पों से काफी गहरा सम्बंध है.

## कश्मीर को जीतने के लिए चाहिए मोहब्बत या ताकत

सरकार ने एक महीने पहले से घाटी में पाकिस्तानी न्यूज चैनलों पर पाबंदी लगा रखी है. इंटरनेट पर आए दिन बैन लगाया जा रहा है. लेकिन इसके बावजूद शांति और कानून का राज दूर-दूर तक नजर नहीं आता. रोजाना घाटी के किसी न किसी क्षेत्र में सेना और मिलिटेंट्स में झड़पें हो जाती हैं. रोजाना किसी न किसी इलाके में नौजवान हिंसात्मक प्रदर्शन और पथराव करते नजर आते हैं और रोजाना सीमा पर गोलीबारी या घुसपैठ की कोई न कोई घटना होती है. कुल मिलाकर, कश्मीर घाटी की मौजूदा स्थिति का आकलन करना हो, तो कहा जा सकता है कि यहां हर गुजरने वाले दिन के साथ मिलिटेंसी बढ़ रही है. प्रदर्शन और पथराव एक नियमित दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं और सीमा पर तनाव है. इस स्थिति के बावजूद, अगर गृहमंत्री भरोसे के साथ कह रहे हैं कि एक वर्ष के अंदर कश्मीर के हालात बदल जाएंगे, तो यकीनन हर किसी के मन में ये सवाल पैदा होगा कि कैसे?

एक राय ये भी है कि सरकार कश्मीर में मिलिटेंसी और प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए बहुत ज्यादा ताकत का प्रयोग करने के बारे में सोच रही है. अगर ऐसा हुआ, तो कहा जा सकता है कि आने वाले चंद महीनों में कश्मीर में हिंसा और तेज हो जाएगी. सेना और पुलिस की तरफ से बहुत ज्यादा मौतें, बहुत ज्यादा जख्म, बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां और बहुत हिंसा देखने को मिल सकती है. लेकिन एक सवाल सबके मन में आ रहा है कि क्या इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाल के दिनों में जो गंभीर सोच वाले लोग कश्मीर घाटी के दौरे पर आए हैं, उनमें यशवंत सिन्हा, मणिशंकर अय्यर और कमल मोरारका शामिल हैं. इन लोगों के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने यहां आम लोगों से लेकर बड़े-बड़े नेताओं से मुलाकात की और स्थिति की गहराई समझने की कोशिश की. दिलचस्प बात ये है कि वापस जाने के बाद इन सबने भारत सरकार को मशवरा दिया कि कश्मीर को ताकत की जुबान की जगह मोहब्बत की जुबान की जरूरत है. इन लोगों ने भारत सरकार को कश्मीर मुद्दे पर तुरंत बातचीत का सिलसिला शुरू करने की सलाह दी. संतोष भारतीय, विनोद शर्मा, सीमा मुस्तफा जैसे पत्रकारों ने पिछले एक साल के दौरान कश्मीर घाटी के कई दौरे किए और यहां की स्थिति का जायजा लिया. इन्होंने अपने लेखों के जरिए भारत सरकार को सलाह दी कि कश्मीर समस्या को ताकत की बजाय वार्ता के जरिए हल किया जाय. लेकिन सच तो ये है कि मोदी सरकार कश्मीर को लेकर कोई नरम रवैया अख्तियार करने के मूड में नहीं है. कुछ विश्लेषकों के अनुसार, इसका कारण ये है कि कश्मीर के खिलाफ सख्त रवैया रखने से भाजपा को देश भर में राजनीतिक लाभ हो रहा है. अगर ये सच है, तो यकीन के साथ कहा जा सकता है कि मोदी सरकार की मौजूदा कश्मीर नीति में कोई तब्दीली नहीं आने वाली है. एक साल के अंदर-अंदर हालात बदलने की बात कहकर गृहमंत्री ने शायद यही संकेत दिया है कि यहां मुख्तलिफ आवाजों को दबाने के लिए ताकत का जबरदस्त इस्तेमाल किया जाएगा. यानि कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ महीनों के दौरान कश्मीर के हालात और खराब होने की संभावना है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 09 अंक 17
26 जून- 02 जुलाई 2017

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-65500786
+91-8451050786
+91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

> “गौधन पर सियासत चरम पर है. पशु बिक्री पर केंद्र सरकार की नई अधिसूचना आते ही कई राज्य सरकारों ने आस्तीनें चढ़ा ली हैं. अब सरकार बैक फुट पर है और अधिसूचना में संशोधन के लिए तैयार है. इन बेजान क़ानूनों की आड़ में बेज़ुबान पशुओं व पशुपालकों की फरियाद कहीं दबकर रह गई है.”

# बेजान क़ानूनों के सहारे बेज़ुबान

चंदन राय

राजस्थान के बाड़मेर जिले में 11 जून को तमिलनाडु के कुछ पशुपालन अधिकारियों को 50 गौरक्षकों ने घेर लिया. तमिलनाडु के ये अधिकारी जैसलमेर से थापरकर नस्ल की गायों को खरीदकर बेहतर ब्रीडिंग के लिए ले जा रहे थे. 5 ट्रकों में 50 गाएं व 30 बछड़े लदे थे. ट्रकों पर बड़े-बड़े अक्षरों में स्पष्ट लिखा था ऑन ड्यूटी, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु. सभी जरूरी कागजात और परमिशन लेटर दिखाए गए, पर गौरक्षकों को भला इसकी परवाह कहां थी. उन्होंने अधिकारियों को जमकर पीटा और ट्रकों में आग लगा दी. पुलिस के आने के बाद किसी तरह अधिकारी जान बचाकर भागे. गौरक्षकों के हमलों को अगर गौर से देखें तो उनमें एक स्पष्ट पैटर्न नजर आता है. अक्सर दलित और एक खास समुदाय के लोग ही उनके निशाने पर होते हैं, अपवादस्वरूप ऊपर वर्णित कुछ ऐसे मामले भी सामने आ जाते हैं. सवाल ये है कि मानसिक गुलामों को इन गैरकानूनी कृत्यों के लिए ताकत कहां से मिलती है.

पशु क्रूरता अधिनियम 1960 में केंद्र सरकार ने हाल में पशु बिक्री के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं. अब पशुपालकों को अपने मवेशियों को बाजार में बेचने से पहले यह लिखित आश्वासन देना होगा कि वे मवेशियों को मांस कारोबार के लिए नहीं बेच रहे हैं. इतना ही नहीं, मवेशी भी केवल उन्हीं लोगों को बेचे जाएंगे, जो दस्तावेजी साक्ष्य दिखाकर यह साबित कर सकेंगे कि वे किसान हैं. इस अधिसूचना के आते ही कई राज्यों में विरोध शुरू हो गया. विरोध की यह आग उन राज्यों में भी भड़क उठी, जहां हाल में विधानसभा चुनाव होने हैं. भाजपा सरकार के लिए बुरी खबर यह थी कि विरोध करने वाले अधिकतर राज्यों में बीफ बैन नहीं है. इन राज्यों में सत्ताधारी दलों ने बीफ बैन को अपने फूड कल्चर पर हमले के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया. एक तरफ भाजपा का गौ प्रेम और दूसरी तरफ इन राज्यों में चुनाव जीतने की उत्कट इच्छा के बीच टकराव ने सरकार को मध्यम मार्ग अपनाने के लिए मजबूर किया. यही कारण है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों, गोवा, केरल और पश्चिम बंगाल में भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता अब बीफ बैन के विरोध में खड़े दिख रहे हैं. कह सकते हैं कि बीफ बैन पर विपक्ष के हमलावर तेवर ने सरकार के लिए दुविधा की स्थिति खड़ी कर दी है. गौरक्षकों का भगवा प्रेम अब फीका पड़ने लगा है.

## सियासी चाल पर भारी गौ चाल

बीफ बैन पर विपक्ष के हमलावर तेवर झेल रही भाजपा को मद्रास हाईकोर्ट के फैसले ने भी जबरदस्त पटखनी दी है. मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने पशु बिक्री के नए नियमों पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर चार सप्ताह में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. इधर, मेघालय सरकार ने भी पशुओं के खरीद-फरोख्त के केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है. मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने कहा कि केंद्र का यह नोटिफिकेशन नॉर्थ-ईस्ट के खिलाफ है. मेघालय की 80 फीसदी आबादी ईसाई है, जहां 89 फीसद लोग बीफ खाते हैं. मेघालय में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. भाजपा को नॉर्थ-ईस्ट या बीफ खाने वाले राज्यों में आगामी चुनाव जीतने के लिए अलग रणनीति अपनानी पड़ रही है. वहीं भाजपा की इस दोहरी चाल को बेनकाब करने के लिए विपक्षी भी मैदान में खम ठोके हैं. केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि सरकार लोगों के खाने की चीजें तय कर रही है. यह सही नहीं है. पशु बिक्री पर नोटिफिकेशन जारी करने से पहले सरकार को राज्य सरकारों से सलाह लेनी चाहिए थी. कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि किसी को क्या खाना है, क्या नहीं, यह केंद्र सरकार का एजेंडा नहीं है. इसे राज्य सरकार पर छोड़ देना चाहिए. वहीं, केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि बूचड़खानों में बिकने वाले मवेशियों की लिस्ट में से भैंस को हटाया जा सकता है. पर्यावरण मंत्रालय के सचिव एएनझा कहते हैं कि हमें बैन लिस्ट में संशोधन के लिए कुछ प्रस्ताव मिले हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है.

## केंद्र-राज्यों में संवैधानिक गतिरोध

**गौमांस पर प्रतिबंध लगने से अब बैलों और सांड़ों के मूल्य में 60 प्रतिशत तक की गिरावट देखी जा रही है. कभी कृषि व्यवस्था का आधार माने जाने वाले बैल भी अब ट्रैक्टर व कृषि में उन्नत टेक्नोलॉजी आने के बाद अनुत्पादक हो गए हैं. ऐसे में इन पशुओं को खुले में छोड़ देने के अलावा किसानों के पास कोई चारा नहीं है. इससे किसानों को अब वो पैसा भी नहीं मिल रहा है, जो पशुधन को बेचकर मिलता था. ऐसे में गौ की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना दम तोड़ रहे किसानों के गले में एक और फांस लगाने जैसा कदम है.**

पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना से देश में संवैधानिक गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई है. पशुपालन व कृषि मूल रूप से राज्यों के विषय हैं, जिस पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार नहीं है. वहीं पशु क्रूरता रोकने का विषय समवर्ती सूची में आता है, जिसपर केंद्र सरकार कानून बना सकती है. अपने इसी अधिकार के तहत केंद्र सरकार ने नई अधिसूचना जारी की है. हालांकि इसमें बीफ बैन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर मकसद कुछ वैसा ही था. इसके तहत कत्ल के लिए पशुओं की बिक्री पर रोक लगाई गई है, जो पशुओं पर क्रूरता के दायरे में आता है. केरल के मुख्यमंत्री विजयन इसे संघीय ढांचे और धर्मनिरपेक्ष संस्कृति की बुनियाद पर चोट मानते हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार कानून की आड़ में राज्य सरकार के अधिकारों का हनन कर रही है. यह नागरिकों के स्वतंत्र व्यापार करने के अधिकार और मनपसंद भोजन करने की स्वतंत्रता का भी उल्लंघन है.

## इन राज्यों में बीफ बैन नहीं

केरल, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में गोहत्या पर बैन नहीं है. वहीं, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओड़ीशा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में गोहत्या पर बैन लगा है.

## ममता-केंद्र की रार से पशु तस्करों की मौज

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पशु व्यापार के नए कानून को मानने से इंकार कर दिया है. ममता के इस रूख से पशु तस्कर राहत की सांस ले रहे हैं. अनुमान है कि सीमावर्ती इलाकों से रोजाना 40 हजार पशुओं को तस्कर बांग्लादेश भेजते हैं. हर साल पांच-दस करोड़ रुपए मूल्य के पशु जब्त भी किए जाते हैं, लेकिन सरकारी नीलामी के दौरान पशु तस्कर फिर इन पशुओं को खरीद लेते हैं. बांग्लादेश में पशुओं की कीमत 10 गुनी ज्यादा होने से तस्कर मोटा मुनाफा कमा लेते हैं. भारत-बांग्लादेश सीमा पर पांच पशु हाट संचालित हो रहे हैं. बीएसएफ अधिकारी बताते हैं कि इन हाटों में बिकने वाले पशुओं को देर-सबेर नदी मार्ग से सीमा पार भेज दिया जाता है. पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने सीमा के पास चलने वाले पशु बाजारों को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन ममता बनर्जी इस पर चुप्पी साधे हैं.

## किसानों के गले की फांस बना कानून

देश में करीब 70 प्रतिशत पशुपालक खेती-बाड़ी पर आश्रित हैं. सरकार के पशु बिक्री कानून की मार इन पशुपालक छोटे किसानों पर पड़ी है. गाय, बैल या भैंस की ज्यादातर बिक्री छोटे किसान ही करते हैं. सूखे व अकाल की स्थिति में पशुओं को चारा-पानी का प्रबंध करने में असमर्थ होने पर ये पशुओं को बेच देते हैं. इस पैसे से ही वे दुर्दिन, सूखा या अकाल में अपना गुजर-बसर करते हैं. अनुत्पादक पशुओं को पालने या उनके लिए चारा-पानी का प्रबंध करने में किसानों की कमर टूट जाती है. गौमांस पर प्रतिबंध लगने से अब बैलों और सांड़ों के मूल्य में 60 प्रतिशत तक की गिरावट देखी जा रही है. कभी कृषि व्यवस्था का आधार माने जाने वाले बैल भी अब ट्रैक्टर व कृषि में उन्नत टेक्नोलॉजी आने के बाद अनुत्पादक हो गए हैं. ऐसे में इन पशुओं को खुले में छोड़ देने के अलावा किसानों के पास कोई चारा नहीं है. इससे किसानों को अब वो पैसा भी नहीं मिल रहा है, जो पशुधन को बेचकर मिलता था. ऐसे में गौ की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना दम तोड़ रहे किसानों के गले में एक और फांस लगाने जैसा कदम है.

गाय की खाल पर आधारित चमड़ा उद्योग का व्यापार लगभग 11 अरब डॉलर का है. यहां तक कि 95 प्रतिशत जूता उद्योग भी इसी कच्चे माल पर निर्भर है. पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों का एक बहुसंख्यक तबका चमड़ा उद्योग से जुड़ा है.

## पशु हाट में पसरा सन्नाटा

पशुओं के रंभाने से गुलजार रहने वाले पशु हाटों में आज सन्नाटा पसरा है. किसान राममूर्ति बताते हैं कि इन दिनों गाय व भैंस को बाजार तक लाने का काम काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है. कहीं भी बजरंग दल व गौरक्षक पशुपालकों को घेरकर उनके साथ मारपीट करते हैं. अगर किसी तरह वहां से बच निकले तो अगले नाके पर पुलिस वाले घेर लेते हैं. हाट तक पशुओं को लाने के बाद किसानों की हिम्मत नहीं होती कि वे बिना बिके पशुओं को वापस लेकर जाएं. ऐसे में वे औने-पौने दाम पर ही पशुओं को बेच देते हैं. एक अनुमान के मुताबिक, बाजार में पशुओं की कीमत में 50 फीसद तक गिरावट आई है. मेवात के फिरोजपुर झिरका में पशु हाट लगता है. यहां 6 माह पहले करीब एक हजार पशु बिकने के लिए आते थे, जो अब घटकर 50-60 पशु तक रह गए हैं. इस पशु व्यापार से मेवात के करीब पांच हजार लोग जुड़े थे. इन पशु मेले के ठीकेदारों को भी तीन लाख रुपए प्रति सप्ताह घाटा हो रहा है. ठेकेदार नूर शाह का कहना है कि कई ठेकेदार मिलकर इस पशु मेले को 15 साल से ठेके पर लेते रहे हैं. सभी को हर साल 10 से 20 लाख रुपए मुनाफा हो जाता था. अब मुनाफा तो दूर की बात, एक करोड़ का घाटा उठाना पड़ सकता है.

गौ बिक्री पर नियंत्रण कर बीफ बैन लागू करने का ख्वाब देख रही सरकार को गौरक्षकों की गतिविधियों पर भी नियंत्रण रखना होगा. देश में पशुक्रूरता निवारण कानून पहले से ही है, जिससे पशुओं पर हो रहे अत्याचारों व क्रूरता पर दंड का प्रावधान है. अगर उन कानूनों का ही क्रियान्वयन सही ढंग से किया जाए, तो इन मूक, बेबस प्राणियों की जीवन रक्षा हो सकती है. गौ की रक्षा से ज्यादा गायों की खरीद-फरोख्त करने वालों को आतंकित कर गौरक्षक सरकारी योजना को ही पलीता लगा रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

# ग़लतियों से सीख रही है भाजपा

सरोज सिंह

कहते हैं गलतियों से सबक सीखने की आदत ही कामयाबी की राह खोलती है. जो गलतियों से नहीं सीखता, वह बिखर जाता है. तमाम उम्मीदों और प्रयासों के बावजूद जब पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में भाजपा सत्ता से काफी दूर रह गई तो एक पल लगा कि अब आगे की राह पार्टी के लिए काफी मुश्किल हो गई है. भाजपा ने जाने-अनजाने 2015 के विधानसभा चुनाव में इतनी गलतियों को अंजाम दे दिया कि उसका बना-बनाया खेल ही बिगड़ गया. विरोधी एकता को कम आंकना और जमीनी हकीकत से इतर फैसले लेकर भाजपा ने सत्ता में वापसी का एक सुनहरा मौका खो दिया. लेकिन पार्टी के लिए संतोष की बात है कि बहुत जल्द वह हार के सदमे से उबर कर आगे की राह पकड़ने की कवायद में जुट गई है.

भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार अमित शाह ने प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय को फ्री हैंड दे दिया है. अमित शाह ने उन्हें साफ कह दिया है कि उन्हें 2014 के प्रदर्शन को सूबे में दोहराना है. नित्यानंद राय यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि उनके सामने काफी कड़ी चुनौती है. लालू प्रसाद और नीतीश कुमार अगर एकसाथ बने रहे तो 34 वाले आंकड़े को पाना लगभग असंभव हो जाएगा. नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का जो करिश्मा काम करे, लेकिन अगर महागठबंधन एकजुट रहा और पिछड़ी जातियों की मजबूत गोलबंदी जारी रही तो फिर विधानसभा वाला हाल ही हो जाएगा. भाजपा के रणनीतिकार यह समझ रहे हैं कि सूबे में जिस तरह विकास पर जातीय गोलबंदी हावी रहती है, वैसे में महागठबंधन में दरार डाले बिना लोकसभा का महारण जीता नहीं जा सकता है. इसलिए एक उच्चस्तरीय बैठक में महागठबंधन की कमजोर कड़ी यानि लालू एंड फैमिली पर ताबड़तोड़ हमले की रणनीति बनाई गई. प्रदेश कमिटी के गठन में सुशील मोदी को लेकर जो कड़वाहट थी, उसे भी दूर करने को कहा गया. तय हुआ कि नीतीश कुमार पर हमले कम से कम हों और लालू व उनके परिवार के भ्रष्टाचार को जमकर उछाला जाए. सुशासन की दुहाई देकर नीतीश कुमार से बस इतना पूछा जाए कि क्या कानून का राज इसी तरह से चलता है. बैठक के फैसलों को अमलीजामा पहनाने के लिए सुशील मोदी को दस्तावेजों का पुलिंदा देकर आगे कर दिया गया. सूत्र बताते हैं कि लालू और उनके परिवार से जुड़े भ्रष्टाचार के दस्तावेजों को मुहैया कराने में जदयू का एक गुट भी सक्रिय है. लालू के बड़े बेटे तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, इसलिए शुरुआत उन्हीं से की गई और मॉल की मिट्टी को जू में खपाने का मुद्दा उछाला गया. इसके बाद घेरे में तेजप्रताप, राबड़ी देवी, मीसा भारती

और उनके पति शैलेश आते चले गए. इस बीच चारा घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने भाजपा को मुंहमांगा वरदान दे दिया. इन आरोपों को कोर्ट की बैशाखी मिल जाने के बाद भाजपा ने अब भ्रष्टाचार के इन मुद्दों को सड़क पर ले जाने का मन बना लिया. सभी जिला मुख्यालयों में पार्टी ने धरना-प्रदर्शन कर जनता को यह संदेश देने का प्रयास किया कि नीतीश कुमार सुशासन की बात तो करते हैं पर लालू और उनके भ्रष्टाचार पर चुप हैं. सुशील मोदी कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार सही मायनों में सुशासन के अगुआ हैं, तो फिर तेजस्वी और तेजप्रताप पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सुशील मोदी सवाल दागते हैं

कि मंत्री तेजप्रताप और तेजस्वी यादव द्वारा दाखिल की गई संपत्ति और उम्र के झूठे शपथपत्र के खिलाफ कार्रवाई करना मुख्यमंत्री के दायरे से बाहर कैसे है? विधायकों को को-ऑपरेटिव में सैकड़ों विधायकों के प्रतीक्षारत रहने के बावजूद लालू प्रसाद और जयप्रकाश यादव को दो-दो प्लॉट आवंटन पर नीतीश कुमार की नजर क्यों नहीं जा रही है?

बिना पर्यावरण विभाग की अनुमति के 750 करोड़ के मॉल का निर्माण होने देना, क्या नीतीश कुमार के दायरे से बाहर की चीज है. भाजपा का इस तरह लालू एंड फैमिली पर हमला कर नीतीश कुमार को कटघरे में खड़े करने की रणनीति महागठबंधन को कमजोर करने की पहली कवायद है, जो काफी हद तक निशाने पर लगी है. नीतीश कुमार इन मामलों में बहुत संभलकर बोल रहे हैं और अपने सुशासन की इमेज को बचाने में लगे हैं. सुशासन ही नीतीश कुमार की पूंजी है और इसे वे खोना नहीं चाहेंगे. भाजपा के थिंक टैंक मान कर चल रहे हैं कि जिस तरह से भ्रष्टाचार का मामला बिहार में सबकी जुबां पर चढ़ता जा रहा है, उससे घबराकर नीतीश कुमार को एक न एक दिन कुछ कड़े फैसले करने ही पड़ेंगे. इसी तरह इंटर टॉपर को लेकर सरकार की जो छीछालेदार हो रही है, उसे भी भाजपा हथियार बना रही है. शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी कांग्रेस कोटे से हैं, इसलिए भाजपा को लग रहा है कि अगर इस मामले को भी उछाला जाए तो कांग्रेस को लेकर भी नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ेगा. कहा जाए तो भाजपा ने महागठबंधन को कमजोर करने का जो पहला टास्क लिया था, उसमें वह कामयाब होती जा रही है. अब दूसरा टास्क महागठबंधन के पक्ष में पिछड़ों की गोलबंदी रोकने की है. यह टास्क भाजपा के लिए नया नहीं है. देखें तो विधानसभा चुनाव के दौरान भी इस दिशा में पार्टी ने काम किया था, लेकिन वह आधे-अधूरे मन से हुआ था. भाजपा अब अपनी पुरानी गलती सुधारने में लगी है. यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बिहार दौरा तय कर दिया गया है. कुशवाहा समाज के मजबूत नेता सम्राट चौधरी को उनकी उपस्थिति में पार्टी में शामिल कराया गया है. गौरतलब है कि कुशवाहा समाज में सम्राट चौधरी की अच्छी पकड़ है. सम्राट चौधरी को आगे कर भाजपा कुशवाहा और अन्य पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने की फिराक में है. जानकार बताते हैं कि भाजपा की तैयारी है कि प्रमंडल स्तर पर पिछड़ी व अतिपिछड़ी जातियों का बड़ा सम्मेलन आयोजित कर उसे पार्टी के पक्ष में गोलबंद किया जाए. इसे लेकर भाजपा में गंभीर मंथन चल रहा है और जल्द ही इस प्लान को अमलीजामा पहना दिया जाएगा. प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय कहते हैं कि हमलोग बारह महीने जनता के बीच रहने वाले लोग हैं. हमलोग सत्ता में रहें या बाहर, जनता से सीधा संवाद करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उसका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं. राय मानते हैं कि भाजपा का हर कार्यकर्ता इस समय सूबे में पार्टी का जनाधार और मजबूत करने के लिए काम कर रहा है. जनता इस सरकार के भ्रष्टाचार और घोटाले से परेशान है और नीतीश कुमार से पूछ रही है कि क्या हुआ आपके सुशासन का. राय का दावा है कि यह सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है और जल्द ही बिहार की जनता को इस भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति मिलेगी. बहरहाल यह कहा जा सकता है कि भाजपा अपनी पुरानी गलतियों से सीख रही है और सही ढंग से विपक्ष की भूमिका निभाने का प्रयास कर रही है. अब यह महागठबंधन की सरकार को तय करना है कि भाजपा के इस बढ़त को कैसे रोका जाए. ■

feedback@chauthiduniya.com

## एनडीटीवी-सीबीआई छापा

# राम गयो, रावण गयो, जाके बहु परिवार : अरुण शौरी

चौथी दुनिया ब्यूरो

***तुम से पहले वो जो इक शख़्स यहां तख़्तनशीं था,***
***उसको भी अपने ख़ुदा होने पे इतना ही यक़ीं था.***

दिल्ली के प्रेस क्लब में इंडियन एक्सप्रेस के पूर्व संपादक और भाजपा नेता अरुण शौरी ने जैसे ही मुस्कुराते हुए ये शेर पढ़ा, तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी. दरअसल, शौरी ने ये शेर सीधे-सीधे नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा था. इसके साथ ही उन्होंने एक और ताकीद भी कर दी कि राम गयो, रावण गयो, जाके बहु परिवार और फिर अरुण शौरी का ये कहना कि ये भी जाएंगे, नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला था. मौका था दिल्ली के प्रेस क्लब में एनडीटीवी के प्रमोटर्स के यहां पड़े सीबीआई छापे के विरोध में आयोजित पत्रकारों की एक बैठक का. दरअसल, कुछ ही दिन पहले एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणय रॉय और राधिका रॉय के यहां सीबीआई ने छापे मारे थे. उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक निजी बैंक से लिया हुआ कर्ज नहीं चुकाया है. इस छापे को मीडिया की आजादी पर हमले के तौर पर देखा गया. इसी के विरोध में दिल्ली के प्रेस क्लब में कई महत्व-पूर्ण पत्रकारों ने एक बैठक आयोजित कर इसे केंद्र सरकार की दुर्भावनापूर्ण बदले की कार्रवाई बताया. इस मौके पर अरूण शौरी, कुलदीप नैयर, फली एस नरीमन, एच के दुआ, शेखर गुप्ता, प्रणय रॉय आदि मौजूद रहे.

इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतने सारे मित्रों को साथ ला दिया. पहले उन्होंने विज्ञापनों जैसे प्रोत्साहन दिए, फिर डर का ये माहौल दिया. अब दबाव डालने के लिए वे तीसरे साधन का उपयोग कर रहे हैं. उन्होंने एनडीटीवी के रूप में हमें एक उदाहरण दिया है. मुझे आशंका है कि आने वाले महीनों में ये सरकारी प्रवृत्ति और भी ज्यादा उग्र होगी. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार सर्वसत्तावादी है, यानि ये हर एक चीज पर अपना अधिकार जमाना चाहती है. लेकिन सरकार को याद रखना चाहिए कि जिस किसी ने भी भारत में प्रेस पर हाथ डालने की कोशिश की, वो अपने हाथ जला बैठा. श्री शौरी ने कहा कि एनडीटीवी द्वारा दिए गए तथ्यों का सीबीआई जवाब तक नहीं दे पा रही है. उन्होंने वहां मौजूद पत्रकारों से कहा कि आपको अपने मित्र की मदद करनी ही चाहिए, क्योंकि वो आपको बांटने की

**वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने इस मौके पर कहा कि आपातकाल के दौरान किसी को किसी से ये नहीं कहना पड़ता था कि क्या करना है. सभी जानते थे कि क्या करना है. तब इंडियन एक्सप्रेस एक प्रतीक बन गया था. आज जब हम कमोबेश वैसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं. हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम किसी को भी बोलने की आजादी छीनने ना दें. वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने कहा कि ये प्रेस की आजादी पर हमला है. सोशल मीडिया ने हम सबको गुमराह कर दिया है. अन्य पेशों की तुलना में पत्रकारिता में कहीं बेहतर लोग हैं. कोई भी प्रोस्टिट्यूट नहीं है. दुर्व्यवहार से न डरें. वहीं प्रणय रॉय ने कहा, एक बार मैं चीन गया. वहां मुझसे पूछा गया, क्या आपको हमारी गगनचुंबी इमारतें देखकर जलन नहीं होती है?**

कोशिश करेंगे. आप केवल यंत्र न बनें. साथियों का समर्थन नहीं करने से ज्यादा हतोत्साहित करने वाली बात कोई और नहीं होती. मेरी अपने प्रेस के सहयोगियों से शिकायत है कि हम उतने सतर्क नहीं रहें, जितना हमें रहना चाहिए था. ये बहुत दुखद है कि आरटीआई का गला घोंटे जाने के समय हमें जैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए थी, वैसी हमने नहीं की.

राज्यसभा के पूर्व सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार एचके दुआ ने कहा कि पिछली दफा प्रेस के ज्यादातर लोग खड़े नहीं हुए थे और जैसा कि आडवाणी ने कहा था, वे रेंग रहे थे. उसके बाद अवमानना विधेयक आया. राजीव गांधी बात करना चाहते थे, लेकिन हमने इंकार कर दिया. तब प्रेस की एकता ने लड़ाई जीत ली थी. विधेयक वापस लेना पड़ा था, क्योंकि लोग उसके खिलाफ थे. वैसे ही संकेत अब भी दिख रहे हैं. अगर हम एकजुट हों, तो फिर से उसे दोहरा सकते हैं. इस अवसर पर मशहूर वकील और न्यायविद फली नरीमन ने कहा कि एनडीटीवी मामले में जिस तरह से कार्रवाई की गई है, उससे मुझे लगता है कि ये प्रेस की आजादी पर हमला है. 2 जून को सीबीआई ने 7 साल पहले हुई घटना के लिए एफआईआर दर्ज की, वो भी बिना किसी जांच के, केवल संजय दत्त नाम के एक शख्स द्वारा दी गई सूचना के आधार पर. सीबीआई को ऐसा कोई मामला दायर करते समय एनडीटीवी की प्रतिक्रिया लेनी चाहिए थी. लेकिन ऐसा नहीं किया गया. ये संवैधानिक कर्तव्य का मामला है. इंदिरा गांधी के समय भी मीडिया पर ऐसे ही हमले हुए थे. तब इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ रिटर्न नहीं फाइल करने के 120 मामले दर्ज कराए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अंततः हमारी जीत हुई.

वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने इस मौके पर कहा कि आपातकाल के दौरान किसी को किसी से ये नहीं कहना पड़ता था कि क्या करना है. सभी जानते थे कि क्या करना है. तब इंडियन एक्सप्रेस एक प्रतीक बन गया था. आज जब हम कमोबेश वैसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं. हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम किसी को भी बोलने की आजादी छीनने ना दें. वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने कहा कि ये प्रेस की आजादी पर हमला है. सोशल मीडिया ने हम सबको गुमराह कर दिया है. अन्य पेशों की तुलना में पत्रकारिता में कहीं बेहतर लोग हैं. कोई भी प्रोस्टिट्यूट नहीं है. दुर्व्यवहार से न डरें. वहीं प्रणय रॉय ने कहा, एक बार मैं चीन गया. वहां मुझसे पूछा गया, क्या आपको हमारी गगनचुंबी इमारतें देखकर जलन नहीं होती है? मैंने कहा, हमारे पास सर्वश्रेष्ठ स्काईस्क्रैपर्स हैं- आजाद माहौल. ये मामला केवल एनडीटीवी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये हम सब के लिए एक संकेत है. प्रेस की आजादी भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ बात है. उन्होंने कहा कि हम किसी एजेंसी के खिलाफ नहीं लड़ रहे. वे भारत की संस्थाएं हैं, लेकिन हम उन नेताओं के खिलाफ हैं, जो इनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मैंने या राधिका ने काले धन का एक रुपया भी नहीं रखा है. हमने कभी किसी को रिश्वत नहीं दी है. इस मौके पर अनुपस्थित रहे वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने अलग से एक वीडियो संदेश जारी कर कहा, मुझे लगता है कि वर्तमान माहौल में चुप रहना कोई विकल्प नहीं है. ये वो क्षण है, जब हमें इतिहास में सही किनारे पर खड़ा होना होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

# दफ़न हो रहे इंसान पलता झाड़त साहेबान

प्रशान्त शरण

झारखंड में झरिया के इंदिरा चौक के पास अपने अब्बू के साथ 10 साल का रहीम खान जब चाय पीकर अपने घर लौट रहा था, तो कुछ ही दूरी के बाद उसके कदमों के भार से जमीन धंस गई और वो उसमें जिंदा दफन हो गया. उसे बचाने आए उसके पिता बबलू खान भी उसमें गिर पड़े और उनकी भी मौत हो गई. दस फीट के बने गोफ में बेटा और बाप जिंदा दफन हो गए. ये कोई नई बात नहीं है. लेकिन झरिया में जमीन के नीचे कोयले में लगी आग से प्रशासन की नींद अभी तक नहीं खुली है. कोयलांचल के इस क्षेत्र के 17 हजार वर्ग किलोमीटर में वर्षों से आग लगी हुई है. लगभग आठ लाख परिवार इससे प्रभावित हैं, लेकिन अभी तक इनलोगों को पुनर्वासित करने का काम सरकार द्वारा नहीं किया जा सका है. उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने 2009 में ही झरिया मास्टर प्लान बनाया था. ये देश की सबसे बड़ी फायर फाईटिंग व पुनर्वास योजना है. इसमें 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बसाने की योजना बनाई गई थी. हालांकि इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा, मुआवजा और जिम्मेदारी अब तक तय नहीं हो सकी है. जब भी कोई मौत होती है, तो प्रशासन एवं बीसीसीएल के अधिकारी एक-दूसरे के माथे पर उसका ठीकरा फोड़ने का खेल शुरू कर देते हैं. वहीं राज्य सरकार एवं भारत सरकार पंच की भूमिका में आ जाती है.

बीसीसीएल एवं राज्य सरकार की इस लड़ाई में यहां के लोग जिंदा दफन होने को मजबूर हैं. नीचे कोयले की आग और गैस रिसाव और ऊपर जिंदगी. 17 हजार वर्ग किलोमीटर में फैले इस आग के ऊपर लगभग आठ लाख जिंदगियां हैं. जमीन के अंदर कोयले में लगी आग से वे पूरा इलाका दहक रहा है, भू-धसान एवं गैस रिसाव की घटनाएं आम हो गई हैं. हाल में हुए हादसे से यहां के लोग भारी दहशत में हैं कि पता नहीं कब किसका मकान धंस जाय. इस क्षेत्र के 595 जगहों को चिन्हित किया गया है, जहां जमीन के नीचे लगी कोयले की आग से भू-धसान का खतरा है. इसमें 42 जगहों को तो अत्यधिक खतरनाक माना गया है, जिसे तुरंत कहीं शिफ्ट करने की बात कही जा रही है. अगर ये काम जल्द नहीं किया गया, तो एक बड़ी घटना कभी भी घटित हो सकती है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं तो तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेट है, जिसे देखकर एनडीआरएफ की टीम भी हैरान हो गई है.

दरअसल, ये काम इसलिए धीमी गति से चल रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इससे अपना हाथ खींच लिया है. पहले ये योजना दस हजार करोड़ की थी, लेकिन अब ये बढ़कर 31 हजार करोड़ रुपए की हो गई है. पहले बने मास्टर प्लान में कहा गया था कि आग पर नियंत्रण और अग्निक्षेत्र में रह रहे कोल कर्मियों के सुरक्षित जगहों पर पुनर्वास की जिम्मेदारी बीसीसीएल की है, वहीं रैयती एवं अतिक्रमणकारियों का पुनर्वास राज्य सरकार को करना है. इसके लिए बकायदा झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है. उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल के आयुक्त को इस बोर्ड का अध्यक्ष, बीसीसीएल के सीएमडी को उपाध्यक्ष और जिले के उपायुक्त को सचिव बनाया गया है. केंद्र सरकार के स्तर पर कोयला मंत्रालय ने मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए हाइपावर कमिटी गठित कर रखी है, जो नियमित बैठक करती है. उच्चतम न्यायालय इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है. लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि इतनी सुस्पष्ट व्यवस्था व रोडमैप के बावजूद अग्निक्षेत्र में हर मौत के बाद जिम्मेदारी की फेकाफेकी होती है. प्रशासन आग बुझाने की जिम्मेदारी जहां बीसीसीएल पर डालता है, तो वहीं बीसीसीएल प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को हटाने की जिम्मेदारी प्रशासन पर डालती है. जिम्मेदार संस्थानों के बीच तालमेल है ही नहीं. इसका खामियाजा प्रभावित क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जबकि इस तरह की घटनाओं के लिए सभी दोषी हैं, यहां तक कि केंद्र सरकार भी. शुरू में पुनर्वास कार्य में जो तेजी आई थी, वो अटक सा गई है. कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है. नई जगह पर उनके जीवन-यापन का क्या साधन होगा, इसका हल अभी तक नहीं निकला जा सका है. अग्निक्षेत्र के प्रभावित लोगों को क्या मुआवजा मिलेगा, ये भी बड़ा सवाल बन गया है. अग्निक्षेत्र में लगभग 1.25 हजार परिवार रह रहे हैं. इसमें 30 हजार रैयत लोगों को मुआवजा देने का प्रावधान है. अतिक्रमणकारियों को जहां बना बनाया आवास मिलेगा, वहीं रैयतों को अपने घर जमीन का बाजार मूल्य के साथ ही बसने के लिए सुरक्षित जमीन. अतिक्रमणकारी भी दोनों चीजें मांग रहे हैं. इसके कारण प्रशासन को पुनर्वास करने में कठिनाई आ रही है. इधर 10 हजार करोड़ की योजना 31 हजार करोड़ की हो गई और इसे देखकर केंद्र सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं.

जमीन की आग के कारण धनबाद चंद्रपुरा रेल लाईन को भी बंद कर दिया गया है, जिसके कारण सवा करोड़ यात्रियों के आवागमन के साथ ही कोयला दुलाई की समस्या भी खड़ी हो गई है. 34 किलोमीटर के इस रेलखंड को बंद कर दिए जाने से सात राज्यों के पावर प्लांटों को कोयला मिलने में परेशानी होगी. रेलवे को इससे लगभग 3000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा. वैकल्पिक लाईन बनने में लगभग पांच साल लग जाएंगे.

इधर, अधिकारी भी अब स्थिति की गंभीरता को लेकर चिंता जाहिर करने लगे हैं. राज्य सरकार की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने स्थिति को भयावह बताते हुए कहा कि जल्द ही अग्निप्रभावित क्षेत्रों को खाली करा दिया जाएगा. बीसीसीएल के तकनीकी निदेशक भी ये स्वीकार करते हैं कि झरिया की आग एवं गैस रिसाव अब खतरनाक रूप लेता जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस आग का दायरा काफी बड़ा है और काफी नीचे तक है. बारिश के मौसम में धसान का खतरा और बढ़ जाएगा. इसलिए प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को हटाने के लिए पहले ही नोटिस दिया जा चुका है. बीसीसीएल के लोगों के पुनर्वास का काम बीसीसीएल के द्वारा किया जा रहा है. आधे से अधिक कर्मचारियों को दूसरे जगह शिफ्ट किया जा चुका है, जबकि गैर बीसीसीएल के लोगों को दूसरे जगह बसाने की जिम्मेदारी झरिया विकास प्राधिकरण को दी गई है. वहीं, धनबाद के उपायुक्त ए दोड्डे का कहना है कि असुरक्षित क्षेत्र को खाली करने के लिए लोग मानसिक रूप से तैयार रहें.

प्रभावित परिवार नए कानून के तहत जमीन के बदले मुआवजा और कोल इंडिया की पॉलिसी के तहत नियोजन की मांग कर रहे हैं. बीसीसीएल के अधिकारियों का कहना है कि हमें कोयला खनन के लिए इस क्षेत्र में जमीन चाहिए ही नहीं. दूसरी ओर भू-अर्जन की जटिल प्रक्रिया के कारण जमीन उपलब्ध नहीं होने से विस्थापितों के लिए नई कॉलोनी बनाने में दिक्कतें आ रही हैं, जिसके कारण काम धीमी गति से चल रहा है. कोल फील्ड बचाओ समिति के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल का कहना है कि कोयले के लिए बीसीसीएल आग को दहका रही है. झरिया में पहले चारो ओर हरियाली थी, लेकिन ओपन कास्ट माइनिंग ने धरती का कलेजा चीर कर तस्वीर बदल दी है. हरियाली की जगह अब गैस रिसाव और काली मिट्टी पत्थर के पहाड़ ही दिखते हैं. ओपन कास्ट माईंस की वजह से कोयले में लगी आग हवा के सम्पर्क में आ गई, जिससे आग का दायरा बढ़ता ही चला गया. इस पर कभी अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया. उन्होंने कहा कि झरिया पुनर्वास योजना सौ सालों में भी पूरी नहीं होगी.■

feedback@chauthiduniya.com

## स्थिति भयावह, जल्द ही पुनर्वास होगा: मुख्य सचिव

झारखंड की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि झरिया की स्थिति अत्यंत भयावह है. जमीन के अंदर एक बड़े भू-भाग में आग लगी हुई है. साथ ही दूषित गैस भी निकल रही है. इससे कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है. इस स्थिति से जल्द ही निबटना होगा. झरिया पुनर्वास बोर्ड विस्थापितों को पुनर्वासित करने का काम कर रहा है. जल्द ही प्रभावित परिवारों को यहां से हटाया जाएगा. जिला प्रशासन एवं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द प्रभावित क्षेत्र के लोगों को शिफ्ट करें. बीसीसीएल कर्मियों को शिफ्ट करने का काम तेजी से चल रहा है. झरिया एवं अन्य प्रभावित क्षेत्रों में रेल परिचालन को भी 15 जून से बंद कर दिया है. रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में फैसला ले लिया है. मुख्य सचिव ने बताया कि जहां पर लोगों का पुनर्वास किया जाएगा, वहां हर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने बताया कि 42 ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां के परिवारों को तुरंत दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा. इसके बाद अन्य जगहों के परिवारों को शिफ्ट किया जाएगा. उन्होंने बताया कि झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण द्वारा छः हजार आवास बनाए गए हैं. उपायुक्त को समय-समय पर आवश्यक निर्देश दिया जा रहा है.■

## अग्निक्षेत्र से हटाए जाएंगे सभी कोलकर्मी

झरिया में जमीन के नीचे कोयले की आग व गैस रिसाव के खतरनाक रूप को देखते हुए प्रभावित लोगों के पुनर्वास की प्रक्रिया तेज की दी गई है. असुरक्षित स्थानों से लोगों को हटने के लिए जरेडा व बीसीसीएल की ओर से पहले ही नोटिस दिया जा चुका है. खतरे वाले स्थानों को चिन्हित कर वहां से बसे लोगों का सर्वे कर हटने के लिए कहा गया है. जरेडा को गैर बीसीसीएल लोगों को बसाने की जिम्मेवारी दी गई है. बीसीसीएल अपनी जिम्मेदारी के तहत अग्निप्रभावित क्षेत्र में रह रहे कोलकर्मियों को शीघ्र हटाने जा रही है. इस दिशा में काम शुरू किया गया है. इसमें और तेजी लाने के लिए हर क्षेत्र के महाप्रबंधक व अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया गया है. कोल कर्मियों को सुरक्षित जगहों पर बसाने के लिए 15852 नए आवास बनाए जा रहे हैं. 6416 आवास बन कर तैयार हैं. अब तक 2876 कोल कर्मियों को नए आवास में शिफ्ट किया जा चुका है. कुसुंडा, बस्ताकोला, सिजुआ, लोदना सहित प्रभावित एरिया के कर्मियों को प्राथमिकता से शिफ्ट किया जाएगा. कहा जा रहा है कि 2019 तक सभी कोल कर्मियों को भूमिगत आग व खतरनाक स्थानों से हटा लेने का लक्ष्य रखा गया है. नए आवासों में पानी व बिजली की व्यवस्था शीघ्र करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है. कर्मियों के लिए नई जगहों पर सारी सुविधाएं दी जा रही है. पानी, बिजली, चिकित्सा व्यवस्था समेत बच्चों के लिए स्कूल की भी व्यवस्था है. हालांकि आवास के आकार को लेकर शिकायतें आ रही हैं. लेकिन अधिकारी इससे इंकार करते हैं. उनका कहना है कि आकार उतना भी छोटा नहीं है, डिजाइन पास होने के बाद ही ये आवास बनाए गए हैं.

## हादसों की लंबी फेहरिस्त

- 26 सितम्बर 1995 को केंदुआ के चौरसिया दंपत्ति इसके शिकार हुए.
- वर्ष 1996 में कतरास मोड़ में भू-धसान की घटना.
- 4 अगस्त 1997 को धर्म नगर की गीता नामक बालिका भू-धसान में दफन
- जून 1999 में सेंट्रल बासजोड़ा में एक युवक जिंदा दफन, भू-धसान में कई घर क्षतिग्रस्त.
- वर्ष 2006 में शिमलाबहाल बस्ती की मीरा नामक लड़की जमीन में धंस कर जिंदा जली.
- 15 मार्च 2007 को बीसीसीएल के नयाडीह कुसुंडा में भू-धसान में दस लोगों की मौत.
- वर्ष 2008 में सेल के सेवानिवृत्त कर्मी चासनाला के उमाशंकर त्रिपाठी इंदिरा चौक के पास जमीन धंसने से जिंदा जले.
- 16 मई 2008 को चासनाला की डेको परियोजना में डोजर मशीन समेत विनोद दास नामक कर्मी दफन.
- 19 सितम्बर 2008 को कुजामा में ज्योति नामक बालिका गोफ में गिर कर मरी.
- अक्टूबर 2008 में धर्म नगर झरिया में भू-धंसान में सुंदरी देवी की मौत.
- 5 फरवरी 2016 को सुदामडीह में भू-धंसान में जीरा देवी मकान समेत दफन.
- 13 मार्च 2017 को बोका पहाड़ी में भू-धंसान से पचास फीट व्यास का गोफ बना.

# देश के किसान क्यों निराश हैं

**वर्ष 2016 में भरपूर फसल के साथ आयात कीमतें 63 फीसदी तक नीचे हुई हैं. नोटबंदी के कारण नकदी में भी कमी हुई. पिछले छह दशकों से वर्ष 2011 तक 3.5 लाख करोड़ रुपए निवेश करने के बावजूद आधे से अधिक किसान वर्षा पर निर्भर हैं. हम बता दें कि निवेश की गई यह राशि 545 टिहरी-आकार के बांधों के निर्माण के लिए पर्याप्त है.**

प्राची साल्वे/एलिसन सलदनहा/विपुल विवेक

ये तीन कारण हैं जिसकी वजह से खेती पर निर्भर भारतीय किसान आक्रोश में हैं. यहां यह जान लेना जरूरी है कि भारत में 9 करोड़ परिवार खेती पर निर्भर हैं.

पुलिस गोलीबारी में छह किसानों की मौत के बाद मध्यप्रदेश के ग्रामीण इलाकों में आक्रोश भड़का और किसानों का विरोध-प्रदर्शन महाराष्ट्र और ऋण-ग्रस्त राज्यों में और तेज हुआ. हमने महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में किसानों के आक्रोश और निराशा के कारण जानने की कोशिश की है. विश्लेषण में हमने पाया कि किसानों का ये विरोध ऋण माफी की मांगों को लेकर है. भारत में खेती अप्रभावी होने का मुख्य कारण खेतों का लगातार छोटा होना है. दुनिया में सबसे ज्यादा छोटे खेत भारत में ही पाए जाते हैं. यहां इन सिकुड़ते खेतों पर अधिक लोगों की निर्भरता है. हम बता दें कि वैश्विक औसत जमीन धारक आकार 5.5 हेक्टेयर है.

कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1951 के बाद से प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता में 70 फीसदी की गिरावट हुई है. ये आंकड़े वर्ष 2011 में 0.5 हेक्टेयर से 0.15 हेक्टेयर तक हुए हैं और भविष्य में और भी कम होने की आशंका है. इस तरह के छोटे और सीमांत भूमि-धारक इस समय देश में परिचालित खेतों की संख्या का 85 फीसदी बनाते हैं, जैसा कि भारतीय कृषि राज्य पर 2015-16 की रिपोर्ट में कहा गया है.

छोटे खेतों पर आधुनिक मशीनरी का उपयोग आमतौर पर नहीं होता. इस तरह के खेतों के मालिक अक्सर महंगे उपकरण खरीदने में सक्षम नहीं होते हैं. मैनुअल ढंग से खेती करने में लागत बढ़ती है. गांव छोड़कर श्रमिक लगातार शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं. इससे श्रमिकों का मिलना मुश्किल हो रहा है. इसके अलावा खेतों का छोटा आकार और उससे बहुत कम उपज ऋण और संस्थागत ऋण तक पहुंच को सीमित करता है.

## सूखे के बाद अच्छी फसल लेकिन आय में गिरावट

वर्ष 2017 में, भारत के खेतों के लिए अच्छी खबर मिली. वर्ष 2014 और 2015 के सूखे के बाद, 2016 में अच्छे मानसून ने दो साल के ग्रामीण आर्थिक गिरावट को बदल दिया. भारत में कृषि विकास दर 2014-15 में 0.2 फीसदी थी. लगातार पड़ने वाले सूखे के कारण यह दर 2015-16 में 1.2 फीसदी से अधिक नहीं बढ़ी. 2016-17 में, कृषि अर्थव्यवस्था में 4.1 फीसदी की वृद्धि हुई है.

दाल उगाने वाले कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात के बाजारों में माल बहुत आया है. विशेषकर तूर दाल, क्योंकि इसकी उपज अन्य दालों की तुलना में सबसे अधिक हुई है. अधिकतर भारतीयों के लिए दाल प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उपजाने वाला देश है.

हालांकि सितंबर 2016 से मार्च 2017 तक के दो वित्तीय तिमाहियों में म्यांमार, तंजानिया, मोज़ाम्बिक और मलावी से दालों की आवक 20 फीसदी बढ़ी है. इस बारे में बिजनेस स्टैंडर्ड ने 3 मार्च, 2017 की अपनी रिपोर्ट में बताया है. इस कारण भारतीय तूर दाल की कीमतों में गिरावट हुई है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 7 जून, 2017 को जारी एक मौद्रिक नीति बयान में कहा गया है, कि दालों की कीमत स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड उत्पादन और अत्यधिक आयात के कारण लड़खड़ा रही है.

दिसंबर 2015 में तूर दाल की कीमत 11,000 रुपए प्रति क्विंटल थी. अब यह कीमत 63 फीसदी घटकर प्रति क्विंटल 3800-4000 रुपए हो गई है. इस कीमत पर सरकार कृषि उत्पादन खरीदती है और यह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से 20 फीसदी नीचे है.

दालों के उत्पादन में 29 फीसदी की वृद्धि हुई है. वर्ष 2014-15 में दालों का उत्पादन 17.15 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 22.14 मिलियन टन हुआ है. इसी अवधि के दौरान तूर दाल के उत्पादन में 50 फीसदी की वृद्धि हुई है. तूर दाल का उत्पादन 2.81 मिलियन टन से बढ़कर 4.23 मिलियन टन हुआ है. सितंबर 2016 में मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन की अध्यक्षता वाली एक सरकारी समिति ने वर्ष 2017 में तूर दाल के लिए एमएसपी बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति क्विंटल और 2018 में 7,000 रुपए प्रति क्विंटल करने की सिफारिश की है.

मार्च 2017 तक, दाल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,050 रुपए प्रति क्विंटल था. यह राशि दालों पर समिति द्वारा सिफारिश की गई कीमतों से लगभग 20 फीसदी या 18 फीसदी कम है. कीमतें कम होने के साथ किसानों के लिए अपने उत्पाद का भंडारण करने और नोटबंदी के कारण नकदी में कमी से अगले मौसम के लिए धन प्राप्त करना मुश्किल हो गया है. हम बता दें कि 8 नवंबर 2016 को सरकार ने देश की 86 फीसदी मुद्रा को अमान्य घोषित कर दिया था.

## नोटबंदी से किसानों को हुई नकद की कमी

18 मई को दोपहर की कड़ी धूप में 30 वर्षीय प्रशांत लांडे ने भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई से 664 किमी पूर्व अमरावती कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) को 800 क्विंटल तूर बेचने के लिए घंटों इंतजार किया.

महाराष्ट्र के विदर्भ के पूर्वी क्षेत्र में, अमरावती जिले के आष्टी तालुका के सिंहला गांव के लांडे कहते हैं कि उन्होंने अपनी 800 क्विंटल तूर सरकारी खरीद केंद्र में बेचने से इनकार कर दिया. हालांकि राज्य उच्चतम दर पर तूर खरीदता है. बाजार में लांडे अपना तूर 3,800 रुपए से 4,000 रुपए प्रति क्विंटल में बेच सकते थे, जबकि सरकारी खरीद केंद्र ने 5,050 रुपए प्रति क्विंटल की पेशकश की थी.

लांडे कहते हैं, हम सरकारी केंद्र में नहीं बेचते, क्योंकि बिक्री की प्रक्रिया एक महीने में पूरी होती है. बिक्री के लिए टोकन के लिए लाइन में खड़े होने से भुगतान खाते तक पहुंचने में महीने भर का समय लग जाता है. हमारे साथी किसान, जिन्होंने 22 मार्च को प्रापण केंद्र में अपने उपज बेचे हैं, अब तक जून में भी उन्हें पैसे नहीं मिल पाए हैं.

नोटबंदी के ठीक बाद, कर्नाटक और तमिलनाडु में टमाटर के किसानों को और महाराष्ट्र और गुजरात में प्याज के किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि कीमतों में 60-85 फीसदी की गिरावट आई. छह महीने बाद थोड़ी राहत के साथ, किसानों की हड़ताल और कृषि बाजारों के अस्त-व्यस्त होने के साथ नोटबंदी के इस प्रयोग ने परिस्थितियों को और बिगाड़ना शुरू कर दिया है. रिज़र्व बैंक ने स्वीकार किया कि नोटबंदी के दौरान कम बिक्री से मूल्य में गिरावट आई है और इसका प्रभाव जारी है.

7 जून 2017 को आरबीआई के बयान में कहा गया है, मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि क्षणभंगुर प्रभाव वाले फलों और सब्जियों, दालों और अनाजों के संबंध में अतिरिक्त आपूर्ति शर्तों के साथ उलझा हुआ है और इस पर मुख्य खाद्य पदार्थों से संबंधित मूल्य का निर्धारण टिका हुआ है. कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे समय में, लांडे जैसे किसानों पर ऋण का बोझ बढ़ता है.

महाराष्ट्र में 57 फीसदी खेतीहर परिवार ऋण के बोझ तले दबा हुआ है. नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन के 2013 के परिवारों के परिस्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण के मुताबिक, इस संबंध में भारत के लिए आंकड़े 52 फीसदी हैं. इस ऋण के परिणाम व्यापक हैं. वर्ष 2015 में किसी अन्य राज्य की तुलना में महाराष्ट्र में अधिक किसानों ने आत्महत्या की है. आंकड़े 4,291 हैं, जो कि वर्ष 2014 के 4,004 के आंकड़ों से 7 फीसदी ज्यादा हैं. 1,569 के आंकड़ों के साथ कर्नाटक दूसरे और 1,400 के आंकड़ों के साथ तेलंगाना तीसरे स्थान पर है. इधर उत्तर प्रदेश की नई सरकार ने 30,792 करोड़ रुपए के कृषि ऋण को माफ कर दिया है, जिससे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों पर भी दबाव बन रहा है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ऐसा करने से इंकार कर रहे हैं. लेकिन उनकी सरकार के गठबंधन सहयोगी दल शिवसेना अन्य दलों के साथ राजनीतिक आंदोलन की तैयारी कर रही है. इससे उन्हें राज कोष पर विचार करना मुश्किल हो सकता है.

आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने 6 अप्रैल, 2017 को आशंका जताई है कि एक कृषि ऋण माफी भविष्य के उधारकर्ताओं को कर्ज न चुकाने के लिए प्रोत्साहन देता है. यह नैतिक जोखिम पैदा करता है और अंततः राष्ट्रीय बैलेंस शीट को प्रभावित कर सकता है. राजकोषीय विवेक और कृषि संकट के बीच संतुलन जारी रहेगा, लेकिन यह अनिश्चित कृषि जरूरतों के लिए हमेशा बंधक का काम करेगा।

## 52 फीसदी भारतीय किसानों के पास सिंचाई की सुविधा नहीं

अधिकतर ग्रामीण भारत में बुनियादी समस्या यह है कि सिंचाई के फैलाव के बावजूद, भारत के 52 फीसदी खेत बारिश पर निर्भर हैं, जिस पर जलवायु परिवर्तन के इस दौर में कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता.

क्लच ऑफ इंडियन एंड ग्लोबल स्टडीज के अनुसार, मध्य भारत में अत्यधिक बारिश की घटनाएं बढ़ रही हैं और स्थानीय और विश्व मौसम में जटिल परिवर्तनों के एक भाग के रूप में मध्यम और वर्षा कम हो रही है. ग्रामीण महाराष्ट्र में 2014 और 2015 के सूखे को 2016 के भारी बारिश ने कम किया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों ने भी बाढ़ का सामना किया है. अनिश्चित मौसम किसानों को सही सलाह देने के लिए सरकारी विस्तार प्रणालियों की क्षमता को प्रभावित करता है.

विदर्भ के किसान लांडे कहते हैं, सरकार ने हमें खरीफ (जुलाई से अक्टूबर) के मौसम में और अधिक तूर उपजाने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि इन फसलों के लिए पानी की खपत कम और मांग उच्च है. पिछले तीन सालों में हमें इतनी हानि का सामना नहीं करना पड़ता, अगर वहां सिंचाई

की उचित व्यवस्था होती. वर्ष 2015-16 राज्य कृषि रिपोर्ट के अनुसार, सिंचाई के छह दशकों के बावजूद, 50 फीसदी से कम या 140 मिलियन हेक्टेयर के भारत का शुद्ध-खेती वाले क्षेत्र का 66 मिलियन हेक्टेयर सिंचित है. भूजल भारत की सिंचाई के दो-तिहाई भूमि के लिए पानी प्रदान करता है, लेकिन अत्यधिक उपयोग से ये स्तर गिर रहा है.

प्रथम पांच वर्षीय योजना (1951-56) से ग्यारहवें (2006 से 2011) तक केंद्र सरकार ने सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर कुल 3.51 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, जैसा 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) की यह रिपोर्ट बताती है. 1 जुलाई, 2015 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच साल (2015-16 से 2019) में 50,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का शुभारंभ किया है. पीएमकेएसवाई का नीति वाक्य है- हर खेत को पानी और मोर क्रॉप पर ड्रॉप. वर्ष 2015-16 में माइक्रो इरगैशन के लिए एक हजार करोड़ रुपए की एक तिहाई (312 करोड़ रुपए) से कम की राशि जारी की गई, जैसा कि इस सरकारी रिपोर्ट से पता चलता है. माइक्रो इरगैशन फाइनांशियल प्रोग्रेस मानिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से अप्रैल 2016 तक, 48.3 करोड़ रुपए या 5 फीसदी से कम, वास्तव में खर्च किया गया था. सरकार ने 2016-17 के माइक्रो इरगैशन के लक्ष्य के रूप में 1,763 रुपए निर्धारित किए हैं, लेकिन परिणाम पर कोई भी आंकड़ा जारी नहीं किया गया है.

माइक्रो इरगैशन कार्यक्रम में 6,51,220 हेक्टेयर या 0.46 फीसदी शुद्ध खेती वाला क्षेत्र शामिल है. ■

feedback@chauthiduniya.com

# चौथी दुनिया इफ़्तार 2017

हर साल की तरह इस साल भी 15 जून 2017 को दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में चौथी दुनिया की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया. इफ्तार पार्टी का आयोजन श्री कमल मोरारका और संतोष भारतीय की तरफ से किया गया. इफ्तार पार्टी में केंद्रीय मंत्री से लेकर विदेशी राजनयिक, सांसद, विभिन्न दलों के नेता, पत्रकारों, मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्धन, जनरल वीके सिंह, पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह, कांग्रेस नेता संजय सिंह, लोजपा नेता रामचंद्र पासवान, जद(यू) के के सी त्यागी, राजद नेता एम ए ए फातमी, समाजवादी नेता सुनीलम, कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री, झारखंड के पूर्व गवर्नर सैयद सिब्ते रजी, जस्टिस (रिटायर्ड) ए एम अहमदी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री एसवाई कुरैशी आदि मौजूद रहे. इस मौके पर मशहूर उर्दू कवि गुलजार देहलवी भी मौजूद रहे.

इफ़्तार पार्टी में भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने भी शिरकत की. देश के जाने-माने पत्रकार कुलदीप नैयर, कमर वहीद नकवी, विनोद अग्निहोत्री, विनीत नारायण, अशोक वानखेड़े, कमर आगा, द राइजिंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी, इफ्तिखार गिलानी, असद रजा, कासिम सैय्यद ने अपनी मौजूदगी से इफ्तार पार्टी की शोभा बढ़ाई.

इस पाक मौके पर जमाते इस्लामी के इंजीनियर सलीम, नुसरत अली, मोहम्मद अहमद एवं अरशद शेख के साथ ही मुस्लिम मजलिसे मुशावरत के नवेद हामीद, अब्दुल हमीद नोमानी, मर्कजी जमियत अहले हदीस के मौलाना असगर अली इमाम मेहंदी सलफी, जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अजीमुल्ला, मिल्ली कौंसिल के सफी अख्तर, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज के डॉक्टर जेड एम खान और मोहम्मद आलम, अल-हिकमा फाउंडेशन के डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, शाह बलीउल्लाह इंस्टीट्यूट के मौलाना अताउर्रहमान कासिम एवं गालिब इंस्टीट्यूट के रजा हैदर, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ग़यूरूल हसन भी मौजूद थे.

सभी फोटो- *अजित कृष्ण*

# लोगों को दबाकर महान प्रधानमंत्री नहीं बन सकते

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

**2019 का चुनाव नजदीक है. अब सरकार के पास वक्त नहीं है. नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बने तीन साल गुज़र चुके हैं. अगले दो साल में वे चुनाव प्रचार में लग जाएंगे. लिहाज़ा वे कोई ऐसा फैसला नहीं लेंगे, जो देश को दीर्घकालिक लाभ पहुंचाए. अब 2019 तक वे लोक-लुभावन फैसले ही लेंगे. मुझे नहीं लगता कि देश को एकजुट रखने के लिए दीर्घकालिक समाधान जैसा परिपक्व फैसला उनके एजेंडे में शामिल है. इसके साथ-साथ वे चुनाव जीतने के लिए कट्टरपंथी विचार का इस्तेमाल करने में भी नहीं हिचकेंगे. कश्मीर की मिसाल ले लें. कश्मीर की समस्या का समाधान करने के लिए वो ताक़त का इस्तेमाल करेंगे और चुनाव जीतने के लिए सेना का इस्तेमाल करेंगे.**

देश की स्थिति ठीक नहीं है. जैसा कि हम सब जानते हैं, ये मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और किसान देश की रीढ़ हैं. लोगों की ऐसी सोच बन गई है कि कृषि क्षेत्र पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है. सारा ध्यान उद्योग और बड़ी योजनाओं ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया है. दुर्भाग्यवश अब समस्याएं बढ़ जाने से किसान तनावग्रस्त हैं. इसका एक स्पष्ट प्रमाण आत्महत्या करने वाले किसानों की बढ़ती संख्या है. बेशक देश के अलग-अलग हिस्सों में किसानों की आत्महत्या के अलग-अलग कारण हैं. उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के कपास किसान समृद्ध हैं, इसके बावजूद वहां आत्महत्याएं हुई हैं. इसके सामाजिक-आर्थिक कारण हैं. लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्रों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि में पैदावार कम है. यहां केवल खेती पर भरोसा कर किसान सम्मानपूर्वक जीवन यापन नहीं कर सकता है. दुर्भाग्यवश मौजूदा सरकार ने दो तरह से किसानों की समस्या में और इजाफा कर दिया. पहला, सत्ता में आने से पहले प्रधानमंत्री ने किसानों की उम्मीदें यह कह कर बढ़ा दीं कि किसान की लागत में 50 प्रतिशत का लाभ जोड़ कर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा. सत्ता में आने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि यह मुश्किल काम है. इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 6 वर्षों में किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे. इस वादे को भी पूरा करना लगभग असंभव है. आमदनी दोगुनी करने के दो रास्ते हैं या तो पैदावार दोगुनी कीजिए (कोई भी बता सकता है यह असंभव है) या फिर एमएसपी बढ़ा दीजिए. यूपीए सरकार कीमतों में 80-100 रुपए तक इजाफा करती थी, ये सरकार 10-20 रुपए का इजाफा करती है. इससे किसानों में आशा नहीं जगती है. सरकार दुविधा की स्थिति में है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी वादे को पूरा करते हुए कृषि ऋण माफ़ कर दिया. एक बार फिर अर्थशास्त्री, बैंक, रिज़र्व बैंक के अपने संदेह हैं कि 30 हज़ार करोड़ के ऋण माफ़ करने का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लेकिन समस्या यहीं समाप्त नहीं होती है. अब इसी तरह की मांगें हरेक राज्य से उठने लगी हैं और सरकार का दुर्भाग्य यह है कि अधिकतर राज्य भाजपा शासित हैं. लिहाज़ा उनके पास ये भी बहाना नहीं है.

ऋण माफ़ी का मौजूदा दौर आएगा और चला भी जाएगा. यह समस्या का समाधान नहीं है और यह बात किसानों को भी मालूम है. आपने ऋण तो माफ़ कर दिया, लेकिन कल की आय का क्या? लिहाज़ा जब तक आप एमएस स्वामीनाथन जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले कृषि अर्थशास्त्री की सेवाएं नहीं लेंगे और उनकी रिपोर्ट पर अमल नहीं करेंगे, तब तक कृषि क्षेत्र पर दबाव बना रहेगा. इस समस्या पर कई थिंक टैंक्स ने अपनी रिपोर्ट दी है, लेकिन बदकिस्मती से अखबारों की सुर्खियां कॉर्पोरेट सेक्टर और आधारभूत ढांचे की योजनाएं बटोर लेती हैं. किसान कभी चर्चा में नहीं आते हैं. इसके बावजूद अनाज की पैदावार में लगातार इजाफा हो रहा है. इसका मतलब यह नहीं कि हम आश्वस्त हो जाएं. आबादी बढ़ रही है और आगामी 10-20 वर्षों में हम अधिक मुसीबत में पड़ जाएंगे. ऐसे में दुनिया का कोई भी देश हमें



उस मुसीबत से निजात नहीं दिला सकता है क्योंकि हम दुनिया की आबादी के छठवें भाग हैं. यदि हम अपने लिए अनाज नहीं उपजा सकते हैं, तो हमें कोई खाना नहीं दे सकता. जहां तक अमेरिका का सवाल है तो हम जानते हैं कि उन्होंने किस कीमत पर हमें अनाज दिया था. हमारी संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी. ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं. मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपना दिल बड़ा कर अलग-अलग विचारधारा के लोगों, जिसमें वामपंथी, दक्षिणपंथी और मध्यमार्गी विचार के लोग शामिल हैं, से चर्चा करते और अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञों के साथ-साथ उन अर्थशास्त्रियों से भी विचार-विमर्श करते, जो उनसे असहमत हैं, जिससे एक आम सहमति बनती. लेकिन मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि हम एक मुश्किल दौर की ओर कदम बढ़ा रहे हैं.

दूसरी समस्या यह है कि 2019 का चुनाव नजदीक है. अब सरकार के पास वक्त नहीं है. नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बने तीन साल गुज़र चुके हैं. अगले दो साल में वे चुनाव प्रचार में लग जाएंगे. लिहाज़ा वे कोई ऐसा फैसला नहीं लेंगे, जो देश को दीर्घकालिक लाभ पहुंचाए. अब 2019 तक वे लोक-लुभावन फैसले ही लेंगे. मुझे नहीं लगता कि देश को एकजुट रखने के लिए दीर्घकालिक समाधान जैसा परिपक्व फैसला उनके एजेंडे में शामिल है. इसके साथ-साथ वे चुनाव जीतने के लिए कट्टरपंथी विचार का इस्तेमाल करने में भी नहीं हिचकेंगे. कश्मीर की मिसाल ले लें. कश्मीर की समस्या का समाधान करने के लिए वो ताक़त का इस्तेमाल करेंगे और चुनाव जीतने के लिए सेना का इस्तेमाल करेंगे. यह बहुत ही सतही राजनीति है. बेशक इस काम के लिए आरएसएस उनकी सराहना करेगा. व्यापारी वर्ग, बनिया और दक्षिणपंथी लोग समझेंगे कि वे एक महान प्रधानमंत्री हैं. लेकिन महान प्रधानमंत्री लोगों को मारकर या उनपर दवाब बनाकर महान नहीं बनता. यहां मैं ये ज़रूर कहूंगा कि श्री मोदी विश्व हिन्दू परिषद या बजरंग दल में शामिल लोगों से बेहतर हैं. उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, जिसकी इस संदर्भ में मैं आलोचना कर सकूं. लेकिन मैं एक सवाल जरूर पूछूंगा. हम आईएस या तालिबान आदि के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम भारतीय मुसलमान होंगे, जो आतंकवादी बनते हैं. मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों है? इसका जवाब यह है कि जिस तरह से देश 70 साल तक चला है, उसमें मुसलमानों ने यह महसूस नहीं किया है कि उनके साथ भेदभाव हुआ, वे असुरक्षित या निराश हैं (हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि वे बहुत संपन्न नहीं हैं). देश गरीब है, इसलिए वे भी गरीब हैं. बीफ, गाय-भैंस या मंदिर-मस्जिद के नाम पर फिलहाल वे जो कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, यदि यह जारी रहा, तो आगामी 20 वर्षों में हम देखेंगे कि भारतीय लड़के आईएस में भर्ती होने लगेंगे. उन्हें ये अहसास नहीं होता है कि ये उन लड़कों की गलती नहीं है या उन मुसलमानों की गलती नहीं है, यह हमारी गलती है यानि जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग बहुसंख्यक हैं. इन्हें यह अवश्य समझना चाहिए कि जब विभाजन हो रहा था, तब जिन्ना ने कहा था कि हमारी तरफ हिन्दू होंगे और उनकी तरफ मुस्लिम होंगे और दोनों की सुरक्षा के लिए हम उनके साथ अच्छा सुलूक करेंगे. हालांकि यह पाकिस्तान में नहीं हो सका, वहां से हिन्दुओं को भगा दिया गया, लेकिन भारत ने अपने वादे को पूरा किया. हमने मुसलमानों के साथ ठीक-ठाक व्यवहार किया है. आज भी हमारा संविधान किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है. ये लोग इसे पसंद नहीं करते हैं. मुझे नहीं मालूम कि आरएसएस और उनके घटक क्या चाहते हैं? उनका कहना है कि बंटवारा एक गलती थी. मैं उनसे पूछता हूं कि मान लीजिए बंटवारा नहीं हुआ होता, तो आज आप 15 प्रतिशत मुसलमानों को संभाल नहीं पा रहे हैं, तब 30 प्रतिशत मुसलमानों को कैसे संभाल लेते?

दरअसल आएसएस के लोग विभाजन नहीं चाहते थे, वे मुसलमानों को दबा कर रखना चाहते थे. वे चाहते थे कि मुस्लिमों पर हिन्दू वर्चस्व बना रहे. क्या उन्होंने हिन्दुओं से पूछा? हम सभी हिन्दू हैं. हमें हिन्दू होने पर गर्व है. मैं गर्व करता हूं कि मैं हिन्दू हूं और मैं एक सेक्युलर हिन्दू हूं. मेरा धर्म सिखाता है कि किसी के साथ भेदभाव मत करो. इस बात का उन्हें एहसास नहीं है. उनके शासन का तीन साल बीत गया है, दो साल अभी बाक़ी है. यदि वे एक बार फिर जीत जाते हैं और इसी एजेंडे को लागू करने की कोशिश करते हैं तो देश दिनोंदिन और गर्त में चला जाएगा. हमें आशा करनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो. ■

feedback@chauthiduniya.com

# कश्मीर में कट्टरता के मिथक

शुजात बुख़ारी

पिछले कुछ महीनों से कश्मीर में दुष्प्रचार हो रहा है कि वहां ग्राउंड पर जो कुछ भी हो रहा है, वह कथित तौर पर इस्लामीकरण का प्रत्यक्ष परिणाम है. ऐसे विशेषज्ञ (एक्सपर्ट्स) यह कहते हैं कि कश्मीर वहाबीकरण के चंगुल में है. ये सलफी विचारधारा के मानने वाले हैं, जिन्हें कश्मीर में अहले हदीस के नाम से जाना जाता है. वहाबियत, अठारहवीं सदी के धर्मविज्ञानी मुहम्मद इब्न अब्द अल-वहाब द्वारा नजद 'सऊदी अरब' से शुरू किया गया एक धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था. इसके अनुयायी मुख्य रूप से अरब में हैं, कतर में सबसे ज्यादा 48 प्रतिशत हैं. लेकिन हाल में वहाबियत का उपयोग कश्मीर के संदर्भ में अधिक हो रहा है. किसी को भी ये आश्चर्य हो सकता है कि क्या सचमुच कश्मीर इस विचारधारा का केंद्रबिंदु है.

ये विशेषज्ञ, विशेष रूप से टीवी चैनलों पर, सहजता के साथ इस्लाम से जुड़ी एक राजनीतिक समस्या को चित्रित करने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं. जब जामिया मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के बाद कुछ बिगड़ैल बच्चों द्वारा आईएसआईएस का झंडा लहराया जाता है, तो यह घटना सुर्खियों में आ जाती है.

इसे कोई नकार नहीं सकता है कि पिछले कुछ साल में अहले हदीस की लोकप्रियता बढ़ी है और यह दुनिया भर में होने वाले परिवर्तनों का नतीजा है. लेकिन क्या समाज के इस वर्ग के लोगों ने उस राजनीतिक संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई है जो 27 वर्षों से चली आ रही है? नहीं. कश्मीर का सशस्त्र संघर्ष 1980 के दशक के अंत में जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने शुरू किया था. यह सेकुलर विचारधारा के लिए जाना जाता है और इसका लक्ष्य 1947 वाले जम्मू-कश्मीर का एकीकरण करना था. इसे 1990 में हिज्बुल मुजाहिदीन और अन्य संगठनों के जरिए आगे बढ़ाया गया. इन संगठनों ने कश्मीर संघर्ष को इस्लाम और पाकिस्तान से जोड़ा. इन संगठनों की संख्या बढ़ती गई. समाज के कई हिस्सों के लोग, जो नई राजनीतिक स्थिति में खुद को हाशिए पर पाते थे, इस सशस्त्र विद्रोह में शामिल होते गए. तहरीक-उल-मुजाहिदीन एक संगठन था, जो जाहिर तौर पर अहले हदीस की सशस्त्र शाखा थी. लेकिन दोनों ने इस वास्तविकता को कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया था. दिलचस्प बात यह है कि पिछले दस साल में एक भी युवा, जिसने किसी मदरसे या दारूल उलूम से अध्ययन किया हो, आतंकवादी संगठनों में शामिल नहीं पाया गया. यह सबको पता था कि अपना राजनीतिक अस्तित्व सुनिश्चित करने और अपने कैडर्स की सुरक्षा के लिए कुछ छोटे संगठनों को लॉन्च किया गया था.

अहले हदीस आंदोलन कश्मीर के लिए नया नहीं है. यह माना जाता है कि इसके द्वारा चलाए जाने वाले मस्जिदों की संख्या 1990 के 500 से बढ़कर 2017 में 900 हो गई है. यह मुख्य रूप से सऊदी अरब द्वारा वित्त पोषित है. इस पर गृह मंत्रालय द्वारा निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि अहले हदीस से जुड़े संस्थानों में से कुछ ऐसे हैं, जिन्हें विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम प्रमाणपत्र दिए गए हैं.

कश्मीर घाटी का आंदोलन 120 साल पुराना है. श्रीनगर में सबसे पहली अहले हदीस मस्जिद 1890 में बनाई गई थी. इसे शोपिया के रहने वाले अनवर शाह शोपियानी ने बनवाया था. वे तत्कालीन अविभाजित पंजाब के सलफी आंदोलन से प्रभावित थे. कश्मीर में अहले हदीस को प्रचारित-प्रसारित करने वाले लोग मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, अबुल कासिम बनारसी, अब्दुल अजीज रहीमाबादी जैसे विद्वानों से प्रभावित हुए. दरअसल मुख्य इस्लामिक आंदोलन, जैसे जमात-ए-इस्लामी, अहले हदीस और बरेलवी, देश के अपने पीरों से प्रभावित हुए हैं. कश्मीर में अहले हदीस ने अलगाव-वादी आंदोलन में ज्यादा भूमिका नहीं निभाई है. हालांकि यह संयुक्त हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हिस्सा था. 2003 में यह उससे अलग हो गया था. उसके बाद यह किसी भी अन्य गुट में शामिल नहीं हुआ. इसके एक प्रेसीडेंट, मौलाना शौकत की हत्या के बाद इसने अपनी गतिविधियां सीमित कर लीं. तब से इसे किसी भी राजनीतिक आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाते नहीं देखा गया है.

लेकिन जिस तरह से वहाबीकरण की कहानी बुनी जा रही है, इससे लग रहा है कि यह कश्मीर पर कठोर नीति अपनाए जाने की रणनीति का हिस्सा है. सुशील पंडित एक कश्मीरी पंडित और राजनैतिक टिप्पणीकार हैं. हालियों दिनों में कश्मीरियों की मुसीबतों के संदर्भ में एक पैनलिस्ट से कहा था कि अभी और मुसीबतें आने वाली थीं. इसी तरह, भाजपा के एक प्रवक्ता कश्मीर की आजादी के आंदोलन से चिंतित दिखे और उन्होंने श्रीनगर से आने वाले एक अन्य पैनलिस्ट से कहा कि कहां है आपकी आजादी का आंदोलन? इसे तो सलफी इस्लाम ने हाइजैक कर लिया है. दूसरे शब्दों में, इसका मतलब यह होगा कि भाजपा को ऐसे किसी स्वतंत्र आन्दोलन से आपत्ति नहीं होगी, अगर वो पाकिस्तान और इस्लाम से अलग हो.

कश्मीर को 1586 से ही सियासी तौर पर कमजोर बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, जब मुगल सम्राट अकबर ने अंतिम संप्रभु शासक यूसुफ शाह चक को अपदस्थ कर दिया. उसी समय से लोग संघर्षरत हैं. इस संघर्ष में उन्होंने आक्रमणकारी मुस्लिम और गैर मुस्लिम शासक के बीच भेदभाव नहीं किया. आज भी सैयद अली गिलानी, मीरवाइज फारूक और यासीन

**कश्मीरियों को अपने पर गर्व है, यहां तक कि अपने हिंदू अतीत पर भी. हुर्रियत नेता प्रो. अब्दुल गनी भट तो कश्मीर में भारत के ब्राह्मणों और कश्मीर के ब्राह्मणों के बीच लड़ाई का वर्णन भी करते हैं. वे कहते हैं कि हम कश्मीरी सारस्वत ब्राह्मण हैं, भारतीय ब्राह्मण लक्ष्मी ब्राह्मण हैं, हम उन पर भारी पड़ेंगे. शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने महाराजा हरि सिंह के भारत में विलय का समर्थन किया और द्वि-राष्ट्र सिद्धांत की मुखालफत की. इस सिद्धांत के तहत जम्मू-कश्मीर स्वत: पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता. लेकिन सच्चाई जल्द सामने आ गई, जब उन्हें (शेख अब्दुल्ला को) 1953 में अपमानित कर सत्ता से बेदखल कर दिया गया.**

मलिक सलफी या वहाबी विचारधारा को नहीं मानते. गिलानी एक ज्ञात पाकिस्तान समर्थक हैं, लेकिन वे आईएसआईएस और अलकायदा की निंदा करने वाले पहले नेता हैं. उन्होंने हमेशा कहा है कि लोगों की इच्छाएं ही काम करने के लिए प्रेरणा देती हैं. इसका कारण यह है कि कश्मीरियों ने धर्म के साथ राजनीति का मिश्रण करने से हमेशा परहेज किया है. हिज्ब कमांडर ज़ाकिर मूसा के इस्लामी खलीफा के विचार को इनलोगों ने पूर्ण रूप से अस्वीकार कर यह साफ कर दिया है. इस्लामीकरण पर बात करने वाले उन आतंकवादियों के लिए कश्मीर युद्ध क्षेत्र क्यों बन गया है? इसका कारण यह है कि दिल्ली ने राजनीतिक मुद्दे पर हमेशा नकारात्मक रवैया अपनाया, जिसकी वजह से कश्मीरियों द्वारा हिंसा से अहिंसा की ओर जाने के क्रम में जो रिक्त स्थान बना, उसका इस्तेमाल इन तत्वों ने किया.

कश्मीरियों को अपने पर गर्व है, यहां तक कि अपने हिंदू अतीत पर भी. हुर्रियत नेता प्रो. अब्दुल गनी भट तो कश्मीर में भारत के ब्राह्मणों और कश्मीर के ब्राह्मणों के बीच लड़ाई का वर्णन भी करते हैं. वे कहते हैं कि हम कश्मीरी सारस्वत ब्राह्मण हैं, भारतीय ब्राह्मण लक्ष्मी ब्राह्मण हैं, हम उन पर भारी पड़ेंगे. शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने महाराजा हरि सिंह के भारत में विलय का समर्थन किया और द्वि-राष्ट्र सिद्धांत की मुखालफत की. इस सिद्धांत के तहत जम्मू-कश्मीर स्वत: पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता. लेकिन सच्चाई जल्द सामने आ गई, जब उन्हें (शेख अब्दुल्ला को) 1953 में अपमानित कर सत्ता से बेदखल कर दिया गया. लोगों ने महसूस किया कि नई दिल्ली का इरादा नेक नहीं था.

यहां तक कि अगर कोई इस्लामीकरण की बात को मान भी लेता है, तो सवाल ये उठता है कि पिछले 4 सालों में केवल 100 कश्मीरी ही आतंकवादी क्यों बने, जबकि 1990 में इनकी संख्या 15 हजार थी. पुलिस अधिकारी स्वयंप्रकाश पानी, जो अभी दक्षिण कश्मीर में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हैं, ने कट्टरपंथ के मिथक का पर्दाफाश किया. 1 जून 2017 को हिन्दुस्तान टाइम्स में पानी लिखते हैं, दूसरा मिथक यह है कि ये सभी रंगरूट कट्टरपंथी युवा हैं. अधिकतर मामलों में, आतंकवाद में शामिल होने का कारण साथियों से संपर्क होना देखा गया है न कि कट्टरपंथी सोच. बेशक, आतंकवादी गुट में शामिल होने के बाद, वे कभी-कभी सोशल मीडिया पर रेडिकल (कट्टरपंथी) विचार व्यक्त करते हैं, जो कुछ मामलों में एक शक्तिशाली हथियार बन जाता है. इसे हिंसा को सही ठहराने, ध्यान खींचने और उच्च नैतिक आधार प्रदान करने के तौर पर देखा जाता है.

यह कट्टरता राजनीतिक है. अधिकतर कश्मीरियों का तर्क है कि यदि कश्मीर में धार्मिक भावना है, तो भाजपा सरकार के अधीन शेष भारत में जो कुछ हो रहा है, उसे देखते हुए इसे जायज ठहराया जा सकता है. चिंता ये है कि सरकार की कोशिश, जो टीवी द्वारा समर्थित है, कश्मीर को इस तरह के कट्टरपंथ की तरफ धकेल रही है, ताकि राजनैतिक समाधान की बात न की जा सके. ■

*-लेखक राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं.*

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

# जब तोप मुक़ाबिल हो



## सरकार की प्राथमिकता में नहीं हैं किसान

किसानों का सवाल पिछले 60 साल में हर गुजरते दिन के साथ महत्वपूर्ण होता चला गया है, लेकिन किसी सरकार ने किसानों की समस्याओं को कभी अपनी प्राथमिकता में नहीं रखा. लोग ये मानते थे कि किसान कभी संगठित नहीं हो सकते हैं. किसान कभी अपनी मांगों को लेकर जोर नहीं दे सकते हैं, दबाव नहीं डाल सकते हैं. इसका कारण हर राजनीतिज्ञ और नौकरशाह को पता था कि किसान कभी संगठित नहीं हो सकते. उनकी इसी अनदेखी ने देश के किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया. एक दौर था जब किसानों के कई नेता हुआ करते थे, जिनमें महेंद्र सिंह टिकैत प्रमुख थे. टिकैत साहब ने मेरठ कचहरी को महीनों घेर कर किसानों को संगठित किया और पहली बार किसानों की शक्ति का एहसास कराया. दक्षिण में नंजू स्वामी थे. टिकैत के देहावसान के बाद पूरा किसान आंदोलन कम से कम उत्तर भारत में असंगठित हो गया. सरकारों का रवैया नहीं बदला, राजनीतिक दलों का रवैया नहीं बदला, नौकरशाहों का रवैया नहीं बदला और अब किसान निराशा के दौर में पहुंच गए हैं. उसने बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं करनी शुरू कर दीं. आत्महत्याओं की जड़ में गांव का सूदखोर नहीं था, बल्कि बैंकों का सूद था, बैंकों का दबाव था, खेती का अलाभकारी होना था और खेती का मूल्य न मिलना था. किसान के पास खेती के अलावा आय का कोई दूसरा साधन नहीं होता है. सारे देश में एक सरल तरीका निकला कि समस्या से बचने के लिए आत्महत्या कर लो. ये आत्महत्याएं इतनी बढ़ गईं कि धीरे-धीरे किसानों के भीतर भी अपने साथी की मौत की संवेदना समाप्त होने लगी. ये दौर कई साल चला, लेकिन अब जाकर किसानों ने दोबारा अपने हक के लिए लड़ने का फैसला किया है. किसानों ने धीरे-धीरे ये निर्णय लेना शुरू कर दिया कि वो उतनी ही फसल उगाएंगे, जितनी फसल उनके परिवार के भरण-पोषण के लिए काफी है. किसान अपनी जमीन को परती छोड़ देने का फैसला लेने लगा और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र, खासकर औरंगाबाद और नासिक के किसानों ने की. उन्होंने फसल का दाम नहीं मिलने के विरोध में सड़क पर टमाटर फेंक दिए, हजारों लीटर दूध फेंक दिया, फसलों का भाव नहीं मिलने के विरोध में सड़कें जाम कीं. महाराष्ट्र में किसानों के सवालों को लेकर सड़कों पर बड़े-बड़े जुलूस निकले, लेकिन न राज्य सरकार चेती और न ही केन्द्र सरकार.

किसानों का ये दर्द मध्यप्रदेश पहुंच गया. एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा था और दूसरी तरफ आत्महत्याएं हो रही थीं. अब किसानों के बीच इस बात की चर्चा चल रही है कि आखिर हम सरकार से मांगें, तो क्या मांगें. किसान संगठित नहीं हैं. कई सारे किसान संगठन हैं. उनकी अपनी स्थानीय मांगें हैं, पर राष्ट्रीय स्तर पर किसान क्या मांग करे. मेरी कई किसान नेताओं से बात हुई. उस बातचीत के बाद मैं ये समझा कि किसान अपनी मांगों के लिए अपने को संगठित करने का फैसला ले चुका है. वे सरकार पर दबाव डालने के तरीके भी तलाश रहे हैं. वे अब अपनी खेती को लाभकारी बनाने के कई तरीके भी सरकार को सुझाना चाहते हैं, जिनमें पहला तरीका है कि सरकार एक बार देश के किसानों का कर्ज माफ करे. जितना कर्ज सरकार बड़े पूंजीपतियों का बैंकों के जरिए माफ कर देती है, जिस पैसे को लेकर वो विदेश भाग जाते हैं, चाहे वो एनपीए के रूप में हो या सीधी कर्ज माफी हो या वन टाइम सेटलमेंट हो, लेकिन किसान का दो-तीन लाख रुपए का कर्जा माफ करने में सरकार को पसीने आ जाते हैं. सरकार तरह-तरह के बहाने बनाती है. जहां घोषणा कर देती है, वहां भी कर्ज माफी अमल में नहीं आती. तीन लाख के लिए एक किसान अपनी जान दे देता है. शायद इसलिए किसान ये मांग करना चाहते हैं कि देश में एक बार किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो जाए, लेकिन कर्जा माफ होना उनकी समस्याओं का हल नहीं है. इसी के साथ देश के हर ब्लॉक में, उस ब्लॉक में पैदा होने वाली प्रमुख फसल पर आधारित उद्योग धंधा लगे. किसान सरकार से उद्योग लगाने के लिए पैसे नहीं मांग रहे हैं. उनका कहना है कि सरकार ऐसी नीति बनाए कि कोई सरकारी अधिकारी, पुलिस उस ब्लॉक में पैदा होने वाली प्रमुख फसल पर आधारित उद्योग लगाने में अड़ंगा न डाल सके. किसान ये भी मांग करना चाहते हैं कि उस उद्योग को लगाने में प्राथमिकता के आधार पर बैंक से कर्ज मिले और जिसकी ब्याज दर सिर्फ दो प्रतिशत हो. इस ऋण को लौटाने की अवधि दस साल हो. इसका परिणाम ये होगा कि किसान को फसल सिर्फ 10 किलोमीटर की यात्रा कर अपने ब्लॉक तक ले जाना होगा. वहां उपलब्ध औद्योगिक इकाई को फसल बेचनी होगी और वह खुशी-खुशी अपने घर चला जाएगा. फिर किसान या कृषि आधारित उद्योग लगाने वाले उस व्यक्ति को सामान बेचने बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि तब छोटे या बड़े व्यापारी उस ब्लॉक में आकर सामान सीधे खरीद लेंगे. इसमें केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का एक पैसा नहीं जाता है. इसमें बैंक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर जोर दें. किसान अपना उद्योग स्वयं लगा ले. खेती के साथ-साथ उसकी फसल का पैसा उसे मिले और उसके बच्चों को उन उद्योग धंधों में नौकरी मिल जाए. किसान अपनी इन मांगों के समर्थन में सारे देश में सम्मेलन करने वाले हैं और सरकार से ये कहने वाले हैं कि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको देश में एक मजबूत किसान क्रांति का सामना करना पड़ेगा.

> सरकार ये क्यों नहीं समझती कि तीन लाख, चार लाख, पांच लाख रुपए की वजह से एक किसान आत्महत्या करता है और दूसरी तरफ वो अरबों करोड़ रुपए विदेशों में बहुत सारे देशों को दान में दे रही है. जहां वो पैसा वहां के विकास में नहीं लगता, बल्कि वहां की भ्रष्ट व्यवस्था उस पैसे को खा जाती है. भारत सरकार जिन अफ्रीकी देशों को पैसा दे रही है, वहां पर भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है. वहां भारत से हजार गुना ज्यादा भ्रष्टाचार है और शायद इस पैसे को देने में भारतीय विदेश सेवा या भारतीय बैंकिंग सेवा के अधिकारियों का भी एक बड़ा हिस्सा होता है. सरकार को चाहिए कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश को दो साल तक सहायता न दे.

किसानों ने अपने वोट से नरेन्द्र मोदी को भारी बहुमत से जिताया है. इस आशा से जिताया है कि उन्हें उनकी फसल का लागत से 50 प्रतिशत अधिक मूल्य मिलेगा. प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा देश के हर हिस्से में जाकर की थी, शायद इसलिए कि वो किसानों का वोट चाहते थे. किसान अब उन्हें याद दिला रहे हैं कि आप उस वादे पर भी अमल कीजिए. आपने कर्ज माफी का वादा किया था, उस पर भी अमल कीजिए और तत्काल कृषि आधारित उद्योग धंधों को बढ़ाने का एक बड़ा फैसला लीजिए.

सरकार ये क्यों नहीं समझती कि तीन लाख, चार लाख, पांच लाख रुपए की वजह से एक किसान आत्महत्या करता है और दूसरी तरफ वो अरबों करोड़ रुपए विदेशों में बहुत सारे देशों को दान में दे रही है. जहां वो पैसा वहां के विकास में नहीं लगता, बल्कि वहां की भ्रष्ट व्यवस्था उस पैसे को खा जाती है. भारत सरकार जिन अफ्रीकी देशों को पैसा दे रही है, वहां पर भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है. वहां भारत से हजार गुना ज्यादा भ्रष्टाचार है और शायद इस पैसे को देने में भारतीय विदेश सेवा या भारतीय बैंकिंग सेवा के अधिकारियों का भी एक बड़ा हिस्सा होता है. सरकार को चाहिए कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश को दो साल तक सहायता न दे. विदेशों में अरबों करोड़ रुपए दान के रूप में भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ाए, बल्कि उस पैसे का इस्तेमाल भारत में किसानों के लिए उद्योग धंधे लगाने में करे.

दरअसल किसानों की समस्याओं का हल कर्ज माफी नहीं है, लेकिन कर्ज माफी तात्कालिक रूप से जान बचाने का एक साधन जरूर है. अफसोस की बात है कि सरकार ने इसे लेकर कभी सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई. किसी भी सरकार ने नहीं बुलाई. सरकार ने नीति-निर्माताओं से कभी नहीं कहा कि वो किसान को केन्द्र में रखकर नीति बनाएं. सरकार ने बड़े उद्योगपतियों से कभी नहीं कहा कि वो अपने लाभ में से एक हिस्सा किसानों के कोष के लिए भी बनाएं. सरकार ने कभी किसान आयोग की बात नहीं की, जिसका संवैधानिक दर्जा हो और जो सरकार को किसानों की हालत के बारे में समय-समय पर जानकारी दे सके.

लेकिन, अब वक्त आ गया है कि सरकार किसानों के लिए कुछ करे. किसान बड़ी आशा से इस समय केन्द्र सरकार की तरफ देख रहे हैं कि उनकी समस्याओं के हल के लिए केन्द्र सरकार कुछ लेकर आएगी, पर केन्द्र सरकार ने तो मखौल बना दिया. उसने प्रचार करना शुरू कर दिया कि उसने मंत्रिमंडल में किसानों को सस्ती दर पर बैंकों से कर्ज दिलवाने का फैसला लिया है. ये सब तो आठ साल से चल रहा है. उसमें कौमा, फुलस्टॉप भी नहीं बदला है. तब केन्द्र सरकार का कौन मंत्री है, जो इतना बड़ा झूठ सारे देश में फैला रहा है. क्या उसे लगता है कि किसानों को इस बात का पता नहीं चलेगा कि आपने उनके लिए कुछ नहीं किया है? इसलिए अभी वक्त है कि किसानों के लिए कुछ सार्थक कीजिए जिससे किसानों की जिंदगी में खुशियां लौट सकें, उनकी आत्महत्याएं रुके, उनको उनकी फसल का दाम मिले और साथ ही साथ उनकी फसल को उनकी पहुंच के भीतर उनके ही ब्लॉक में प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए पक्के माल में तब्दील किया जा सके. अगर आज ये नहीं होता है, तो कल देश को और खासकर केन्द्र सरकार को और बहुत सारी राज्य सरकारों को किसानों के उग्र आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है. आज ये विनती है, कल मजबूरी हो जाएगी. तब किसान सारे राजनीतिज्ञों को एक ही तराजू पर तौलने लगेगा और उन्हें एक ही नजर से देखने लगेगा कि ये उनके हितों के दुश्मन हैं. ये स्थिति न आए, इसके लिए अगर कुछ काम करना है तो आज करना होगा. ■

editor@chauthiduniya.com

# इतना धोखा खाया है कि अब गोकियों की पहचान हो गई है

(12 से 18 जून के अंक में प्रकाशित संपादकीय, जिसका शीर्षक था, '*अपने आस-पास के गोकियों से बचिए*' को कर हमारे एक पाठक ने अपने विचार भेजे हैं. हम उसे यहां प्रकाशित कर रहे है.)



डॉक्टर सबा यूनुस

आपका अख़बार पढ़ रही थी. सभी आर्टिकल अच्छे लगे. फिर आपके कॉलम पर नजर गई. हैडिंग में उल्लेखित शब्द गोकियों को पढ़ कर रुक गई. पहली बार ये लफ्ज़ सुना था तो ये जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर ये गोकी होता क्या है. जैसे-जैसे संपादकीय पढ़ती गई, वैसे-वैसे एहसास होता गया कि इस तरह के लोगों से तो मेरा कई मर्तबा पाला पड़ चुका है. इस हद तक, इतना ज्यादा मैं छली गई हूं कि अब मुझे इन गोकियों की पहचान भी हो गई है.

मैं बहुत भावनात्मक शख्सियत हूं. इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान धोखा कर के भी मेरे आगे अपनी ग़लतियों की रो कर माफ़ी मांग ले, तो मैं उसे माफ़ कर देती थी. लेकिन इन गोकियों ने मेरी भावनात्मक कमजोरी भी ख़त्म कर दी. यानी, जो गोकी होते हैं, उनकी करतूतें आपका विश्वास इंसानों पर से उठा देती हैं. फिर आप कभी किसी और इंसान पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर पाते हैं. अगर आप एक बार भी गोकी के शिकार हुए है तो आगे से आप किसी और इंसान पर भरोसा नही कर पाएंगे.

मैं तो दो तीन बार अपनी शराफत और इंसानियत की वजह से इन गोकियों की शिकार हो चुकी हूं. पर मेरे इन्हीं कड़वे तजुर्बों ने मुझे सही और ग़लत इंसान की परख करना भी सिखा दिया है. अब मैं इंसानों को उनके हाव-भाव और बात करने के तरीको से ही जान लेती हूं कि वह इंसान कैसा हो सकता है.

यानि, मैं कहना ये चाहती हूं कि गोकियों से निपटने का तरीका यही है कि आप उनको अपना राजदार न बनाए. उनको क्या, किसी भी शख्स को अपना राजदार न बनाए. क्यूंकि, क्या मालूम किसी रोज़ आपका सगा भी दगाबाजी को अमादा हो जाए और आपके बताये हुए राज को आपके खिलाफ ही हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लगे और अंत में वह आदमी आपके लिए गोकी बन जाए. आप खुद को कभी भी किसी शख्स के साथ इमोशनली इंवॉल्व न करे, भले ही आपको लगे कि वो आपका गहरा मित्र बन गया है, भले ही वो आपको ये एहसास कराये कि वो आपकी बहुत परवाह करता है. लेकिन फिर भी, कभी भी किसी भी बाहरी शख्स को अपनी ज़िंदगी को बेहद करीब से झांकने मत दीजिए. आपको नहीं पता होता है कि कौन आदमी आपसे क्या चाहता है? आपको ये भी नहीं पता कि कौन किस फ़िराक में है और अपना मकसद साधने के लिए आपसे झूठा अपनापन का महज़ दिखावा कर रहा हो.

> मैं बहुत भावनात्मक शख्सियत हूं. इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान धोखा कर के भी मेरे आगे अपनी ग़लतियों की रो कर माफ़ी मांग ले, तो मैं उसे माफ़ कर देती थी. लेकिन इन गोकियों ने मेरी भावनात्मक कमजोरी भी ख़त्म कर दी. यानी, जो गोकी होते हैं, उनकी करतूतें आपका विश्वास इंसानों पर से उठा देती हैं. फिर आप कभी किसी और इंसान पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर पाते हैं. अगर आप एक बार भी गोकी के शिकार हुए है तो आगे से आप किसी और इंसान पर भरोसा नही कर पाएंगे.



संपादकीय 9

जब तोप मुक़ाबिल हो

अपने आस-पास के गोकियों से बचिए

आर या पार

आदिवासियों के ग़ुस्से की वजह को समझें

इन गोकियों से पाला पड़ने के बाद मैंने एक निष्कर्ष ये निकाला है कि इंसान से ज्यादा खतरनाक कोई प्राणी धरती पर नहीं होता है. इसकी वजह ये है कि इंसानी आदत और तबियत को आप अपने पूरी उम्र बीता देने के बाद भी सही से आंक नहीं सकते हैं. आप ये पता नहीं कर सकते हैं कि कोई इंसान ऊपर से क्या दिखा रहा है और अंदर ही अंदर उसकेमन में क्या चल रहा है. ये बात आप तब तक नहीं जान सकते, जब तक वो इंसान खुद अपना अंदरूनी चेहरा आपके सामने नहीं लाता है.

इसलिए, इंसानों से सावधान रहें, कुछ बातें, कुछ एहसास खुद के साथ ही शेयर करें. यदि आप खुदा या भगवान को मानते हों तो आप अपने दिल की बात उनके साथ शेयर कर ले. लेकिन अपनी ज़िन्दगी की पूरी किताब कभी भी किसी बाहरी शख्स के सामने न खोले. अक्सर वही इंसान गोकियां होते हैं, जो हमारी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल होना चाहते हैं. ये हमारी गलती है कि हम उन्हें अपने अंदर घुस कर हमें ही काटने के लिए, हमें अंदर से बर्बाद करने के लिए, रास्ता मुहैय्या कराते हैं. अगर हम सतर्क रहे और मौका न दे तो कोई भी गोकी हमारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता है.

इसलिए सचेत रहना और भावना में न बहना ही एक मात्र उपाय है, इन गोकियों से बचने का.■

*(लेखिका समाजशास्त्र की प्रोफेसर और सामाजिक कार्यकर्ता हैं)*

feedback@chauthiduniya.com

## सीतापुर में बीच सड़क लुटेरों का तांडव, व्यापारी परिवार की नृशंस हत्या

# क़त्ल क़ानून व्यवस्था का

■ पुलिस से बेहतर थी कामिनी जो आख़िरी दम तक लड़ीं ■ जिला पुलिस गई-गुज़री, एसटीएफ भी नाकारा साबित

संजीव गुप्ता

दुस्साहसिक वारदातों के लिए बदनाम सीतापुर की बदतर कानून व्यवस्था की बदरंग किताब में एक और काला अध्याय जुड़ गया जब छह जून को रात के करीब दस बजे शहर के वीआईपी मोहल्ले में सीतापुर के एक व्यापारी, उनकी पत्नी और बेटे गोली मारकर हत्या कर दी गई और लाखों रुपए लूट लिए गए. डीएम आवास, एसपी आवास और शहर कोतवाली के नजदीक हुई इस सनसनीखेज वारदात ने पुलिस तंत्र की नाकामी उजागर कर दी है.

सीतापुर शहर के सिविल लाइन निवासी सुनील जायसवाल दालों के थोक व्यापारी थे. सीतापुर के राजा बाजार में उनकी सुनील दाल स्टोर के नाम से दुकान है.

आस-पास के कई जनपदों में उनका व्यापार फैला हुआ है. छह जून को सुनील दुकान बन्द करने के बाद अपनी मोटर साइकिल से प्रतिदिन की तरह घर जाने के लिए निकले. उनके घर से करीब चार सौ मीटर दूर शहर कोतवाली, डीएम और एसपी के आवास हैं. सुनील के पास उस दिन की कमाई का रुपया अधिक था जो एक काले रंग की लेदर बैग, मोटर साइकिल की डिग्गी और पैंट की जेब में रखा हुआ था. यह रकम करीब चालीस लाख रुपए बताई जा रही है. रात करीब 09 बजकर 55 मिनट पर वो जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंचे, तीन मोटर साइकिलों पर सवार पांच नकाबपोश सशस्त्र लुटेरों ने पीछे से आकर इन्हें रोक लिया और रुपए से भरा बैग छीनने लगे. कुछ सशस्त्र लुटेरे घर के सामने रोड पर दोनों ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद खड़े थे. बैग न देने पर लुटेरों ने इन्हें लात मारकर मोटर साइकिल सहित जमीन पर गिरा दिया और बैग छीन लिया. चीखने-चिल्लाने पर लुटेरों ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी. चीख-पुकार और गोलियों की आवाज सुनकर पत्नी कामिनी जायसवाल अपने पन्द्रह वर्षीय बेटे रितिक के साथ गेट खोलकर बाहर आईं और निहत्थे ही सशस्त्र लुटेरों से भिड़ गईं. दो लुटेरों को उन्होंने जमीन पर पटक भी दिया, इस अन्य लुटेरे उनकी गर्दन से पिस्टल सटाकर गोली मार दी. मां और बाप को रक्त रंजित तड़पता देख रितिक चीखा और घर के अन्दर भागा तो लुटेरों ने उसकी पीठ में गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए. स्वचालित हथियारों से लैस पेशेवर लुटेरों ने लूट के दौरान जो भी घर से निकला और लूट में बाधक बना, उसी की हत्या कर दी. लुटेरों की सभी गोलियां तीनों के सीने के ऊपर ही मारी गईं, यानि लुटेरे शातिर लुटेरे और शार्प शूटर थे. एक राहगीर ने करीब सौ मीटर दूर खड़ी 100 नंबर की गाड़ी में बैठे पुलिसकर्मियों को सूचना दी, लेकिन उन्होंने अपना इलाका न होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया. खास बात यह थी कि पेशेवर लुटेरों को यह बखूबी मालूम था कि घर के पास सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इस वजह से उन लोगों ने स्ट्रीट लाइट को पहले ही तिरछा करा दिया था और कैमरे के बेहद करीब आए बिना ही वारदात को अंजाम दिया. खबर है कि वारदात के कुछ घंटे पहले कुछ लोग सीढ़ी लेकर सिविल लाइन पहुंचे थे और उन्होंने खम्भे पर चढ़कर व्यापारी के घर के ठीक सामने की स्ट्रीट लाइट को उल्टी दिशा में घुमा दिया था. उनलोगों ने आस-पास की कई स्ट्रीट लाइटों से भी छेड़छाड़ की थी, ताकि रोड पर अंधेरा रह सके और सीसीटीवी कैमरे भी बेअसर रहें. स्ट्रीट लाइटों से छेड़छाड़ करने वाले लोग कौन लोग थे? इसका जवाब न तो विद्युत विभाग के पास है, न नगर पालिका के पास और न पुलिस के पास. पुलिस इसकी छानबीन भी नहीं कर रही है.

सीसीटीवी में वारदात की स्पष्ट रिकार्डिंग हो जाने के बाद भी बेखौफ लुटेरे शहर की सड़कों पर अपनी रेसर बाइकों से फर्राटे भरते रहे और कुछ दूर जाकर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए. शहर के तिराहों और चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी उनकी लोकेशन दिखाने में नाकाम ही साबित हुए हैं. दौलत और शोहरत के धनी इस व्यापारी के परिवार की निर्मम हत्या में पुलिस करीबियों पर शक कर रही है, लेकिन कुछ हासिल करने की दिशा में कुछ नहीं हो रहा है. लुटेरों का मकसद केवल धन लूटना ही नहीं था बल्कि मशहूर दाल व्यापारी और उसके खानदान को नष्ट करना भी था. लेकिन पुलिस को इस एंगल से भी छानबीन करने की फुर्सत नहीं. पुख्ता कानून व्यवस्था का योगी का दावा केवल सत्ता गलियारे की सीमा तक ही सीमित है.

हजारों नाराज व्यापारियों, मजदूरों, सामाजिक संगठनों के कर्ता-धर्ता, अधिवक्तागण और आम लोग घटना के अगले दिन सुबह ही सड़कों पर उतर आए. इस पर सियासत भी होने लगी और यह पूर्व सपा विधायक राधेश्याम जायसवाल और मौजूदा भाजपा विधायक राकेश राठौर के समर्थकों के बीच मारपीट की बदनुमा शक्ल में भी तब्दील हुई. पूर्व विधायक को मौके से उल्टे पांव भागना पड़ा. देर शाम कोतवाली में पूर्व सपा विधायक राधेश्याम जायसवाल के विरुद्ध मुकदमा भी पंजीकृत किया गया. घटना के खुलासे में पुलिस को नाकाम देख कर व्यापारियों ने तीन दिन शहर बन्द का ऐलान भी किया और शहर की सड़कों पर डेरा डाल दिया. सीतापुर के पुलिस अधीक्षक मृगेंद्र सिंह आए दिन यह डायलॉग मारते रहे हैं, 'अपराधी शहर छोड़ दें या भूमिगत हो जाए'. सीतापुर के इस जघन्य वारदात के बाद पुलिस अधीक्षक का डायलॉग जहरीले तीर की तरह उन्हीं को छेद रहा है.

### चिता पर भी सेंक रहे सियासत की रोटी

जनता की अदालत से बेइज्जत करके भगाए कुछ सफेदपोश तिहरे हत्याकांड पर अपनी सियासी रोटियां सेंकने से बाज नहीं आ रहे. धौरहरा के पूर्व कांग्रेसी सांसद एवं केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद, कांग्रेस के पूर्व एमएलसी हरीश बाजपेयी, पूर्व सपा विधायक राधेश्याम जायसवाल, मौजूदा भाजपा विधायक राकेश राठौर जैसे नेता इसमें अग्रणी हैं. सीतापुर से भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ तक जा पहुंचा और व्यापारी परिवार की हत्या करने वाले लुटेरों की गिरफ्तारी की मांग की. इनमें मंडल में जिला प्रभारी एवं मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, जिला प्रभारी मानसिंह, सीतापुर सांसद राजेश वर्मा एवं सदर विधायक राकेश राठौर भी शामिल थे. समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य नरेश अग्रवाल, महोली के पूर्व सपा विधायक अनूप गुप्ता सहित अन्य कई नेता भी पीड़ित परिवार के घर पहुंच कर भावुक होने और दिखने का उपक्रम किया. सामाजिक कार्यकर्ता कुमुदलता कहती हैं कि कामिनी (व्यापारी की पत्नी) बहुत दिलेर महिला थीं, जो लुटेरों से आखिरी दम तक लड़ती रहीं, लेकिन सीतापुर की पुलिस वह महिला भी नहीं है, वह क्या है इसके लिए अब कुछ कहने की जरूरत नहीं. योगी सरकार में मंत्री रहते हुए रीता बहुगुणा जोशी ने स्पष्ट कहा कि व्यापारी परिवार हत्याकांड से प्रदेश की कानून व्यवस्था को कड़ी चुनौती मिली है.

### आंखों में आंसू पर जुबां पर न्याय की मांग

लूट के दौरान मारे गए दाल व्यापारी सुनील जायसवाल की दोनों बेटियां शिवानी व रिचा लखनऊ में रहकर पढ़ाई करने के चलते बच गईं. इस हृदय विदारक घटना के बाद दोनों बहनें अवाक हैं. वे योगी सरकार से मांग कर रही हैं कि हत्यारों को मौत मिले अन्यथा वे फांसी लगा लेंगी. सियासत करने पहुंच रहे हर नेता से दोनों बेटियां न्याय की मांग कर रही हैं. बेटियों के सुलगते सवालों से शासन और प्रशासन दोनों कठघरे में है. बेटियां पुलिस से पूछ रही हैं कि उनके पिता का मोबाइल फोन कहां गायब है? उनके पिता सुनील की हत्या करने के बाद अपराधी उनका मोबाइल ले गए या किसी अन्य व्यक्ति ने मोबाइल गायब कर दिया? एडीजी अभय कुमार प्रसाद ने भी 72 घंटे के अंदर हत्यारों को सलाखों के पीछे करने की बात कही थी, लेकिन उनका दावा भी नेता का बयान ही साबित हुआ.

### हत्याकांड पर व्यापारी समुदाय नाराज़

व्यापारी हत्याकांड और पुलिस की नाकामी के खिलाफ पिछले दिनों सिद्धार्थनगर, सीतापुर, वाराणसी, लखीमपुर, हरदोई व कुछ अन्य जिलों से आए व्यापारियों ने लखनऊ के व्यापारियों के साथ मिल कर राजधानी लखनऊ में गांधी प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों में वैश्य समाज, जायसवाल समाज एवं व्यापार मंडल के सदस्य शामिल थे. इनमें जायसवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय जायसवाल, लखनऊ स्थित मनकामेश्वर मंदिर की महंत स्वामी दिव्या गिरी, विधायक अजय राज, अखिल भारतीय उद्योग मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल, विकास जन कल्याण सेवा समिति के मुख्य संरक्षक विजय गुप्ता, अखिल भारतीय उद्योग मंडल के महामंत्री सुरेश छबलानी, सेंट्रल बार एसोसिएशन के सचिव मनीष जायसवाल, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के अध्यक्ष सतीश गुप्ता, नवयुवक जायसवाल समाज के अध्यक्ष राजेश जायसवाल और वैश्य महासभा के महासचिव राजकुमार गुप्ता समेत सैकड़ों लोगों ने भाग लिया. प्रदर्शनकारियों ने सीतापुर पुलिस के नाकारेपन के आधार पर इस हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराने की मांग की. ■

### अपराधियों ने धो डाला सरकार का दावा

मथुरा में सर्राफा व्यापारियों की हत्या और सीतापुर में दाल व्यापारी के पूरे परिवार की हत्या समेत कई अन्य सनसनीखेज वारदातों ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और योगी सरकार के दावों को धोकर रख दिया है. अखिलेश सरकार की खराब कानून व्यवस्था पर उंगली उठाने वाले भाजपाई अब अपनी कानून व्यवस्था पर झेंप रहे हैं. आम नागरिक तब भी कानून व्यवस्था को लेकर निराश था, अब भी है. सरकार बदलने के कुछ दिन तक तो लगा कि पुलिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े तेवर का कुछ असर है, लेकिन जल्दी ही वह हनक भी जाती रही. अब योगी ही कातर भाव में नजर आने लगे हैं. मुख्यमंत्री ने पहले कहा कि प्रशासनिक तबादलों का असर कानून व्यवस्था पर नहीं पड़ता, लेकिन अब अपनी बात बेअसर होता देख कर वे भी धड़ाधड़ तबादले कर रहे हैं. योगी ने जावीद अहमद को हटा कर सुलखान सिंह को डीजीपी बनाया, लेकिन सुलखान सिंह की ईमानदारी और सख्ती भी पुलिस पर कोई असर नहीं दिखा पाई. तबादलों की सूची पर अब यह भी कहा जाने लगा है कि दागी और नाकारा छवि वाले पुलिस अफसर जुगाड़ बिठाकर अहम तैनातियां पा रहे हैं.

जमीनी सच्चाई यही है कि उत्तर प्रदेश में लोग खराब कानून व्यवस्था से त्रस्त हैं. पुलिस वाले अपने धंधे में व्यस्त हैं. प्रधानमंत्री ने अपने विधायकों और सांसदों को हिदायत दे रखी है कि वे किसी के तबादले की सिफारिश नहीं करेंगे. पीएम की यह हिदायत उनके लिए परेशानी का सबब बन गई है. अफसर भी यह समझ गए हैं कि सांसद विधायक की कोई औकात नहीं रह गई है. प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पिछले दिनों जब मेरठ गए तो उन्हें भाजपा सांसद और विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के रोष का सामना करना पड़ा. समीक्षा बैठक में जब मौर्य ने पूछा कि अपराधियों में भाजपा सरकार का खौफ है या नहीं तो सबने एक सुर में कहा, नहीं. मौर्य से कुछ कहते नहीं बन पड़ा. मथुरा में सर्राफा व्यापारियों की हत्या, सहारनपुर में शब्बीरपुरकांड, रामपुर में मुस्लिम युवकों द्वारा सरेराह लड़की और उसकी मां से अश्लील हरकत की वारदात, हाथरस में पुलिसवालों द्वारा रम्पत्ति को लूटने का मामला और अब सीतापुर में व्यापारी परिवार की हत्या उत्तर प्रदेश में योगी राज के बजाय जंगल राज की पुष्टि कर रही है.

feedback@chauthiduniya.com

## सरकार और प्राइवेट स्कूलों ने मिल कर मार डाला सरकारी स्कूलों को

# किताबें नहीं, ड्रेस ज़रूरी

## उत्तर प्रदेश में उड़ रही हैं सर्व शिक्षा अभियान की धज्जियां

शिक्षा में भी वर्गीय भेदभाव का नायाब नमूना : बुंदेलखंड का एक सरकारी विद्यालय (बाएं) और लखनऊ का आलीशान (प्राइवेट) ला मार्टिनियर स्कूल...

**खूफी यायावर**

उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों की चांदी है और सरकारी स्कूलों की हालत दिन पर दिन और खस्ता होती जा रही है. कैग की रिपोर्ट भी यह कहती है कि 2010 से लेकर 2016 तक प्राइवेट स्कूलों में नामांकन 36.5 प्रतिशत बढ़ा, जबकि सरकारी स्कूलों में नामांकन प्रतिशत करीब 17 प्रतिशत घट गया. कैग की यह रिपोर्ट पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान रखी गई और इस चिंता जताने का प्रहसन भी खेला गया. विधानसभा में चिंता की औपचारिकताओं के बीच यह बात भी सामने आई कि 2012 से 2016 के बीच साढ़े छह लाख बच्चों को पाठ्य पुस्तकें ही नहीं मिलीं, जबकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत फंड की कोई कमी नहीं. स्पष्ट है कि फंड कहां गया. सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) पर खर्च किए गए 1.16 लाख करोड़ रुपए (17.7 अरब डॉलर) के बावजूद यह स्थिति है. स्थिति कितनी शर्मनाक है, यह आप समझ सकते हैं. यूपी के स्कूलों में बिना किताबों के पढ़ाई चल रही है. कमीशनखोरी के चक्कर में सरकारी किताबें नहीं छापी जा सकीं. कुछ स्कूलों में बच्चों को पुरानी किताबों से पढ़ाया जा रहा है. चारों तरफ नारे लग रहे हैं, 'पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया', लेकिन ये नारे व्यवहारिक तौर पर नपुंसक साबित हो रहे हैं. प्रदेश के बच्चे उन किताबों से ही वंचित हैं जो उन्हें सरकार से मुफ्त में दी जाती है. सरकार को बच्चों की किताबों के लिए कोई फिक्र नहीं, लेकिन स्कूल ड्रेस की काफी फिक्र है. सारे सरकारी स्कूलों के ड्रेस बदल दे गए हैं. इसके पीछे भीषण कमीशनखोरी के खेल की चारों तरफ चर्चा है.

योगी सरकार ने प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के ड्रेस में बदलाव और नो-बैग-डे जैसे फार्मूले तो लागू कर दिए, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का कोई भी कारगर नहीं हो रहा. प्रदेश की स्थिति यह है कि ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 में पढ़ने वाले महज 7.2 फीसदी और 5 में पढ़ने वाले 24.3 फीसदी बच्चे ही कक्षा दो के स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं. कक्षा 5 के महज 10.4 फीसदी बच्चे गणित में भाग का सवाल कर सकते हैं. यूपी के तमाम प्राथमिक स्कूल शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं. पांचवीं तक के स्कूलों में बमुश्किल दो से तीन अध्यापक होते हैं. इन अध्यापकों के जिम्मे न केवल पांच कक्षाओं के बच्चों का सिलेबस पूरा कराना होता है बल्कि मिड डे मिल, जनगणना, प्रबंधकीय कामकाज उन्हीं के कंधों पर होता है. ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर स्कूलों में दो से तीन कमरे ही बने हैं, जिनमें पांचवीं तक के बच्चों की पढ़ाई होती है. ज्यादातर स्कूलों में टेबल कुर्सी की व्यवस्था नहीं है, बच्चों को दरी पर बैठाया जाता है. गंदे क्लास रूम और उजड़ी हुई दीवारें प्राथमिक शिक्षा की बदहाली बयान करती हैं. सरकारी स्कूलों में पौने दो लाख शिक्षकों की कमी है. इस तरह देशव्यापी स्थिति देखें तो पांच साल में प्राइवेट स्कूलों में दाखिले में 17 मिलियन छात्रों की बढ़ोतरी हुई तो सरकारी स्कूलों में 13 मिलियन छात्रों का दाखिला कम हुआ. 2010-11 और 2015-16 के बीच 20 राज्यों में सरकारी स्कूलों में छात्रों का नामांकन 13 मिलियन तक नीचे गिर गया, जबकि प्राइवेट स्कूलों ने 17.5 मिलियन नए छात्रों का नामांकन हुआ. एक अध्ययन के अनुसार भारत के सार्वजनिक-विद्यालय शिक्षा संकट के अभूतपूर्व दौर से गुजर रहे हैं.

दूसरी तरफ सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर द्वारा उर्दू सहित भाषा शिक्षकों से सम्बन्धित यूपी-टीईटी परीक्षा निर्धारित मानदंडों के विपरीत कराए जाने के सम्बन्ध में दाखिल जनहित याचिका में राज्य सरकार द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दिए गए हलफनामे से निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई एक्ट) के अनुपालन की बुरी स्थिति सामने आई है. बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रस्तुत हलफनामे के अनुसार आरटीई एक्ट में निजी स्कूलों द्वारा अनिवार्य रूप से दिए जाने वाले प्रवेश के नियम का अनुपालन प्रदेश में पहली बार वर्ष 2013-14 में हुआ जब मात्र 60 छात्रों को निजी स्कूलों में प्रवेश मिला था, जबकि आरटीई एक्ट वर्ष 2009 में ही लागू हो गया था.

इसी प्रकार वर्ष 2014-15 में मात्र 54, 2015-16 में 3,135 तथा 2016-17 में 14,898 छात्रों को निजी स्कूलों में आरटीई एक्ट में दाखिला मिला. हलफनामे में दी गई सूचना के अनुसार इनमें लखनऊ में 2465, बाराबंकी में 23, आगरा में 2005, वाराणसी में 1851 और गोंडा में 66 छात्र थे. वर्तमान अकादमिक वर्ष 2017-18 में अब तक मात्र 13,364 छात्रों का चयन निजी स्कूलों में दाखिले हेतु किया गया है. प्रदेश में हर वर्ष कई लाख छात्र कक्षा एक में प्रवेश लेते हैं, वहीं उनमें मात्र दस हजार छात्रों का निजी स्कूलों में दाखिला अत्यंत निराशाजनक स्थिति है और यह बेसिक शिक्षा विभाग की निष्क्रियता को दिखाता है. मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम- 2009 में 25 प्रतिशत अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए अपने पड़ोस के किसी भी विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क पढ़ने का अधिकार है. शैक्षणिक सत्र 2015-16 में लखनऊ के जिलाधिकारी ने 31 बच्चों के दाखिले का आदेश शहर के जाने-माने सिटी मांटेसरी स्कूल की इंदिरा नगर की शाखा में किया. उच्च न्यायालय में महीनों चली लड़ाई के बाद उन 13 बच्चों के दाखिले का आदेश हुआ, जिनका घर विद्यालय से एक किलोमीटर के दायरे में था. सर्वोच्च न्यायालय के कारण ये बच्चे अभी सिटी मांटेसरी स्कूल में टिके हुए हैं. सीएमएस स्कूल समूह के संस्थापक-प्रबंधक जगदीश गांधी और उनकी शिक्षाविद पुत्री गीता गांधी किंग्डन ने उन बच्चों को अपने स्कूल से निकालने की पूरी कोशिश की.

शैक्षणिक सत्र 2016-17 में सिटी मांटेसरी की विभिन्न शाखाओं में 55 बच्चों के दाखिले का आदेश हुआ लेकिन फिर जगदीश गांधी ने अड़ंगा लगा दिया और एक भी दाखिला नहीं लिया. सिटी मांटेसरी की देखा-देखी भाजपा नेता सुधीर हलवासिया ने अपने विद्यालय नवयुग रेडियंस में 25 बच्चों का, जगदीश गांधी की दूसरी पुत्री सुनीता गांधी ने अपने विद्यालय सिटी इंटरनेशनल में 12 बच्चों का, डॉ. वीरेन्द्र स्वरूप पब्लिक स्कूल महानगर ने 2 बच्चों का और सेंट मेरी इंटरमीडिएट कॉलेज की दो शाखाओं ने 11 बच्चों का दाखिला नहीं लिया. कुल मिला कर 105 बच्चों को दाखिला न देकर इन विद्यालयों ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम का सरासर उल्लंघन किया. यही हाल मौजूदा सत्र में भी हो रहा है. शैक्षणिक सत्र 2017-18 में भी उपर्युक्त विद्यालय बच्चों का दाखिला नहीं ले रहे. कानपुर शहर में डॉ. वीरेन्द्र स्वरूप, चिंटल पब्लिक व स्टेपिंग स्टोन पब्लिक स्कूल जैसे विद्यालय इस वर्ष दाखिला नहीं ले रहे. इस तरह शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) के तहत दाखिला न लेने वाले विद्यालयों की संख्या बढ़ती जा रही है और इन्होंने मिलकर राष्ट्रीय कानून का मजाक बना कर रख दिया है. सामाजिक संगठनों की मांग है कि इन विद्यालयों की मान्यता रद्द होनी चाहिए और इनके संचालकों के खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई होनी चाहिए.

जिस तरह गुजरात में कानून लाकर प्राथमिक विद्यालयों के लिए 15 हजार रुपए सालाना, माध्यमिक विद्यालयों के लिए 25 हजार रुपए और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 27 हजार रुपए सालाना की सीमा तय की गई है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी निजी विद्यालयों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की सीमा तय होनी चाहिए. इस कानून को पारित कराते समय गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेन्द्र सिंह चुड़ास्मा ने कहा था कि शिक्षा सेवा का कार्य है कोई व्यवसाय नहीं. जिन्हें पैसा कमाना है वे कोई कारखाना लगाएं, व्यापार करें, स्कूल न खोलें. ठीक ऐसा ही रुख उत्तर प्रदेश सरकार का भी होना चाहिए. सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडेय का कहना है कि निजी विद्यालयों के मनमाने तरीके से काम करने पर अंकुश लगाने के लिए शिक्षा आयोग का गठन होना चाहिए और जो निजी विद्यालय सरकार का नियम-कानून मानने को तैयार नहीं हैं, उनका संचालन सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिए. उत्तर प्रदेश जन-मंच ने मांग की है कि सरकारी प्राइमरी विद्यालयों को बंद करने का उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध है, इसे सरकार को वापस लेना चाहिए. उत्तर प्रदेश सरकार ने कम उपस्थिति वाले स्कूलों को बंद करने का फैसला करके सरकारी शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के उच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत जाने का काम किया है. यह प्रदेश की पहले से ही जर्जर प्रारंभिक सरकारी शिक्षा व्यवस्था को और बदतर बनाएगा. सरकार का यह फैसला नागरिकों को कल्याणकारी राज्य देने के संवैधानिक दायित्वों से मुंह चुराना है. निजी विद्यालयों और कॉरपोरेट शिक्षा प्रणाली के पक्ष में लिए गए इस निर्णय से छात्राएं और दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज के वंचित वर्ग की बुनियादी शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा. सरकार का यह तर्क कि जिन विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति कम है उसे बंद किया जाएगा, वंचित समुदाय के प्रति नाइंसाफी है, क्योंकि बच्चों की उपस्थिति कम होने का कारण सरकारी प्राथमिक स्कूलों में गुणत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है जिस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी आक्रोश जताते हुए कहा था कि इसका हल यही है कि राजनेताओं और अधिकारियों के बच्चों को इन विद्यालयों में पढ़ाया जाए तभी सरकारी विद्यालयों की दशा में सुधार हो सकता है. गौरतलब है कि प्रदेश में पहले से ही स्कूल नहीं जा सकने वाले बच्चों की बड़ी तादाद है. ड्रॉपआउट दर भी तकरीबन 55-60 फीसदी है. मोदी सरकार बाल श्रम में कार्यरत बच्चों के विशेष स्कूल अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में बंद कर चुकी है. मर्जर के नाम पर स्कूल बंद करके प्रदेश सरकार शिक्षाधिकार कानून के अनुसार 9 से 14 साल के हर बच्चे को शिक्षा पहुंचाने के संवैधानिक दायित्व से भी मुकर रही है. इसलिए प्रदेश सरकार को इस फैसले को वापस लेकर स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने काम करना चाहिए. जन मंच की समन्वयक डॉ. वीणा गुप्ता का कहना है कि बुनियादी शिक्षा हर धर्म और जाति के प्रत्येक बच्चे का हक है. जब तक इन स्कूलों में बच्चे हैं, भले ही कम हों, पर संविधान इन स्कूलों को बंद करने की इजाजत नहीं देता. शिक्षा के बिना विकास कैसे हो सकता है! सरकार ने इस फैसले से सरकारी स्कूलों को बंद करके प्राइवेट स्कूलों को मदद पहुंचा कर शिक्षा के बाजारीकरण की ओर एक और कदम बढ़ाया है. प्रदेश के 50 फीसदी से ज्यादा स्कूलों में बुनियादी संरचनाओं के साथ अध्यापकों का बहुत अभाव है. न पुस्तकालय हैं न प्रयोगशालाएं. शौचालयों व खेल के मैदान की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है. तराई के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बरसात में पानी भरा रहता है, उसके बाद महीनों पानी सूखने में लगता है. पढ़ाई का आधा सत्र बीत जाने के बाद किताबें पहुंचती हैं, यूनिफॉर्म और बस्ते के स्कूल तक पहुंचने की कोई समय सीमा नहीं है, सब सरकार और नौकरशाही की मर्जी पर है. अध्यापक तीन आवश्यक ड्यूटी जनगणना, चुनाव और आपदा के अतिरिक्त कोई ड्यूटी नहीं करेंगे, ऐसा कानून बन जाने के बाद भी उसे लागू नहीं किया जाता. आज भी महीनों तक प्राइमरी के अध्यापक बोर्ड में ड्यूटी करने और कॉपी जांचने को मजबूर हैं. इस अवधि में स्कूल बंद रहते हैं. स्पष्ट है कि सरकार प्रारम्भिक शिक्षा में सुधार के लिए गंभीर नहीं है. प्रदेश सरकार का दायित्व है कि स्कूलों की गुणवत्ता सुधारे और उपस्थिती सुनिश्चित कराए. नागरिक समाज की भी जिम्मेदारी है कि वे सरकार को उसका दायित्व याद दिलवाएं. डॉ. वीणा गुप्ता ने प्रदेश की सभी संस्थाओं और संगठनों से भी अपील की है कि प्रदेश के बच्चों और भावी पीढ़ी के सुनहरे भविष्य के लिए और शिक्षाधिकार कानून में वर्णित बच्चों के अधिकारों के लिए आगे आएं और जरूरत पड़े तो सीधे संघर्ष के लिए तैयार रहें. ■

### किताबों से पक रहा मिड-डे मील

एक तरफ स्कूलों में किताबें नहीं तो दूसरी तरफ कई स्कूलों में किताबें ही ईंधन का काम कर रही हैं. इन स्कूलों के प्रबंधन का कहना है कि बच्चों के लिए किताबों से अधिक जरूरी मिड डे मील है. बस्ती जिले के सदर ब्लॉक डारडीहा में ऐसा ही नायाब वाकया सामने आया है. वहां के एक प्राइमरी स्कूल में किताबों को जलाकर मिड-डे मील तैयार किया जा रहा था. स्कूल के प्रबंधन ने कहा कि बच्चों के लिए खाना जरूरी था. ईंधन के लिए स्कूल के पास फंड उपलब्ध नहीं है. सरकारी स्कूलों में किताबें सरकार की ओर से दी जाती हैं, इसलिए उन किताबों को ही मुफ्त का ईंधन बना लिया जाता है.

feedback@chauthiduniya.com

## मुंगेर नक्सली हमले पर आया अदालती फ़ैसला

# पुलिस अनुसंधान पर उठा सवाल

**पांच नक्सलियों को मौत की सजा सुनाने वाले मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव नक्सलियों के निशाने पर आ गए हैं. नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर फांसी की सजा सुनाने वाले जज को ही सजा-ए-मौत का ऐलान किया है. नक्सली संगठन ने धमकी देते हुए कहा है कि जन अदालत लगाकर फांसी की सजा सुनाने वाले जज को सजा दी जाएगी. पुलिस अधीक्षक आशीष भारती के अनुसार न्यायाधीश की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. मामला यहीं नहीं थमा है, इसके बाद गंगटा थाना क्षेत्र के कूनोली जमघट दरियापुर में नक्सलियों ने दो दिन की बंदी की घोषणा के बाद पर्चा साटकर अपनी मंशा का इजहार किया है.**

कुमार कृष्णन

माओवादी सीआरपीएफ के जवानों को लगातार अपना निशाना बनाते आए हैं. बस्तर से लेकर झारखंड और देश के कई हिस्सों में घटित घटनाएं इसका प्रमाण हैं. चुनाव के दौरान तो नक्सली वोट बहिष्कार के नारे के साथ खूनी खेल खेलने को तैयार रहते हैं. 2014 में ऐसी ही एक घटना नक्सल प्रभावित मुंगेर के हवेली खड़गपुर में घटी थी. तारीख 10 अप्रैल 2014. तड़के सुबह 3.30 बजे भीमबांध से वाहनों पर सवार होकर सीआरपीएफ की 131वीं बटालियन के जवान निकले थे. सवा लाख बाबा स्थान से लगभग 200 गज की दूरी पर वाहन लगा कर जवान पैदल चलने लगे. कुछ जवान वाहन में रह गए. इसी दौरान सबसे पीछे वाले वाहन के पास जोरदार धमाका हुआ. नक्सलियों ने लैंडमाइंस विस्फोट किया था. धमाके के तुरंत बाद पत्थरों की ओट लेकर नक्सलियों ने अत्याधुनिक हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई करने पर नक्सली अंधेरे का लाभ उठाकर जंगल की ओर भाग निकले. दोनों ओर से लगभग 200 गोलियां चलीं. इस हादसे में सीआरपीएफ के हवलदार कर्नाटक के निवासी सोने गौरा और बिहार में हाजीपुर के निवासी रविन्द्र कुमार राय शहीद हो गए. साथ ही अशोक बसेरा (जमुई), राघवेन्द्र सिंह (उत्तर प्रदेश), विश्वनाथ (उत्तर प्रदेश),धर्मात्मा कुमार सिंह (आरा), रामपाल (उत्तर प्रदेश), विक्रम सिंह (उत्तर प्रदेश), धर्मपाल (हरियाणा), मनोज यादव (हाजीपुर) सहित 10 जवान घायल हो गए. नक्सलियों ने मुठभेड़ के दौरान माओवादी जिंदाबाद का नारा भी लगाया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ये गंगटा जंगल की ओर फरार हो गए थे. इसी आधार पर मुंगेर के गंगटा पुलिस आउटपोस्ट में 16 जनों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी. 29 अक्टूबर 2014 को इनमें से एक नक्सली अधिक लाल पंडित हवेली खड़गपुर के पहाड़वीत गांव से और दूसरा रत्तू कोड़ा जमुई लक्ष्मीपुर के चीकियां गांव से पुलिस के हत्थे चढ़ गए. इन दोनों ने मुठभेड़ में शामिल होने की बात कबूली और तीन अन्य लोगों के भी नाम बताए. इनकी निशानदेही पर हवेली खड़गपुर के विपिन मंडल, लक्खीसराय के कजरा बरामशिया गांव के बानो कोड़ा और मन्नू कोड़ा को पुलिस ने दबोचा था. हालांकि अन्य नामजद को पुलिस अबतक नहीं ढूंढ पाई है, जिनमें प्रवेश उर्फ अनुज दा, गोपाल दास, बबलू दास, सिद्धू कोड़ा, बालेश्वर कोड़ा, अर्जुन कोड़ा, बाबूलाल यादव, पूना कोड़ा, पिंटू राणा, अनिल कोड़ा, फुलचंद कोड़ा वगैरह प्रमुख हैं.

इस हादसे के तीन साल बाद मुंगेर कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें पांच नक्सलियों को अर्थदंड के साथ फांसी की सजा सुनाई गई है. फैसला सुनाने वाले अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव की टिप्पणी थी कि यह विचारधारा समाज और तंत्र के विपरीत काम करती है. आरोपियों ने हमारे सिस्टम पर प्रहार किया है क्योंकि जवान उस दिन निर्वाचन कार्य कराने जा रहे थे. यह एक जघन्य अपराध है. इस विचारधारा को मानने वाले लोगों में मैसेज जाना जरूरी है कि इस तरह अपराध करना गलत है. दूसरी ओर पुलिस के अनुसंधान पर भी न सिर्फ सवाल उठाया गया, बल्कि राज्य के पुलिस महानिदेशक को भी पत्र लिखकर नाराजगी का इजहार किया गया. नक्सली मुठभेड़ मामले में अनुसंधानकर्ता सह निवर्तमान खड़गपुर पुलिस उपाधीक्षक रंजन कुमार थे. कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर रंजन कुमार पर कार्रवाई करने को कहा है. कोर्ट ने बताया है कि अनुसंधानकर्ता की लापरवाही के कारण ही सभी नक्सलियों के विरुद्ध कई मुख्य धाराएं नहीं लगाई गईं. इनमें से सबसे प्रमुख धारा के अंतर्गत सभी नक्सलियों को राष्ट्रद्रोह की गतिविधि के दायरे में लाया जाना था. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने आदेश जारी करते हुए जजमेंट की कॉपी उन्हें भेजी है. नक्सलियों को कुल 16 धाराओं में सजा सुनाया जाना था. इन 16 धाराओं में कुछ ऐसी धाराएं थीं, जिनपर अनुसंधानकर्ता ने गंभीरता से काम नहीं किया. नतीजतन नक्सलियों को इन धाराओं में सजा नहीं सुनाई जा सकी. इन धाराओं में प्रमुख रूप से भादवि की धारा 149, 121 (ए), 122, 124, 27, 134 (बी) एवं यूएपी की धारा 16, 17, 18, 20, 23 एवं 35 शामिल हैं. धारा 121 (ए), 122, 124 के अनुसार नक्सलियों को राष्ट्रद्रोह सिद्ध किया जाना था. अदालत ने पांचों नक्सलियों रत्तू कोड़ा, अधिक लाल पंडित, विपिन मंडल, बानो कोड़ा और मन्नू कोड़ा के विरुद्ध भादवि की धारा 302, 353, 147, 148, 341, 307 और 3, 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध होने पर फांसी की सजा सुनाई. इसके साथ ही एक लाख पचहत्तर हजार पांच सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया.

शहीद को तिरंगे की सलामी

फांसी की सजा पाए नक्सली

नक्सली जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई

अपर लोक अभियोजक संदीप भट्टाचार्य का कहना है कि अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है. यह बिहार का पहला मामला है जिसमें ऐसी घटना में इस तरह की सजा सुनाई गई है. यदि तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक रंजन कुमार राष्ट्रद्रोह के लिए आदेश का प्रस्ताव बिहार सरकार को समर्पित करते तो सरकार के आदेश के बाद इन नक्सलियों को राष्ट्रद्रोह जैसे मामलों में भी सजा मिल सकती थी. वहीं 27 आर्म्स एक्ट की सजा से भी नक्सली बच निकले. 134(बी) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं यूएपी एक्ट 16, 17, 18, 20, 23 एवं 35 के मुताबिक संज्ञान होने तक गैर कानूनी अभियोजन स्वीकृत्यादेश आना था, जो विलंब से 17 फरवरी 2017 को मिला. नियमानुसार एक सप्ताह में ही प्राप्त करना है. 15 जनवरी 2015 को अनुसंधानकर्ता ने आरोप पत्र दाखिल किया. 27 फरवरी 2015 को अदालत ने इस पर संज्ञान लिया और इसके बाद 17 गवाहों का परीक्षण किया गया.

पांच नक्सलियों को मौत की सजा सुनाने वाले मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव अब नक्सलियों के निशाने पर आ गए हैं. नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर फांसी की सजा सुनाने वाले जज को ही सजा-ए-मौत का एलान किया है. नक्सली संगठन ने धमकी देते हुए कहा है कि जन अदालत में फांसी की सजा सुनाने वाले जज को सजा दी जाएगी. पुलिस अधीक्षक आशीष भारती के अनुसार न्यायाधीश की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. मामला यहीं नहीं थमा है. इसके बाद गंगटा थाना क्षेत्र केकुनोली जमघट दरियापुर में नक्सलियों ने दो दिन बंदी की घोषणा के बाद पर्चा साटकर अपनी मंशा का इजहार किया है.

पांच माओवादियों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद लोग तत्कालीन पुलिस अधीक्षक केसी सुरेन्द्र बाबू के संदर्भ में कहते हैं कि 12 साल बाद भी सुरेन्द्र बाबू सहित छह जवानों की हत्या में शामिल माओवादियों को सजा नहीं मिली है. यह मामला अब भी कोर्ट में चल रहा है.

5 जनवरी 2005 को कॉबिंग ऑपरेशन कर लौट रहे मुंगेर के तत्कालीन एसपी केसी सुरेन्द्र बाबू सहित छह पुलिस जवानों को सोनरवा गांव के पास बारूदी सुरंग विस्फोट कर माओवादियों ने उड़ा दिया था. बारूदी सुरंग विस्फोट में तत्कालीन एसपी केसी सुरेन्द्र बाबू के साथ जवान ध्रुव ठाकुर, ओपी गुप्ता, मो. अंसारी, मो. इस्लाम एवं शिव कुमार राम शहीद हो गए थे. मुंगेर के पुलिस अधीक्षक आशीष भारती कहते हैं कि इस मामले में 22 लोगों पर आरोपपत्र दाखिल हुआ है. कइयों को कोर्ट में पेश किया जा चुका है, जबकि एक नक्सली चिराग दा पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है. दो अन्य की स्वाभाविक मौत हुई है. इस मामले के तीन संदिग्धों को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया है. तीन संदिग्धों की रिहाई के बाद सरकार ने वर्ष 2013 में कांड का अनुसंधान फिर से शुरू कराया है. मजे की बात यह है कि राज्य के 11 जिलों के 44 मोस्टवांटेड नक्सलियों के पीछे सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के करीब 10 हजार जवान लगे हैं. सीआरपीएफ की साढ़े आठ बटालियन फोर्स इस ऑपरेशन में लगाई गई है. इन नक्सलियों पर राज्य सरकार ने 25 हजार से 5 लाख रुपए तक के इनाम घोषित कर रखे हैं. इनमें से कोई 12 तो कोई 20 मामलों में फरार चल रहा है, लेकिन इतने बड़े तंत्र को झोंकने के बाद भी पुलिस और सुरक्षा बलों को इन नक्सलियों का सुराग नहीं मिल पा रहा है. आईजी ऑपरेशन कुंदन कृष्णन ने कहा कि कुख्यात नक्सलियों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी. खास बात यह है कि राज्य के 40 जिलों (दो पुलिस जिला सहित) में से सिर्फ 11 जिलों में ये नक्सली सक्रिय हैं, जिन्होंने पूरे तंत्र की नाक में दम कर रखा है. सबसे अधिक 12 मोस्ट वांटेड मुंगेर के पड़ोसी जिले जमुई जिले के रहने वाले हैं. दूसरे नंबर पर गया जिला है, जहां के 9 नक्सली स्पेशल टास्क फोर्स की लिस्ट में हैं. इसके अलावा औरंगाबाद के 5, जहानाबाद के 2, रोहतास के 3, पूर्वी चंपारण के 2, बगहा के 3, मुंगेर के 3, बांका के 2, लखीसराय के 2 व समस्तीपुर के 1 नक्सली पर राज्य सरकार ने इनाम घोषित कर रखा है. इनमें चार ऐसे नक्सली हैं, जिनकी तलाश केंद्र व राज्य की एजेंसियों को है. अरविंद जी उर्फ अरविंद कुमार सिंह उर्फ देव सेंट्रल कमेटी का सदस्य है. प्रवेश दा पूर्वी बिहार-पूर्वी झारखंड एरिया का सचिव है. विजय यादव उर्फ संदीप जी भाकपा (माओवादी) की मध्य एरिया कमेटी का सचिव है. राजन जी उत्तर बिहार एरिया कमेटी का सचिव है. कहा जाता है कि नक्सली वारदातों और सुरक्षा बलों पर हमले की रणनीति बनाने में इनको महारत हासिल है. वांटेड नक्सलियों में गुरिल्ला कमांडर लालमोहन यादव और स्पेशल प्लाटून कमांडर मनोज हांसदा भी है. को-ऑर्डिनेशन कमेटी में भी इन नामों की चर्चा कई बार हुई है. हर छह महीने पर होने वाली अलग-अलग क्षेत्रों की को-ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठकों में रणनीति बनती रही है, लेकिन इन वांटेड नक्सलियों को दबोचा नहीं जा सका है.

वैसे राज्य पुलिस व सेंट्रल एजेंसियां अब फरार टॉप नक्सलियों की अवैध कमाई से खड़ी की गई संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई करने जा रही है. ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों के अनुसार 25 यूएपीए (अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट) के तहत राज्य सरकार को संपत्ति जब्त करने की शक्ति है. वहीं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत संपत्ति जब्त करने का अधिकार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को है. दोनों ही कानून के तहत नक्सलियों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है. जल्द ही चार-पांच नक्सलियों की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई शुरू होगी. सूत्रों के अनुसार जहानाबाद के हार्डकोर नक्सली प्रदुमन शर्मा की अवैध संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव ईडी के पास है. 5 लाख के इनामियों में विजय यादव उर्फ संदीप जी, भाकपा (माओवादी) की मध्य एरिया कमेटी का सचिव, निवासी-गया जिले के इमामगंज थाने के लुटुआ टोला, बाबूराम डीह के अरविंद जी उर्फ अरविंद कुमार सिंह उर्फ देव, भाकपा (माओवादी) की सेंट्रल कमेटी का सदस्य, निवासी-जहानाबाद के करौना थाना क्षेत्र का सुकुल चक, रामबाबू राम उर्फ राजन जी, भाकपा (माओवादी) की उत्तर बिहार एरिया कमेटी का सचिव, निवासी-मोतिहारी के मधुबन थाना के कौरिया के और प्रवेश दा उर्फ अनुज दा उर्फ अमलेश दा, भाकपा (माओवादी) के पीबीपीजे (पूर्वी बिहार-पूर्वी झारखंड) का सचिव, निवासी-हजारीबाग के विशनुगढ़ थाने के भंडोरी शामिल हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

# पुल की राजनीति में उलझा दांव

इर्शादुल हक

ऐसा हमेशा नहीं होता कि किसी खास मुद्दे पर सत्य सिर्फ एक ही हो. कभी-कभी सत्य के दो रूप हो सकते हैं और कभी ज्यादा भी. इस एक सत्य का संबंध राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन से है तो दूसरा सत्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के स्थानपा दिवस से. हम जिस सत्य पर आगे चर्चा करने जा रहे हैं स्वाभाविक रूप से उसका संबंध लालू प्रसाद से भी है और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बिरापुनिलि) से भी. क्योंकि 11 जून अगर लालू प्रसाद का जन्मदिन है तो यही दिन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का स्थापना दिवस भी है. वैसे लालू और बिरापुनिलि का कोई सीधा संबंध नहीं है, पर तेजस्वी यादव का संबंध यह है कि यह संस्था उस विभाग के अधीन आता है जिसके मंत्री तेजस्वी यादव हैं यानी पथ निर्माण विभाग. ऐसे में इस बात की प्राथमिकता सुनिश्चित करना किसी के लिए भी असंभव है कि 11 जून यानी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के स्थापना दिवस पर लालू का जन्मदिन है या लालू के जन्मदिन पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का स्थापना दिवस. लेकिन राजनीति का एक दिलचस्प पहलू यह है कि वहां बहुत सारी असंभव चीजें भी संभव बना दी जाती हैं. लिहाजा यह राजनीति में ही संभव है कि सुशील मोदी 11 जून को बिरापुनिलि के स्थापना दिवस के बजाय लालू प्रसाद का सिर्फ जन्मदिन मान कर अपने सियासी तरकश से बयानों के तीर छोड़ते हैं. दरअसल 11 जून बिहार की राजनीति में पिछले दिनों राजनीतिक दावपेंच का दिन बन कर रह गया था. इस दिन बिहार सरकार ने देश के क्रमशः पांचवें और छठे सबसे बड़े पुलों को जनता के सुपुर्द करने का ऐलान किया था. इस पुल को पथनिर्माण विभाग के अधीन काम करने वाले बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की देख रेख में बनवाया गया था. ये दोनों पुल गंगा नदी पर बने हैं. एक आरा और छपरा के बीच तो दूसरा पटना के दीघा और सोनपुर के बीच. इन दोनों पुलों के लोकार्पण की तिथि 11 जून तय की गई थी. इसकी घोषणा होते ही सुशील मोदी ने बौखलाहट में जोरदार सियासी हमला बोल दिया. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपने पिता के जन्मदिन पर पुल उन्हें तोहफे में देना चाहते हैं, जबकि यह पुल जनता को सौंपा जाना चाहिए. जैसे-जैसे 11 जून करीब आता जा रहा था, सुशील मोदी के हमले तेज होते जा रहे थे. वह 11 जून पर लालू के जन्मदिन की बात को इतनी बार दोहरा चुके थे कि जनमानस को यह ख्याल भी नहीं रहा कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने इन पुलों के लोकार्पण की तिथि 11 जून को इसलिए रखी है क्योंकि उस दिन उसका 42वां स्थापना दिवस है. यह संभव है कि जब विभाग लोकार्पण की तिथि तय करने पर विचार कर रहा हो तो उसे लगा हो कि स्थापना दिवस पर यह शुभ काम किया जाए जो संयोग से लालू का जन्मदिन भी है. ऐसे में विपक्ष की तरफ से कई आरोप लगाए जाने लगे. मोदी ने कहा कि इस सेतु का लोकार्पण एक सजायाफ्ता (लालू प्रसाद) नेता से कराया जा रहा है क्योंकि नीतीश और लालू के बीच की विश्वास की खाई को सेतु द्वारा कम करने की कोशिश की जा रही है.

दो सेतुओं को बिहार की जनता के हवाले कर नीतीश सरकार ने निश्चित तौर पर बड़ा काम किया है. सुशील मोदी की बयानबाजियों के कारण जनता का ध्यान पुल के महत्व से हटकर उससे जुड़े विवाद की तरफ चला गया. दरअसल मोदी यही चाहते भी थे, लेकिन स्वाभाविक था कि मोदी के इस राजनीतिक व्यवहार का महागठबंधन सरकार गिन-गिन कर बदला लेने के इंतजार में थी. सो जब 11 जून का दिन आया तो उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, शिक्षा मंत्री (कांग्रेस के नेता) अशोक चौधरी, लालू प्रसाद और यहां तक कि नीतीश कुमार ने भी गिन-गिन कर भाजपा पर प्रहार किया, जब कि यह अवसर सेतुओं के लोकार्पण का था.

इन नेताओं ने इसे भाजपा के 'खाली दिमाग' का काम बताया तो मीडिया को भी टीआरपी के चक्कर में इस मुद्दे को हवा देने का कारण बताया. विपक्ष के हमलों से खिन्न नीतीश ने कहा कि किन-किन सवालों का जवाब दीजिएगा? वे लोग बेरोजगार हैं. वे सवाल उठाएंगे ही. अब उनके सवाल का जवाब दीजिएगा तो उनका सवाल महत्वपूर्ण हो जाएगा. वे महत्वपूर्ण हो जाएंगे. नीतीश ने भाजपा के आरोपों की लिस्ट में जिक्र किए गए एक-एक सवाल का जवाब देना शुरू किया और बताया कि दीघा के पुल के निर्माण में लालू जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. रेल मंत्री की हैसियत से उन्होंने इस पुल का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी से करवाया था. लेकिन जब मैं रेल मंत्री बना तो पाया कि इस प्रोजेक्ट की तैयारी का काम ही नहीं हुआ है. लिहाजा मैंने इसे पूरा करवा और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी से इस रेल पुल का कार्यारंभ करवाया. फिर जब अगली सरकार आयी और लालू जी फिर रेल मंत्री बने तो उन्होंने इस रेल पुल के साथ ही इसमें रेल सह सड़क पुल बनाने की कोशिश शुरू की ताकि कम खर्च में दोनों काम हो सके. नीतीश ने कहा कि मौजूदा सड़क पुल का जो लोकार्पण आज हुआ है वह, लालू जी के कठिन परिश्रम से ही बन सका है. नीतीश इन तमाम बातों को कहकर सुशील मोदी के उन सवालों का जवाब दे रहे थे जिसके तहत उन्होंने (मोदी) इस पुल के लोकार्पण की तारीख पर सवाल उठाए थे. नीतीश कुमार मोदी को यह भी बताना चाह रहे थे कि वे यह भ्रम ना फैलाएं कि इस पुल के निर्माण में वाजपेयी सरकार का ही हाथ था. लिहाजा नीतीश यह साफ कर देना चाहते थे कि वाजपेयी ने जिस रेल पुल का कार्यारंभ किया था, उसमें सिर्फ रेल पुल था जबकि उस रेल पुल में सड़क पुल के प्रोजेक्ट को लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते जोड़ा गया.

लेकिन आरा-छपरा वीर कुंवर सिंह सेतु और दीघा-सोनपुर जेपी सेतु के लोकार्पण को मोदी ने जिस तरह से अपनी राजनीति के रंग में रंगने की कोशिश की तो उसके जवाब में महागठबंधन के नेताओं ने भी लोकार्पण समारोह को आक्रमण समारोह में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी. इस अवसर पर तेजस्वी ने अपना क्रोध निकाला और कहा कि वे (सुशील मोदी) झूठ की गंगा बहाते हैं और हम लोग गंगा पर विकास और एकता का सेतु बनाते हैं. इसी दौरान कांग्रेस के नेता अशोक चौधरी ने जमकर लालू और तेजस्वी का साथ दिया. उन्होंने कहा कि अगर वे कहते है कि 11 जून को लालूजी का जन्मदिन है तो हम लोगों को सीना ठोक कर स्वीकार कर लेना चाहिए कि हां है. सारांश यह कि इन दो सेतुओं के लोकार्पण के बहाने गठबंधन के तमाम नेताओं ने भी सुशील मोदी और भाजपा पर जवाबी हमला बोला. लेकिन सुशील मोदी राजनीतिक तौर पर जो हासिल करना चाहते थे, उसमें एक हद तक कामयाब रहे. पुलों के लोकार्पण पर सुशील ने एक ऐसे मुद्दे को आगे बढ़ाया, जिसमें बहुत दम नहीं था. हमने ऊपर उल्लेख किया है कि 11 जून का महत्व बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के लिए जिनता है, उसे नकारा नहीं जा सकता. लेकिन सुशील मोदी ने इस 11 जून को सिर्फ लालू प्रसाद से जोड़ दिया और अपनी बनाई हुई पिच पर बाउंसर डालने लगे. बाद में स्थिति यह आई कि पहले तेजस्वी यादव और तेजस्वी के लोगों पर बाउंसर फेंका गया और फिर अंत में सुशील मोदी ने आखिरी गुगली नीतीश कुमार पर यह कहते हुए डाल दी कि एक मुख्यमंत्री को यह अधिकार है कि किसी पुल या भवन के लोकार्पण के लिए खुद तारीख तय करें. लेकिन सत्ता के अहंकार में क्या वे किसी भवन के लोकार्पण के लिए शहाबुद्दीन, प्रभुनाथ सिंह या राजबल्लभ यादव के जन्म को चुन लेंगे?

गौर से देखें तो पुल पर राजनीति का कोई औचित्य नहीं था. पुल निर्माण के इस गंभीर पहल को सुशील मोदी ने पूरी अगंभीरता से राजनीतिक रंग दे दिया. यही वजह है कि राजद के लोग उन पर अगंभीर नेता होने का आरोप लगाते हैं. इन तमाम बातों के अलावा भले ही मोदी पर अगंभीर या कई बार झूठ बोलने तक के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन इतना तय है कि सुशील मोदी ने पुल की राजनीति कर सत्ता पक्ष को अपने जाल में उलझा लिया. और कम से कम एक पखवाड़े तक बिहार की राजनीति दो सेतुओं के बजाय मोदी के इर्द-गिर्द घूमती रही. ■

feedback@chauthiduniya.com

# पूर्वी चम्पारण में खुलेगा लीची प्रशोधन केन्द्र

राकेश कुमार

feedback@chauthiduniya.com

चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के अवसर पर बिहार में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं. केन्द्र सरकार, बिहार सरकार, विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों सहित मीडिया संगठनों द्वारा इस मौके पर आयोजन हो रहे हैं. विगत 13 अप्रैल से एक सप्ताह तक केन्द्र सरकार द्वारा स्थानीय सांसद सह केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह के नेतृत्व में शानदार कार्यक्रम सम्पन्न हुआ. वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 अप्रैल को चन्द्रहियां से मोतिहारी गांधी उद्यान तक 9 किलोमीटर की पदयात्रा की. बिहार सरकार ने गांधी जी के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए फिल्म पैनोरोमा के तहत बिहार के सभी शहरों में गांधी जी से संबंधित फिल्मों का प्रदर्शन किया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में दो दिवसीय सेमिनार आयोजित कर राष्ट्रीय समस्याओं का निदान ढूंढने की कोशिश की. उक्त सेमिनार में गांधीवादियों एवं चिंतकों ने भी हिस्सा लिया. वहीं 8 से 9 जुलाई तक चम्पारण प्रेस क्लब द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश-विदेश के पत्रकार भाग लेंगे. वहीं प्रमुख वक्ता के रूप में प्रख्यात पत्रकार संतोष भारतीय, एएनआई के प्रमुख ऑकारेश्वर पाण्डेय, डीयू के आचार्य और प्रख्यात विचारक आनन्दवर्धन जैसे महान चिंतक, लेखक और पत्रकार होंगे. गांधी जी के सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के मौके पर देश-दुनिया के थिंक-टैंक कहे जाने वाले लोगों द्वारा विश्व शांति और महात्मा गांधी विषय पर विचार-विमर्श किया जाएगा.

सत्याग्रह शताब्दी समारोह के अवसर पर योग गुरु बाबा रामदेव तीन दिन के प्रवास पर 7 जून को मोतिहारी पहुंचे थे. 8 से 10 जून तक मोतिहारी के गांधी मैदान में उन्होंने योग शिविर का आयोजन किया. इस दौरान उन्होंने चन्द्रहियां स्थित गांधी आश्रम में ग्रामीणों के एक सभा को भी सम्बोधित किया. वहीं दूसरे दिन पीपरा कोठी स्थित कृषि अनुसंधान केन्द्र में किसानों की एक सभा को भी सम्बोधित किया.

बाबा रामदेव का चम्पारण प्रवास कई मायनों में लोगों को एक सुखद अहसास दे गया. एक विशेष भेंट में बाबा रामदेव ने कहा कि महात्मा गांधी स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की बात कहते थे. इसके मूल में आर्थिक और सामाजिक कारण था. देश को समृद्ध बनाने के लिए स्वदेशी अपनाना होगा. उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी के स्वदेशी की आज और भी जरूरत है. उन्होंने बताया कि विदेशी कम्पनियां भारत में पचास लाख करोड़ का व्यवसाय कर रही हैं. विदेशी कम्पनियां देश का अर्थ बाहर ले जा रही हैं और हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात करते हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार पर 15

लाख करोड़ के व्यवसाय पर केवल चीन का कब्जा है. चीन भारत से पैसा कमाकर ले जाता है और उसी पैसे से पाकिस्तान के आतंकवादियों को भारत के खिलाफ फंडिंग करता है. बाबा रामदेव ने कहा कि स्वदेशी अपना कर ही देश आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सकेगा. उन्होंने कहा कि योग मेरा धर्म है, पर राष्ट्रधर्म से पीछे नहीं रहूंगा. स्वदेशी और देशी चिकित्सा के लिए पतंजलि काम कर रहा है. गर्व से कह सकता हूं कि देशवासियों का इतना समर्थन मिला कि केवल एक विदेशी कम्पनी को छोड़कर सभी को पतंजलि ने पछाड़ दिया है और आने वाले एक साल में पतंजलि सबसे आगे होगा. उन्होंने कहा कि देश को आजादी तो मिल गई पर आर्थिक आजादी नहीं मिल सकी. देश को एक ईस्ट इंडिया कम्पनी ने गुलाम बना लिया था, जबकि आज सैकड़ों विदेशी कम्पनियों ने पूरे देश पर कब्जा जमा रखा है.

चम्पारण लीची उत्पादन में सबसे आगे है और यहां का लीची सबसे ज्यादा सुस्वादु होता है. चम्पारण प्रवास के दौरान बाबा रामदेव ने चम्पारण में एक लीची प्रशोधन उद्योग लगाने का ऐलान किया. वहीं स्थानीय किसानों ने बाबा रामदेव से चीनी मिल लगाने की मांग की क्योंकि चम्पारण में गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा होता था. चीनी मिलों के बंद हो जाने से किसानों ने गन्ना उत्पादन बंद कर दिया. गन्ना उत्पादन बंद हो जाने से चम्पारण के किसानों की आर्थिक स्थिति भी चरमरा गई. पीपरा कोठी स्थित कृषि अनुसंधान केन्द्र में आयोजित किसानों की सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान गन्ना का उत्पादन करें और उससे गुड़ बनाएं. पतंजलि सभी किसानों का गुड़ खरीद लेगी.

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सह स्थानीय सांसद राधामोहन सिंह के बुलावे पर बाबा रामदेव चम्पारण आए थे. तीन दिवसीय योग शिविर में मंत्री राधामोहन सिंह भी साथ थे. इसके कारण विरोधियों ने उनपर जमकर निशाना भी साधा. विरोधी दल के लोगों ने इसे भाजपा का कार्यक्रम बताया. विरोधी खेमे में राजद और कांग्रेस ने कहा कि बाबा रामदेव यहां अपना व्यवसाय करने आए हैं. वहीं केन्द्र की किसान विरोधी सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है. ऐसे में बाबा रामदेव की घोषणा अपनी नाकामी छुपाने का प्रयास है.

वहीं जब राधा मोहन सिंह चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह के मौके पर बाबा रामदेव के साथ मोतिहारी के कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, तब मध्यप्रदेश में आक्रोशित किसानों पर पुलिस फायरिंग में पांच किसानों की मौत हो गई थी. घटना के बाद कृषि मंत्री विपक्ष और मीडिया के निशाने पर आ गए. दूसरे दिन मंत्री श्री सिंह ने बयान दिया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में सबसे ज्यादा काम किया है. वहां किसान आन्दोलन कर ही नहीं सकते, कुछ लोगों ने किसानों को भड़काकर हिंसा भड़काई है. उन्होंने सीधा कांग्रेस पर प्रहार किया.

इस मौके पर राधा मोहन सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि चारा खाने वाले एवं देश पर साठ साल तक राज करने वाले आज किसानों के हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं. अगर कांग्रेस किसानों के हित के प्रति गंभीर रहती तो आज भारज का किसान सबसे खुशहाल होता. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों की चिंता कर रही है. किसानों के विकास के लिए तेजी से काम किया जा रहा है, लेकिन विरासत में मिली व्यवस्था को ठीक करने में समय लगता है. उन्होंने मध्यप्रदेश की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं. उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि अगर कोई किसान कर्ज लेता है तो सरकार उसके कर्ज का भुगतान करेगी. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार केन्द्रीय योजनाओं पर ध्यान न देकर केवल शराबबंदी और दहेज उन्मूलन में जुटी है. भाजपा के साथ जब राज्य में सरकार का गठबंधन था तो पांच चीनी मिलें लगी थीं. अब स्थिति यह है कि चीनी मिल मालिक पर केस हुआ है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है. उन्होंने इस मौके पर केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाए जा रहे योजनाओं की जानकारी भी दी. ■

# जौहर की आत्मकथा से खुले राज़

अनंत विजय

जब 2001 में करण जौहर की फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' रिलीज होने वाली थी, तो उस वक्त करण जौहर बेहद घबराए हुए थे. उनके दिमाग में ये बात चल रही थी कि उसी वर्ष आमिर खान की फिल्म 'लगान' ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. फरहान अख्तर की फिल्म 'दिल चाहता है' ने भी जमकर वाहवाही और सफलता दोनों बटोरी थी. इन दो बेहद सफल फिल्मों के बाद करण की फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' को रिलीज होना था. करण ने अपनी संस्मरणात्मक किताब 'एन अनसूटेबल बॉय' में इस पूरे प्रसंग पर विस्तार से लिखा है. करण ने माना है कि उनको इस बात का डर था कि वे आमिर खान और फरहान अख्तर के स्तर को छू पाएंगें या नहीं. इस साल जनवरी में जब करण जौहर की 'एन अनसूटेबल बॉय' प्रकाशित हो रही थी, तो उसी वक्त ऋषि कपूर की आत्मकथा 'खुल्लम खुल्ला' भी प्रकाशित हो रही थी या हो चुकी थी. फिल्म के दर्शकों की तरह दोनों किताबों को लेकर पाठकों के बीच एक उत्सकुता का माहौल था. करण जौहर के संस्मरणों की किताब 'एन अनसुटेबल बॉय' में उनके बचपन से लेकर अबतक की कहानी है, कहीं विस्तार से तो कहीं बेहद संक्षेप में. करण ने अपनी फिल्मों की तरह अपनी इस किताब में भी इमोशन का तड़का लगाया गया है. करण जौहर जब अपने बचपन आदि के बारे में बहुत विस्तार से लिखते हैं, तो कई बार इस बात का अहसास होता है कि किताब के संपादन में थोड़ी निर्ममता की आवश्यकता थी. आम पाठक तो फिल्मी शख्सियतों की किताब में फिल्मी दुनिया के पर्दे के पीछे की कहानियां, गॉसिप, अफेयर्स, लगाव-विरह, पारिवारिक कलह आदि के बारे में जानने की ख्वाहिश रखते हैं. करण जौहर की शख्सियत के साथ उनके सेक्सुअल प्रेफरेंस को लेकर काफी बातें होती रही हैं. अपनी इस किताब में करण जौहर ने अपने सेक्स लाइफ के बारे में विस्तार से लिखा है. एक सफल फिल्मकार की तरह करण ने अपनी शख्सियत से जुड़े उस पहलू को उभारने की कोशिश की है, जिसकी जिज्ञासा पाठकों में सबसे ज्यादा है. करण जौहर ने ईमानदारी से स्वीकार किया है कि उनका सेक्स लाइफ छब्बीस साल की उम्र में अमेरिका में शुरू हुआ था, लेकिन पहले दोनों मौकों पर वे निराश हुए थे. करण जौहर ने लिखा है कि लोगों को लगता है कि बॉलीवुड में संबंध बनाने की छूट और आजादी दोनों रहती है, जो कि बहुत हद तक बॉलीवुड के खुलेपन से बनता है. करण कहते हैं कि लोग उनके बारे में भी सोचते हैं कि वे बहुत ज्यादा यात्रा करते हैं, लिहाजा महिलाओं से संबंध बनाते रहते होंगे. करण के मुताबिक, इस तरह की सोच उचित नहीं है, क्योंकि बोर्डिंग पास का मतलब सेक्स का पास नहीं होता है. अपनी इस किताब में सेक्सुअल लाइफ पर करण ने काफी लिखा है और वे इस पर सफाई भी दे देते हैं. करण के मुताबिक, इस डिपार्टमेंट में वे बचपन में काफी कमजोर थे. उन्होंने ईमानदारी से माना है कि उनके और पिता के बीच उम्र का काफी लंबा अंतराल था और फिर उनके जानने वालों में कोई ऐसा था नहीं, जो इस बारे में कुछ भी बता सके. अपने दोस्तों को करण गुड बॉय-गर्ल मानते हैं, जो कि मासूम गुजराती परिवारों से आते थे, जिन्हें पिकनिक पर जाना अच्छा लगता था, खाना-पीना-घूमना पसंद था, पर बढ़ते उम्र के साथ सेक्स का ना तो कोई ज्ञान था और ना ही उसमें किसी की रुचि. करण जौहर ने 'एन अनसुटेबल बॉय' में इसपर भी एक पूरा अध्याय लिखा है .

इसी तरह करण ने शाहरुख खान से अपनी दोस्ती और उनके साथ अपने संबंधों पर भी एक अध्याय लिखा है. ऐसा प्रतीत होता है कि करण ने शाहरुख के साथ अपनी दोस्ती पर ईमानदारी से कलम चलाई है. शाहरुख के अलावा काजोल से अपने संबंधों के टूटने की वजह भी उन्होंने बताई है. यहां जिस साफगोई से करण ने लिखा है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए, वर्ना आमतौर पर तो आत्मकथात्मक संस्मरणों में सच के आवरण में झूठ का पुलिंदा पेश किया जाता रहा है. करण ने बेहद साफगोई से अपने डिप्रेशन के दौर पर भी लिखा है, जिसमें अपने अकेलेपन से लेकर संबंधों के एकाकीपन पर भी प्रकाश डाला है. इकलौती संतान होने के दंश को भी करण ने बेहतर तरीके से पेश किया है. करण इस बात को लेकर बेहद परेशान रहते थे. उनके साथी उन्हें खौंण कहा करते थे. अपने हावभाव में करण अपने हाथों को इस तरह से हिलाते थे कि दोस्तों को खौंण कहकर चिढ़ाने का मौका मिल जाता था. इस शब्द को सुनकर करण बेहद परेशान हो जाया करते थे. बाद के दिनों में करण ने अपने बात करने के अंदाज को तो संवारा ही, अपने हाथों के मूवमेंट में बदलाव के लिए भी मेहनत की. हाथों के संतान होने के दंश को भी करण ने बेहतर तरीके से पेश किया है. करण इस बात को लेकर बेहद परेशान रहते थे. उनके साथी उन्हें खौंण कहा करते थे. अपने हावभाव में करण अपने हाथों को इस तरह से हिलाते थे कि दोस्तों को खौंण कहकर चिढ़ाने का मौका मिल जाता था. इस शब्द को सुनकर करण बेहद परेशान हो जाया करते थे. बाद के दिनों में करण ने अपने बात करने के अंदाज को तो संवारा ही, अपने हाथों के मूवमेंट में बदलाव के लिए भी मेहनत की. हाथों के इसी अंदाज की वजह से उन्हें दोस्तों के ताने सुनने पड़ते थे. करण ने अपनी इस किताब में बॉलीवुड की कई शख्सियतों पर विपरीत टिप्पणी भी की है, जो इस वक्त ना केवल सक्रिय हैं, बल्कि ताकतवर भी हैं. करण जौहर ने अपनी इस किताब में शाहरुख के अलावा यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा और फिल्म वितरक अनिल थडानी से अपनी दोस्ती को याद किया है. करण ने लिखा है कि तीनों हिंदी फिल्मों के दीवाने थे, जिसकी वजह से उनकी दोस्ती परवान चढ़ी थी. जब आदित्य चोपड़ा ने 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के मार्फत दिलीपकी दुनिया में कदम रखने का फैसला किया, तो उन्होंने करण जौहर को भी अपने साथ काम करने के लिए राजी किया. करण ने आदित्य के असिस्टेंट के तौर पर 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में काम किया. करण ने इस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका भी निभाई. उन्होंने माना है कि 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में आदित्य के साथ काम उनकी जिंदगी का अहम टर्निंग प्वाइंट रहा. इस फिल्म के बाद करण ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में बनाईं. शाहरुख और गौरी खान से उनकी दोस्ती भी इस फिल्म के दौरान ही हुई. अपने पिता की मौत के बाद करण को फिल्मों की रचनात्मकता और कलात्मकता के अलावा वित्तीय प्रबंधन आदि भी देखना पड़ा था, लेकिन वे कहते हैं कि तब उनके स्कूल के दोस्त अपूर्व मेहता लंदन की अपनी नौकरी छोड़कर वापस आ गए और उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन को संभाला.

इस किताब के उपसंहार में करण जौहर ने लिखा है- मैं एक बच्चा चाहता हूं, जो बुढ़ापे में मेरा ख्याल रख सके, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ मुझे अकेलेपन से डर लगता है. ये मेरा सबसे बड़ा डर है. मौत से मुझे डर नहीं लगता, कभी-कभी जिंदगी ही डराती है. जनवरी में जब ये किताब आई थी, तो किसी को करण के मंसूबों के बारे में नहीं पता था कि वे सैरोगेसी से पिता बनना चाहते हैं. हालांकि इस अध्याय में उन्होंने इसके पूरे संकेत दिए हैं. करण ने लिखा है- उम्र के इस दौर में वे एक बच्चे के बारे में सोच रहे हैं. ये बच्चा सैरोगेट होगा या फिर मुझे गोद लेना होगा. इस किताब के वक्त वे कई प्रश्नों और द्वंद्व से मुठभेड़ कर रहे थे. क्या वे सिंगल पेरेंट की भूमिका का निर्वाह कर पाएंगे? क्या वे बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? क्या वे बच्चे की पर्याप्त देखभाल कर पाएंगे? आदि आदि. तब लोगों ने ये कयास लगाए थे कि करण शादी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अभी हाल ही में सैरोगेसी से जुड़वा बच्चे के पिता बने हैं करण जौहर. इस लिहाज से अगर देखें, तो करण की ये किताब उनकी अबतक की यात्रा का स्मरण तो है ही, इसमें उन्होंने अपने भविष्य के भी कुछ संकेत दे दिए थे. 216 पृष्ठों की इस किताब की अगर संपादन के वक्त चूलें कस दी जातीं, तो पाठकों के लिए और रोचक होती. ■

anant.ibn@gmail.com

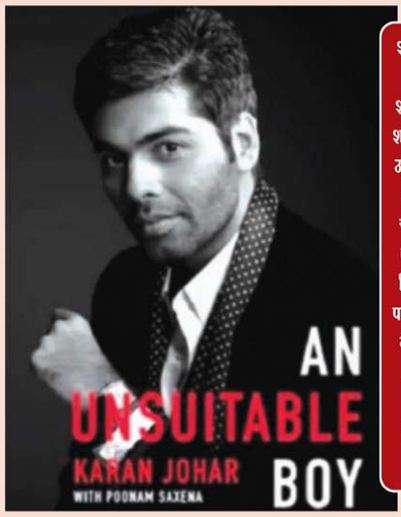


**शाहरुख खान से अपनी दोस्ती और उनके साथ अपने संबंधों पर भी एक अध्याय लिखा है. ऐसा प्रतीत होता है कि करण ने शाहरुख के साथ अपनी दोस्ती पर ईमानदारी से कलम चलाई है. शाहरुख के अलावा काजोल से अपने संबंधों के टूटने की वजह भी उन्होंने बताई है. यहां जिस साफगोई से करण ने लिखा है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए, वर्ना आमतौर पर तो आत्मकथात्मक संस्मरणों में सच के आवरण में झूठ का पुलिंदा पेश किया जाता रहा है. करण ने बेहद साफगोई से अपने डिप्रेशन के दौर पर भी लिखा है, जिसमें अपने अकेलेपन से लेकर संबंधों के एकाकीपन पर भी प्रकाश डाला है. इकलौती संतान होने के दंश को भी करण ने बेहतर तरीके से पेश किया है. करण इस बात को लेकर बेहद परेशान रहते थे. उनके साथी उन्हें खौंण कहा करते थे . अपने हावभाव में करण अपने हाथों को इस तरह से हिलाते थे कि दोस्तों को खौंण कहकर चिढ़ाने का मौका मिल जाता था. इस शब्द को सुनकर करण बेहद परेशान हो जाया करते थे.**

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

# बीपीएल चयन प्रक्रिया की जांच और आरटीआई

जिस देश की 37 फीसदी से ज़्यादा आबादी ग़रीब हो, वहां ये ज़रूरी हो जाता है कि ग़रीबी से जुड़ी योजनाओं को ईमानदारी से लागू किया जाए. लेकिन व्यवहार में अब तक यही देखने को मिला है कि ग़रीबों के विकास के लिए बनाई गईं लगभग सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है. इस अंक में हम एक ऐसे ही मसले पर बात कर रहे हैं, जो सीधे-सीधे ग़रीबों के अधिकारों और उनके विकास से जुड़ा हुआ है, यानि बीपीएल सूची, जिसके आधार पर ग़रीबों को बहुत सी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है. ज़ाहिर है, सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए बहुत से लोग किसी भी प्रकार से अपना नाम बीपीएल सूची में शामिल करा लेते हैं. नतीजतन, जो ज़रूरतमंद लोग हैं और जिन्हें वाक़ई सरकारी मदद की ज़रूरत होती है, वे इससे वंचित रह जाते हैं. इस अंक में एक ऐसा आवेदन प्रकाशित किया जा रहा है, जिसके इस्तेमाल से आप बीपीएल सूची में पारदर्शिता बनाने का दबाव डाल सकते हैं और साथ ही सूची तैयार करते वक़्त इसमें होने वाली गड़बड़ियों को पकड़ सकते हैं या उनका खुलासा कर सकते हैं. हम उम्मीद करते हैं कि आप इस आवेदन का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे और अन्य लोगों को भी इसके लिए उत्साहित करेंगे.

## आवेदन का प्रारूप

बीपीएल के चयन के लिए किए गए सर्वे का विवरण

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

**विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.**

महोदय,

.....*ग्राम में 'गरीबी रेखा से नीचे' (बी.पी.एल.) के सर्वेक्षण के सम्बंध में निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान करें:*

1. उपरोक्त गांव में 'गरीबी रेखा से नीचे' (बी.पी.एल.) के कितने कार्डधारी हैं? उनकी सूची निम्नलिखित विवरण के साथ उपलब्ध कराएं:
   क. कार्डधारक का नाम
   ख. पिता का नाम
   ग. कार्ड संख्या
   घ. कार्ड पर सदस्यों की संख्या (यूनिट)
2. उपरोक्त कार्डधारियो का 'गरीबी रेखा से नीचे' (बी.पी.एल.) का कार्ड किस आधार पर बनाया गया? इस सम्बंध में कार्डधारी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज की प्रति उपलब्ध कराएं.
3. उपरोक्त गांव में 'गरीबी रेखा से नीचे' (बी.पी.एल.) के परिवारों का सर्वेक्षण पिछली बार कब हुआ था? उस सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएं साथ ही सर्वेक्षण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम व पद बताएं?
4. 'गरीबी रेखा से नीचे' (बी.पी.एल.) के परिवारों के सर्वेक्षण के समय परिवारों के चयन के लिए क्या मापदंण्ड/मानक बनाए गए है? इस सम्बंध में समस्त शासनादेशों/नियमों एवं निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध कराएं.
5. उपरोक्त सर्वेक्षण के उपरांत क्या कोई पुन: निरीक्षण (रिव्यू) किया गया? यदि हां, तो समस्त दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराएं.
6. पुन: निरीक्षण (रिव्यू) के सम्बंध में समस्त शासनादेशों/नियमों एवं निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध कराएं.
7. सर्वेक्षण के दौरान किसी अनियमितता का मामला सामने आया है? यदि हां, तो शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई? विवरण दें.

मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपए अलग से जमा कर रहा/रही हूं या मैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बी.पी.एल. कार्ड नं.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएं.

**भवदीय**

नाम:
पता:
फोन नं:

संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

**अगर आपके पास आरटीआई से संबंधित कोई ख़बर या सवाल है, तो हमें इमेल करें:**

**rti@chauthiduniya.com**

# आपातकाल: भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय

**967 और 1971 के बीच, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ ही संसद में भारी बहुमत को अपने नियंत्रण में कर लिया था. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बजाय, प्रधानमंत्री सचिवालय के भीतर ही केंद्र सरकार की शक्ति को केंद्रित किया गया. सचिवालय के निर्वाचित सदस्यों को उन्होंने एक खतरा के रूप में देखा. इसके लिए वह अपने प्रधान सचिव पीएन हक्सर, जो इंदिरा के सलाहकारों की अंदरुनी घेरे में आते थे, पर भरोसा किया. इसके अलावा, हक्सर ने सत्तारूढ़ पार्टी की विचारधारा प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार को बढ़ावा दिया. इंदिरा गांधी ने चतुराई से अपने प्रतिद्वंदियों को अलग कर दिया जिस कारण कांग्रेस विभाजित हो गयी...**

चौथी दुनिया ब्यूरो

26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था. तत्कालीन राष्ट्रपति फ़ख़रुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी. स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक समय था. आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त करके मनमानी की गई. इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया और प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया. प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर नसबंदी अभियान चलाया गया. जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि कहा था.

दरअसल, 1967 और 1971 के बीच, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ ही संसद में भारी बहुमत को अपने नियंत्रण में कर लिया था. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बजाय, प्रधानमंत्री सचिवालय के भीतर ही केंद्र सरकार की शक्ति को केंद्रित किया गया. सचिवालय के निर्वाचित सदस्यों को उन्होंने एक खतरा के रूप में देखा. इसके लिए वह अपने प्रधान सचिव पीएन हक्सर, जो इंदिरा के सलाहकारों की अंदरुनी घेरे में आते थे, पर भरोसा किया. इसके अलावा, हक्सर ने सत्तारूढ़ पार्टी की विचारधारा प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार को बढ़ावा दिया. इंदिरा गांधी ने चतुराई से अपने प्रतिद्वंदियों को अलग कर दिया जिस कारण कांग्रेस विभाजित हो गयी और 1969 में दो भागों, कांग्रेस (ओ) और कांग्रेस (आर) जो इंदिरा की ओर थी, में बट गयी. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस सांसदों के एक बड़े भाग ने प्रधानमंत्री का साथ दिया. इंदिरा गांधी की पार्टी पुरानी कांग्रेस से ज्यादा ताकतवर व आंतरिक लोकतंत्र की परंपराओं के साथ एक मजबूत संस्था थी. दूसरी ओर कांग्रेस (आर) के सदस्यों को जल्दी ही समझ में आ गया कि उनकी प्रगति इंदिरा गांधी और उनके परिवार के लिए अपनी वफादारी दिखने पर पूरी तरह निर्भर करती है. चाटुकारिता का प्रदर्शन उनकी दिनचर्या बन गया. आने वाले वर्षों में इंदिरा का प्रभाव इतना बढ़ गया कि वह कांग्रेस विधायक दल द्वारा निर्वाचित सदस्यों की बजाय, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रूप में स्वयं चुने गए वफादारों को स्थापित करती थीं.

1971 के आम चुनावों में, गरीबी हटाओ का इंदिरा का लोकलुभावन नारा लोगों को इतना पसंद आया कि पुरस्कार स्वरुप उन्हें एक विशाल बहुमत (518 में से 352 सीटें) से जीता दिया. जीत के इतने बड़े अंतर के सम्बंध में इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने बाद में लिखा था कि कांग्रेस (आर) असली कांग्रेस के रूप में खड़ी है, इसे योग्यता प्रदर्शित करने के लिए किसी प्रत्यय की आवश्यकता नहीं है. दिसंबर 1971 में, इनके सक्रिय युद्ध नेतृत्व में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) को पाकिस्तान से स्वतंत्रता दिलवाई. अगले महीने ही उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वह उस समय अपने चरम पर थीं. तानाशाह होने का और एक व्यक्तित्व पंथ को बढ़ावा देने का आरोप लगाने वाले विपक्षी नेताओं ने भी उन्हें दुर्गा सामान माना. 1975 की तपती गर्मी के दौरान अचानक भारतीय राजनीति में भी बेचैनी दिखी. यह सब हुआ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फ़ैसले से, जिसमें इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने का दोषी पाया गया और उन पर छह वर्षों तक कोई भी पद संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.

दरअसल, 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राज नारायण को एक लाख 11 हजार मतों से हराया था. राज नारायण ने इस चुनाव के खिलाफ याचिका दायर की. आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव के दौरान कई कानून तोड़े हैं और भ्रष्ट तरीके अपनाए है. मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश जगमोहन लाल सिंहा ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया. अगले छह साल तक चुनाव लड़ने पर रोक भी लगा दी. साथ ही, जज ने कहा कि इंदिरा गांधी लोकसभा की बैठक में तो शामिल हो सकती हैं, पर वह सदन में मतदान नहीं कर सकतीं. उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 20 दिनों का समय दिया गया. न्यायमूर्ति ने अपने ऐतिहासिक जजमेंट में कहा कि प्रतिवादी को चुनाव कानून की धारा-123(7) के तहत दोषी पाया जाता है. उन्होंने जिलाधिकारी, एसपी, पीडब्ल्यूडी के गजटेड इंजीनियर से अपनी चुनावी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए सहायता ली. साथ ही उन्होंने एक गजटेड कर्मचारी यशपाल कपूर की सेवाएं प्राप्त कीं. यह भ्रष्ट तरीके के इस्तेमाल की श्रेणी में आता है. अदालत ने यह भी पाया कि इंदिरा गांधी, पीएन हक्सर और यशपाल कपूर के कोर्ट में दिए गए बयान दस्तावेजों के तथ्यों से मेल नहीं खाते. अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया. इसके बावजूद इंदिरा गांधी टस से मस नहीं हुईं. यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने भी बयान जारी कर कहा कि इंदिरा का नेतृत्व पार्टी के लिए अपरिहार्य है. 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रायबरेली से इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था. अपनी सांसदी बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोप दिया. सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण और प्रतिपक्ष के करीब एक लाख से भी अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेलों में ठूंस दिया गया. प्रेस पर कड़ी सेंसरशिप लागू कर दी गई. आकाशवाणी पर प्रसारित अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा कि जब से मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील क़दम उठाए हैं, तभी से मेरे ख़िलाफ़ गहरी साजिश रची जा रही थी.

आपातकाल लागू करने के लगभग दो साल बाद विरोध की लहर तेज़ होती देख, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर चुनाव कराने की सिफारिश कर दी. चुनाव में आपातकाल लागू करने का फ़ैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ. ख़ुद इंदिरा गांधी अपने गढ़ रायबरेली से चुनाव हार गईं. जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने. संसद में कांग्रेस सदस्यों की संख्या 350 से घट कर 153 पर सिमट गई और 30 वर्षों के बाद केंद्र में किसी ग़ैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ. कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली. नई सरकार ने आपातकाल के दौरान लिए गए फ़ैसलों की जांच के लिए शाह आयोग गठित की. हालांकि नई सरकार दो साल ही टिक पाई और अंदरूनी अंतर्विरोधों के कारण 1979 में सरकार गिर गई. उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कुछ मंत्रियों की दोहरी सदस्यता का सवाल उठाया जो जनसंघ के भी सदस्य थे. इसी मुद्दे पर चरण सिंह ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई लेकिन वो सरकार सिर्फ़ पांच महीने ही चली.■

# जल संग्राम

## भूजल स्तर को बढ़ाने का कारगर उपाय है सोक-पिट

चौथी दुनिया ब्यूरो

कम होता भूजल स्तर आज संसद से लेकर सड़क तक एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है. आम लोगों के लिए ये चिंता की बात तो है ही, सरकार की तरफ से भी समय-समय पर इसे लेकर बयान आते रहते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में जल संकट से निबटने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया था. पिछले ही साल भारत जल सप्ताह कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसे लेकर चिंता जाहिर की थी कि भारत में दुनिया की 17 प्रतिशत आबादी निवास करती है, लेकिन जल उपलब्धता मात्र चार प्रतिशत है. भूजल स्तर को बढ़ाने के सरकारी प्रयासों के महेजनर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अलग से 60,000 करोड़ रुपए का फंड बनाने की बात कही थी. हालांकि इस दिशा में सरकारी प्रयास रफ्तार पकड़ते नजर नहीं आ रहे हैं. लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसे कई काम हो रहे हैं, जो भूजल स्तर को बढ़ाने में कारगर साबित हो रहे हैं. ऐसा ही एक उपाय है, सोकपिट.

दिन-ब-दिन सूखते जा रहे तालाबों, नदियों और अन्य जल स्रोतों से सीख लेते हुए देश के कई हिस्सों में सोक पिट्स बनाए जा रहे हैं. स्थानीय भाषा में सोखता के नाम से जाने जाने वाले इन सोक पिट्स को लोग आगे बढ़कर इस्तेमाल में भी ला रहे हैं. इसी तरह के एक अनूठे प्रयास के तहत बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक साथ 2168 सोक पिट बनाए गए हैं. सीतामढ़ी देश के उन जिलों में शामिल है, जहां भूजल स्तर खतरे के निशान से भी नीचे चला गया है. इसे ठीक करने के प्रयासों के तहत जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर सोक पिट निर्माण का लक्ष्य रखा और उसे नियत समय सीमा में पूरा भी कर लिया गया. जिले भर के स्कूलों, स्वास्थ्य केन्द्रों, प्रखंड कार्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों पर जिला प्रशासन ने सोक पिट का निर्माण कराया. साथ ही इसे लेकर लोगों को भी जागरूक किया गया. सोक पिट निर्माण के लिए जिला प्रशासन ने 21 दिनों का जागरूकता अभियान चलाया था. इस अभियान का उद्देश्य ना केवल जल संचय के प्रति लोगों को जागरूक करना बल्कि उन्हें अपने घरों में सोक पिट का निर्माण करने को प्रेरित करना भी था. एक साथ इतने बड़े पैमाने पर सोक पिट का निर्माण कार्य करने के लिए जिला प्रशासन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन भी दिया है.

इसी तरह का एक प्रयास महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी देखने को मिला. कुछ वर्षों पहले नांदेड़ जिले की हिमायत नगर तालुका के एक गांव तेंभूरनी के लोगों ने आस-पास पानी को एकत्र होने से रोकने के लिए घरों के सामने पानी सोखने वाले गड्ढे बनाए. हालांकि लोगों ने ये प्रयास खुले पानी में पनपने वाले मच्छरों से बचने के लिए शुरू किया था. लेकिन जब कुछ जागरूक व जानकार लोगों की इसपर नजर पड़ी तो उन्होंने इसे सोक पिट में बदलने का मुहिम चलाया. जब इस काम में पैसों की कमी आड़े आने लगी, तो सरपंच प्रह्लाद पाटिल ने लोगों को श्रमदान के लिए प्रोत्साहित किया और धीरे-धीरे पूरे गांव में यही तरीका अपनाया गया. इसका फायदा ये हुआ कि जो गांव कुछ साल पहले तक टैंकर के पानी पर निर्भर था, वहां के लोग अब पानी की जरूरतों के लिए भूजल का इस्तेमाल करते हैं. तेंभूरनी से निकले इस आइडिया को नांदेड़ जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिमन्यु काले ने पूरे जिले में लागू करने का निर्णय लिया और सोक पिट निर्माण को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना से जोड़ दिया. इस योजना के तहत आने वाले पैसे से अब यहां सोक पिट का निर्माण भी कराया जा रहा है. इसके कारण यहां भूजल स्तर तो ठीक हुआ ही, इधर-उधर पानी जमा होने के कारण मच्छरों से पैदा होने वाली बिमारियों में भी 75 फीसदी की कमी आ गई है. यहां के स्थानीय निवासी इस गड्ढे को जादुई गड्ढा कहते हैं.

जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में भी सोक पिट का प्रयोग शहरी आबादी को भूगर्भ जल रीचार्ज करने की सीख दे रहा है. जमशेदपुर प्रखंड के करनडीह, सरजामदा, गदड़ा, तालसा, पुड़ीहासा, सुंदरनगर जैसे कई इलाकों में सार्वजनिक नालियां नजर नहीं आती हैं. कारण है, सोक पिट का प्रयोग. गिरता भूजल स्तर सिर्फ महाराष्ट्र के नांदेड़, बिहार के सीतामढ़ी या जमशेदपुर की समस्या नहीं है, बल्कि ये समस्या पूरे देश को अपनी जद में ले रही है. भूजल स्तर 1 से 1.5 प्रतिवर्ष के हिसाब से नीचे गिरता जा रहा है. इसलिए जरूरत है कि समस्या इस समस्या से निजात पाने के लिए प्रयास किया जाय. सोक पिट इसके लिए आसान और कारगर उपाय हो सकता है.■

### ऐसे बनाएं सोक-पिट

सोक पिट के लिए गड्ढे की गहराई उसमें जाने वाली पानी की मात्रा पर निर्भर करती है. सामान्य परिवार के उपयोग के लिए एक सोक पिट की लंबाई, चौड़ाई और गहराई लगभग 3 मीटर रखी जा सकती है. सोक पिट की तली में करीब 0.5 इंच मोटी बोल्डर की परत जमाई जाती है. उस बोल्डर के ऊपर बजरी और फिर उसके ऊपर करीब 0.5 इंच मोटी रेत की परत बिछाई जाती है. इसके बाद पिट को बारीक रेत से भरकर इसके निचले भाग में मिट्टी की पाल डाल दी जाती है. अगर मकान का अहाता बड़ा हो या सदस्यों की संख्या ज्यादा हो, यानि बहने वाले पानी की मात्रा ज्यादा हो, तो एक घर के आसपास करीब तीन-चार सोकपिट बनाए जा सकते हैं.■

## रंगभेद के ख़िलाफ़ मुहिम से जुड़ी प्रियंका

प्रियंका चोपड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर अपनी छवि बना ली है. अब वे विश्वभर से रंगभेद और जातिगत भेदभाव को मिटाने की मुहिम से भी जुड़ गई हैं. एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन के ज़रिए वे लोगों को इन मुद्दों के प्रति न सिर्फ़ संवेदनशील बनाना चाह रही हैं, बल्कि इस ऐड फिल्म से लोगों को एकजुट भी कर रही हैं. निर्देशक एडवर्ड एनिनफुल के निर्देशन में बनी *ब्रिजिंग द गैप्स* नाम की इस ऐड फिल्म का निर्माण एक अमेरिकी परिधान ब्रांड के लिए किया गया है. इस विज्ञापन का मकसद है, सभी धर्मों और वर्णों के लोगों को साथ लाना. इस ऐड फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के साथ क्रिस्टी ब्रिंकले, माइल्स कैमले-वॉटसन, जोनाथन ग्रोफ़, फ्रेनांडा ली, ऐलेन रोजा, जैस्मिन सैंडर्स समेत कई कलाकार मौजूद हैं.



# जब विवादों में फंसी प्रियंका चोपड़ा

**अभी 2017 का आधा साल ठीक से ख़त्म भी नहीं हुआ है कि प्रियंका को कई बार अलग-अलग तरीकों से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा चुका है. गलत बातों को लेकर ट्रोल होने पर प्रियंका चोपड़ा को इन लोगों पर गुस्सा भी आता है. लेकिन प्रियंका उन लोगों में से हैं, जो कभी हार नहीं मानते और मुसीबतों का डटकर सामना करते हैं.**

प्रवीण कुमार

मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा फिल्म अभिनेत्री के साथ-साथ एक अच्छी गायिका भी हैं. वे सबसे ज्यादा फीस लेने वाली बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से एक हैं. बॉलीवुड के साथ-साथ प्रियंका ने हॉलीवुड में भी भारत का नाम रौशन किया है. बॉलीवुड में प्रियंका ने अपने अभिनय से कई अवॉर्ड अपने नाम किया है. दुनियाभर में उनके करोड़ों फैन हैं. अब हॉलीवुड में काम करने के बाद उनके विदेशी फैन्स की संख्या काफी बढ़ चुकी है. प्रियंका चोपड़ा भारत के साथ-साथ विदेशों में भी चर्चित सेलिब्रिटीज में से एक हैं. अमेरिका में प्रियंका चोपड़ा के टीवी शो *क्वांटिको* को अपार सफलता मिली है. उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म *बेवॉच भी* रिलीज हो चुकी है. हालांकि विदेशी और बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर बेवॉच कोई ख़ास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन इससे प्रियंका के स्टारडम में कोई कमी नहीं आई. ये भी सुनने में आया है कि प्रियंका को हॉलीवुड की एक और फिल्म ऑफर हुई है, जिसका नाम *ए किड लाइक जेक* है. हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा. फिलहाल तो प्रियंका चोपड़ा कुछ दिनों की छुट्टी पर भारत आई हुई हैं. भारत आते ही प्रियंका ने एक बड़ा धमाका कर दिया है. इस देसी गर्ल ने भारत आते ही अपने फैन्स को खुश करते हुए एक बायोपिक फिल्म साइन कर ली हैं. जी हां, ये कन्फर्म हो गया हैं कि, प्रियंका चोपड़ा जल्द ही भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की बायोपिक में नज़र आने वाली हैं. पिछले एक साल से इस फिल्म के मेकर्स प्रियंका और उनकी टीम से बात कर रहे थे. लेकिन अब जाकर प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म करने के लिए हामी भरी है. डायरेक्टर प्रिया मिश्रा ने कंफर्म किया है कि प्रियंका जल्द ही कल्पना चावला की बायोपिक में दिखाई देंगी.

आपको बात दें कि कल्पना ने पहली बार मिशन विशेषज्ञ और प्राथमिक रोबॉटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में 1997 में कोलंबिया अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी. लेकिन 2003 में कल्पना चावला छह अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ एक अंतरिक्ष यान हादसे का शिकार हो गई थीं.

एक तरफ जहां प्रियंका के करोड़ों फैंस हैं, जो उनकी दीवानगी के कायल हैं, वहीं दूसरी ओर कई ऐसे लोग भी हैं, जो प्रियंका को सोशल मीडिया के जरिए ट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते. अभी 2017 का आधा साल ठीक से ख़त्म भी नहीं हुआ है कि प्रियंका को कई बार अलग अलग तरीकों से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा चुका है. गलत बातों को लेकर ट्रोल होने पर प्रियंका चोपड़ा को इन लोगों पर गुस्सा भी आता है. लेकिन प्रियंका उन लोगों में से हैं, जो कभी हार नहीं मानते और मुसीबतों का डटकर सामना करते हैं. ट्रोल होने पर प्रियंका ने भी ऐसा ही किया और जो लोग उनको अपने निशाने पर लेकर उन्हें ट्रोल कर रहे थे, उन्हें कड़ा जवाब देते हुए बता दिया कि ये उनकी जिंदगी है और उन्हें अपनी जिंदगी में क्या-क्या करना ये कोई और तय नहीं कर सकता.

आइए जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में प्रियंका किन-किन वजहों से सोशल मीडिया पर ट्रोल हुईं.■

feedback@chauthiduniya.com

## 1 नाक की सर्जरी के लिए ट्रोल हुईं प्रियंका

हाल ही में प्रियंका ने मुंबई में लैंड करने से पहले की अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की थी. इस दौरान तस्वीर में प्रियंका की नाक को लेकर सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया गया. ट्रोल्स (सोशल मीडिया पर खिचाई करने वाले लोग) का कहना है कि प्रियंका ने अपनी नाक की सर्जरी करवाई है. दरसअल, देसी गर्ल ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिस पर फैन्स ने अच्छे कमेंट किए, लेकिन कुछ शरारती फैन्स ने उनकी इस तस्वीर को ट्रोल करना शुरू कर दिया. प्रियंका ने अपनी जो सेल्फी पोस्ट की है, वो बहुत करीब से ली गई थी, इसमें उनकी नाक कुछ अजीब सी लग रही है. इसे देखकर फैन्स को लगा कि उन्होंने नाक की सर्जरी कराई है. बस फिर क्या था, कुछ लोगों ने कमेंट कर उनसे पूछ लिया कि क्या उन्होंने फिर से अपनी नाक की सर्जरी करवाई है. एक फॉलोअर ने तो उन्हें ट्रोल करते हुए लिखा कि आपकी नाक अब बहुत भद्दी दिख रही है. खैर प्रियंका ने सर्जरी करवाई है या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन उनकी इस तस्वीर को लाखों लाइक्स मिल चुके हैं.■

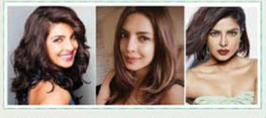

## 2 पीएम मोदी से मुलाक़ात

बर्लिन में जब प्रियंका चोपड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो उन्हें नहीं पता था कि पीएम मोदी से हुई उनकी मुलाकात उनकी ड्रेस को चर्चित हो जाएगी और सोशल मीडिया पर उनकी ड्रेस को लेकर बड़ा बवाल हो जाएगा. जी हां, प्रियंका ने जब पीएम मोदी से बर्लिन में मुलाकात की, तो उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए फेसबुक और ट्वीटर पर तस्वीरें पोस्ट कीं और साथ ही लिखा, *नरेंद्र मोदी सर शुक्रिया, वक्त निकालकर मुझसे मिलने के लिए. कितना अच्छा संयोग है कि हम बर्लिन में एक साथ मौजूद हैं.*

सोशल मीडिया इन दो हस्तियों की मुलाकात का जश्न मना रही थी और कहा जा रहा था कि भारत का नाम रौशन करने वाले दो बड़े नाम एक साथ एक फ्रेम में कितने अच्छे लग रहे हैं. लेकिन तभी, कुछ यूज़र्स ने प्रियंका के कपड़ों और उनके बैठने के तरीके पर आपत्ति जतानी शुरू कर दी. ये मुद्दा आगे चलकर बड़े ट्रोल में बदल गया. कई यूजर्स ने प्रियंका को नसीहत दे डाली कि कम से कम प्रधानमंत्री के सामने तो ठीक से कपड़े पहनकर जातीं. ये हमारी संस्कृति के ख़िलाफ़ है.

जब सोशल मीडिया पर ये बात काफी बढ़ गई, तो प्रियंका ने यूजर्स को कड़ा जवाब देते हुए लिखा कि ये उनकी मर्जी है कि वे क्या पहनें और किसी के सामने कैसे बैठें. ये उनकी जिंदगी है, जिसमें किसी को कोई दखल देने की जरूरत नहीं है. इसके दूसरे दिन प्रियंका ने अपनी मॉम के साथ एक शॉर्ट ड्रेस में बैठी हुई तस्वीर भी शेयर की, ताकि यूजर्स की अकल ठिकाने आ सके. इस पर सनी लियोनी सहित कई हस्तियों ने प्रियंका चोपड़ा का समर्थन किया. वहीं, इस मामले में अमिताभ बच्चन सहित कई सेलिब्रिटी टिप्पणी करने से बचते नज़र आए. अमिताभ ने इस मामले पर टिप्पणी करने से ये कहते हुए इंकार कर दिया था कि *न तो वे प्रधानमंत्री हैं और न ही प्रियंका चोपड़ा.*■

## 3 मेट गाला 2017 रेड कार्पेट

वैसे तो प्रियंका चोपड़ा अपनी ख़ूबसूरती और अच्छे ड्रेस सेंस के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार मेट गाला 2017 रेड कार्पेट में प्रियंका अपनी ड्रेस को लेकर चर्चा में रहीं. प्रियंका चोपड़ा न्यूयॉर्क में हुए मेट गाला 2017 के रेड कार्पेट पर जलवे बिखेरते हुए नज़र आईं. दरअसल, प्रियंका के गाउन का कपड़ा इतना ज्यादा बड़ा था कि पूरे इवेंट में कुछ असिस्टेंट इसे संभालते नज़र आए. प्रियंका के इस इंटरनेशनल लुक को काफी लोगों ने पसंद भी किया. लेकिन कुछ लोगों को ये ड्रेस काफी अजीब लगी. बस फिर क्या था, प्रियंका की इतनी बड़ी ड्रेस को लेकर ट्वीटर पर एक यूजर ने ट्रोल करना शुरू कर दिया.

एक यूजर ने लिखा कि इन दिनों प्रियंका ज्यादा ऊंचा उड़ रही हैं और सुरक्षा के लिए वे अपना पैराशूट साथ लेकर आई हैं. तो वहीं एक दूसरे ने प्रियंका चोपड़ा की इस ड्रेस की तुलना झाड़ू से कर दी.■

## 4 बिकिनी विवाद

प्रियंका चोपड़ा जब अपनी हॉलीवुड फिल्म बेवॉच के प्रमोशन में व्यस्त थीं, उसी दौरान वे कुछ समय निकालकर मियामी में रिलैक्स करने गईं थीं. जहां उन्होंने बीच पर एन्जॉय करते हुए बिकनी पोज दिए, जो काफी वायरल हुआ. प्रियंका ने ये तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की, जिसमें वे डार्क ब्लू बिकिनी में नज़र आ रही थीं. उनके कई फैंस ने उनके इस हॉट अवतार की तारीफ भी की, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ यूजर्स प्रियंका की इन तस्वीरों को ट्रोल करके उनको नसीहत देने लगे.■